(iv) Thirty-second Report on the subject 'Voluntary Organisations Engaged in Implementing Integrated Programme for Welfare of Older Persons' pertaining to the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2007-2008.

REPORT OF DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT

श्री कृष्ण लाल वाल्मीकि (राजस्थान) : महोदय, मैं 2007-2008 के वर्ष के लिए शहरी विकास मंत्रालय की "मुद्रण निदेशालय" से संबंधित समिति के बाइसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विभाग संबंधित शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेज़ी और हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, further discussion on Motion of Thanks on President's Address.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—(Contd.)

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। उपसभापति जी, मैं देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए प्रथम अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री जनार्दन द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता दर्शाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव का, अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपसभापति जी, यह भारतीय जनता के लिए गौरव और सम्मान की बात है कि आज देश के सर्वोच्च पद पर नारी शक्ति की प्रतीक, एक सम्मानित महिला विराजमान हैं। मैं उनके प्रति अपने दल की ओर से हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

उपसभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने सारगर्भित अभिभाषण के 58 पैराग्राफ में सरकार की नीतियों का, सरकार के कार्यक्रमों का और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। मैं उनमें से देश की आम जनता से जुड़ी कुछ बुनियादी समस्याओं - रोज़ी-रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर अपने विचार रखना चाहूंगा। यह खेद की बात है कि आज़ादी के 60 सालों के बाद भी इन सवालों को हम हल नहीं कर पाए हैं, आज भी ये सवाल हमारे सामने सिर उठाकर खड़े हैं।

उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने देश की आर्थिक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने आर्थिक विकास की इस प्रक्रिया को सामाजिक रूप से समावेशी और क्षेत्रीय रूप से संतुलित होने की बात कही है। उनके भाषण में सरकार द्वारा समावेशी विकास, Inter-Conclusive Growth का आवश्यक ढांचा तैयार करने की बात कही गई है। अभिभाषण के पैराग्राफ 2 में ही उन्होंने सरकार के अनेक कार्यक्रमों की चर्चा की है — भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास और सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संसद का ध्यान आकृष्ट किया है। महोदय, देश के ग्रामीण क्षेत्र, जहां तकरीबन तीन-चौथाई आबादी रहती है, उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाली सरकारी नीतियों का भी उन्होंने उल्लेख किया है।

माननीय राष्ट्रपति जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 4 वर्षों में 9 प्रतिशत की दर से विकास होने की बात कही है। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होना और विकास की दर बढ़ना, ये देश की प्रगति के अच्छे लक्षण हैं, परन्तु हमें यह देखना होगा कि विकास की इस दर का लाभ कहां जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है या कुछ सीमित लोगों तक या कुछ सीमित क्षेत्रों में इसका लाभ जा रहा है? क्या इसका लाभ ग्रामीण भारत तक पहुंच रहा है,

जहां देश की दो-तिहाई आबादी रहती है? क्या गांवों में खुशहाली आई है? क्या उनको काम मिल रहा है, उनके पेट भरे हैं, तन ढकने के लिए उनके बदन पर कपड़े हैं, उनके सिर पर कोई छत है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्वास्थ्य केन्द्र पर इनका इलाज हो रहा है, पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है, क्या उनके घर में शौचालय हैं या आज भी महिलाओं को सड़क किनारे शौच के लिए जाना पड़ता है? मान्यवर, आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों से रोजी-रोटी की तलाश में बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि गांव में उन्हें काम नहीं मिल रहा है और मजबूरी में उन्हें पलायन करके शहरों में जाना पड़ता है।

मान्यवर, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार के एक व्यक्ति को वर्ष में सौ दिन काम देने की गारंटी दी है। महोदय, मैं सरकार को इस अधिनियम के लिए बधाई देता हूँ। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ। महोदय, साल में 365 दिन होते हैं, एक परिवार में कम से कम पांच सदस्य जरूर होते हैं, क्या यह सौ दिन का रोजगार देने से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? मैं यह जवाब जानना चाहता हूँ। सरकार ने अप्रैल, 2008 से देश के सभी ग्रामीण जिलों तक इसे लागू करने का निर्णय लिया है।

महोदय, इस योजना के कार्यान्वयन पर संसद में लगातार सवाल होते रहते हैं। इस योजना का, इस महत्वपूर्ण योजना का कार्यान्वयन कैसे हो रहा है, इसका जो उद्देश्य था, इसका जो लक्ष्य था, क्या उसकी पूर्ति हो रही है, क्या राज्य सरकारें इस योजना को सही ढंग से लागू कर रही हैं? ये सवाल हैं जो लगातार संसद में उठते रहते हैं। महोदय, कई राज्यों से शिकायतें आ रही हैं कि वे कार्यक्रम को सही रूप में लागू नहीं कर रही हैं। कई तरह की अनियमितताएं हो रही हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन हो भी जाए तो जॉब कार्ड नहीं मिलते और अगर जॉब कार्ड मिल भी जाता है तो जॉब नहीं मिलता। इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ का जहां तक सवाल उठता है, वह ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंचता है। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए जो सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है, उस सुविधा का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत लोग उस सुविधा का उपभोग कर रहे हैं।

महोदय, एक अच्छे कार्यक्रम का लाभ अगर गरीब मजदूरों तक पहुंचाना है तो इसके दुरुपयोग को रोकना होगा, इसमें पारदर्शिता लानी होगी। जिस प्रकार कई राज्यों में इसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में सैंटर से भी एक मोनिटरिंग व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। वैसे राज्य सरकारों की यह जवाबदेही होती है कि उसको सही ढंग से लागू करे। बिहार में भी ऐसे सवाल उठे हैं, बिहार में भी इस योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। मैं बिहार के मुख्य मंत्री जी को आपके द्वारा अनुरोध करना चाहूंगा कि इस योजना को, जो गरीबों की योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की योजना है, सही ढंग से लागू करे।

महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, वह किसानों से संबंधित है। किसान इस देश के अन्न दाता है। किसान कड़ी धूप में, बरसात में, जाड़े में अपना खून-पसीना बहा करके खेतों में काम करते हैं और देश का पेट भरते है। इस देश में ग्रीन रिज्योलेशन हुआ, हरित क्रांति आई और हरित क्रांति ने अनाज के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाया।

महोदय, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधान मंत्री ने नारा दिया था - "जय जवान, जय किसान"। "जय जवान जय किसान" का नारा इसलिए उन्होंने दिया था कि जहां जवान सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, वहां किसान खेतों में उत्पादन करके देश की रक्षा करते हैं।

महोदय, इस अभिभाषण में किसान से संबंधित भी कई बातें कही गई हैं। महोदय, पैराग्राफ 8 में कृषि ऋण की चर्चा हुई है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कृषि ऋण को तीन वर्षों में दोगुना करने के तय लक्ष्य को काफी पीछे छोड़ा जा चुका है। तीन वर्षों में जो लक्ष्य था कृषि ऋण को दोगुना करने का, सरकार का इस अभिभाषण के द्वारा कहना है कि उसको काफी पीछे छोड़ा जा चुका है। क्या यह कृषि ऋण देश के अधिकांश लोगों तक बैंकों के माध्यम से पहुंच रहा है? महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार अभी भी अधिकांश किसानों

को सेठ-साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। बगल में बैठे हुए येचुरी साहब को आंकड़े याद रहते हैं, जहां तक मुझे याद है कि 36 परसेंट किसानों को ही बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध होता है। महोदय, किसानों पर जो कर्ज़ा था, सरकार ने 60 हज़ार करोड़ का कर्ज़ा माफ किया है। यह बहुत अच्छी बात है। इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा था, अभी भी वह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। हज़ारों किसानों ने आत्महत्या की है, वे कर्ज़ में डूबे, उनकी फसल बरबाद हुई, वे ऋण नहीं चुका पाए और उन्होंने आत्महत्या की। किसानों को 60 हज़ार करोड़ की कर्ज़ माफी से सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं, जिन किसानों ने सेठ-साहूकारों से कर्ज़ लिया है, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है? वे अपना कर्ज़ा कैसे अदा करेंगे, यह प्रश्न मैं सरकार के समक्ष रखता हूं।

महोदय, सिर्फ चालीस प्रतिशत ऐसे कृषि क्षेत्र हैं, जहां सिंचाई उपलब्ध है। मैं बिहार से आता हूं। जब भी बरसात का मौसम आता है, तो बिहार की चर्चा यहां होती है। इसलिए होती है कि बिहार में भयंकर बाढ़ आती है। बाढ़ नेपाल की नदियों से आती है। जब बाढ़ आती है, तो खेत-खलिहान, घर--बार, जान--माल का भारी नुकसान होता है। हज़ारों करोड़ रुपयों का नुकसान हर वर्ष होता है। नेपाल से बात कर रहे हैं, बरसों से बात कर रहे हैं। इस सरकार ही नहीं, पहले की सरकारों ने भी बात की है, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। नेपाल में डैम बनाने की बात हो रही है। बिहार के लगभग बीस-बाईस जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों का जो नुकसान होता है, सरकार को नुकसान भरपाई करनी चाहिये। किसानों के लिए फसल बीमा की व्यवस्था करनी होगी। उनका नुकसान होता है, तो उनके लिए बीमा का प्रबंध करें। महोदय, बाढ़ प्रबंधन की जो स्थिति है, वह भी हम ठीक से नहीं कर पाए हैं। हज़ारों किलोमीटर में बांध बनाए हुए हैं बिहार में, वे बांध कमज़ोर हो गए हैं, यह स्थिति है कि कंट्रीसाइड नीचा हो गया है और रिवरसाइड ऊंचा हो गया है। थोड़ा सा भी पानी अगर आता है, तो बाढ़ आ जाती है और सब कुछ बहा कर ले जाती है।

महोदय, मैं सिंचाई के बारे में, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। किसान को जब तक पानी नहीं मिलेगा, किसान को अच्छा बीज नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि जब तक किसान को अपने प्रोडक्ट की अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी, उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक किसान की यही स्थिति जारी रहेगी। डिस्ट्रेस सेल होती है, किसान डिस्ट्रेस सेल करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देती हैं - वैसे इस सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन वह भी बहुत कम है। हम बाहर के देशों से ज्यादा पैसा देकर अनाज मंगा सकते हैं तो हम अपने किसानों को ज्यादा पैसा क्यों नहीं दे सकते? क्यों हमारे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है? महोदय, किसानों की ऋण माफी के लिए सरकार ने जो प्रयास किया है, फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से जो कुछ बजट में कहा गया है, वह स्वागत योग्य है, सराहनीय है, लेकिन सिर्फ इतने से ही किसान सुखी नहीं होगा, उसके लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। महोदय, मैं स्वयं-सहायता समूह के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जो पैराग्राफ - 9 में है। उसमें कहा गया है कि "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पांच लाख से अधिक स्वयं-सहायता समूहों की मदद की जा रही है, स्वरोजगारियों में 52 प्रतिशत महिलाएं हैं।" महोदय, सरकार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास किया है। महिलाएं इस देश की बहुत बड़ी ताकत हैं, हम उन्हें नारी शक्ति, स्त्री शक्ति, झांसी की रानी तथा अन्य कई महत्वपूर्ण सम्मानित शब्दों से प्रशंसा करते हैं। हमारा समाज अभी भी पुरुष प्रधान है। समाज में जो बराबरी या समानता की बात होनी चाहिए, वह नहीं है। दहेज के लिए हत्याएं हो रही हैं, अभी भी उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, दूसरी तरह के अनेकों अपराध हो रहे हैं। अभी भी वे स्वावलम्बी नहीं हैं, उन्हें अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है। इस दिशा में जो स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसके माध्यम से महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है।

महोदय, अब मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। महोदय, राष्ट्रपति जी ने पैराग्राफ - 13 के द्वारा शिक्षा में पहुंच को बढ़ाकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण पर अत्यधिक जोर दिया है।

छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जातियों के लगभग 30 लाख बच्चों को लगभग 900 करोड़ रुपए की राशि तथा 10 लाख से अधिक जनजातीय बच्चों को 225 करोड़ से अधिक की राशि बजट में दी गयी है। राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की विशेष कोचिंग संबंधी स्कीमों को सक्रियता से क्रियान्वित किया जा रहा है। महोदय, संविधान में अनुसूचित जाति को 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ वर्ग के लोगों को आरक्षण कानून का जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। नौकरियों में आरक्षण मिला है, लेकिन तीसरी और चौथी श्रेणी की जो नौकरियां हैं, केवल उनमें आरक्षण को पूरा करने का प्रयास किया गया है, पहली और द्वितीय श्रेणी की जो नौकरियां हैं - खासकर पहली श्रेणी की जो नौकरियां हैं, उनमें अभी भी वैकेंसी होती है, बैक–लॉग है, कहते हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है इसलिए हम उसे भर नहीं पाते हैं। महोदय, मैं रेल बजट पर तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं रेल मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने रेल विभाग में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो वैकेंसीज़ थी, 99 प्रतिशत वैकेंसीज़ को उन्होंने भर दिया है।

महोदय, मैं पैराग्राफ-15 के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। महोदय, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित सैक्टर सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 प्रस्तुत किया गया है। महोदय, जितने भी मजदूर हैं उनमें 90 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। हम संसद के अंदर उनकी लड़ाई लड़ते हैं और संसद के बाहर भी उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उनके लिए कोई ऐसा विधेयक नहीं था जिसके माध्यम से वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। इस दिशा में असंगठित सैक्टर सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद एक मजबूत कवच उनको मिलेगा और उस कवच के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। महोदय, और भी उनके लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यक्रम है, आम आदमी बीमा योजना कार्यक्रम है, गरीबी रेखा के नीचे तथा 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को 200 रुपए प्रति माह पेंशन देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम प्रारंभ की गई है। महोदय, राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी को भी 66 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है, श्रमिकों को बोनस की अदायगी की पात्रता सीमा को 3500 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। भवन-निर्माण ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों को भी बोनस के भुगतान के लिए पात्र बनाया गया है। महोदय, दिल्ली में तथा बड़े-बड़े शहरों में हजारों लोग, बल्कि लाखों की संख्या में भवन निर्माण से जुड़े हुए मजदूर हैं। महोदय, भवन निर्माण से जुड़े हुए जो मजदूर होते हैं, उनकी रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है। उन्हें जो मजदूरी मिलती हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं होती है और न कोई सीमा होती है। अगर किसी कारण से भवन निर्माण के क्रम में कोई दुर्घटना हो जाती है तो संबंधित ठेकेदार, उस मजदूर की तत्काल कुछ सहायता तो कर देता है, मगर उसके बाद उसकी कोई सहायता नहीं करता। बिहार के काफी लोग इस काम में लगे हुए हैं। ऐसे मजदूरों के लिए, जिनको हम असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहते हैं, मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से उनको अधिकार मिलेगा और वे अपने अधिकार की रक्षा करेंगे।

महोदय, मैं पैराग्राफ-16 के माध्यम से भूमि से विस्थापित लोगों की चिरकालिक समस्याओं का समाधान, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति के लागू करने के बारे में कहना चाहूंगा। महोदय, सेज की बहुत चर्चा है। सेज के लिए हम किसानों से हजारों एकड़ जमीन ले रहे हैं। किसान देना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास जमीन के अलावा कुछ है नहीं। उससे जबर्दस्ती जमीन छीन ली जाती है। वैसे भी जो खेती का एरिया है, वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। किसान के पास जमीन के अलावा आमदनी का अन्य कोई स्रोत नहीं होता है। उसकी जमीन ले लेते हैं, सही मुआवजा नहीं देते, जमीन के बदले में काम नहीं देते। जो कंपसेशन देते हैं, वह बहुत कम होता है और कम्पंसेसन बढ़ाने के मामले को अगर वह कोर्ट में ले जाता है तो उसी में उसका पैसा खर्च हो जाता है उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। महोदय, बहुत पुराना कानून था, उसमें सुधार की आवश्यकता थी। सरकार द्वारा यह पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2007 और भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 संसद में पेश किया जा चुका है। यह स्टेंडिंग कमेटी में है। महोदय, इस

विधेयक को शीघ्र पारित करना चाहिए, क्योंकि किसानों की रक्षा के लिए, किसानों को सही मुआवज़ा मिले तथा इसके लिए यह आवश्यक है। भूमि अर्जन के संबंध में जो पुराना विधेयक है वह आज के समय में किसानों के लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए इस विधेयक को शीघ्र पारित करना चाहिए। महोदय, इसलिए इस विधेयक को शीघ्र पारित करना चाहिए..।

श्री उपसभापति : भंडारी जी, आपकी पार्टी का समय..।

प्रो. राम देव भंडारी : महोदय, मैं इस साल रिटायर हो रहा हूं।

श्री उपसभापति : मुझे उसकी जानकारी है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं। मुश्किल यह है कि कल तीन बजे रिप्लाई है और अभी तीस, पैंतीस सदस्य बोलने वाले हैं। आप जल्दी से समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

प्रो. राम देव भंडारी : सर, मैं इसकी कोशिश करता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): सर, उनको थोड़ा और बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति : आप तो रिकमंड कर रहे हैं, मगर मेरे पास समय नहीं है।

प्रो. राम देव भंडारी : महोदय, मैं इसको शीघ्र समाप्त करने की कोशिश करता हूं। महोदय, पैराग्राफ 17 में पंचायती राज के संबंध में राष्ट्रपति महोदया ने चर्चा की है। महोदय, जनता के हाथ में अधिकार हो, जनता अपनी समस्याओं का फैसला स्वयं करे, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था बनायी गयी है। सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम बनाये जाते हैं, उन कार्यक्रमों को पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लागू किया जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं, मगर यह ठीक से लागू नहीं हो रहा है। एक तो उनके पास उतनी शक्ति नहीं है, जो शक्ति है, वे प्रखंड विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर,एसडीओ होतें हैं, उन्होंने इसकी शक्ति अपने पास हथिया ली है। ये मुखिया या प्रधान है, उसको अपने आसपास घुमाते रहते हैं। जब भी उनका मन होता है, वे पेपर्स पर उनके दस्तखत करवा लेते हैं। ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उस लक्ष्य को पूरा करना होगा। हम सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करना चाहते हैं, और विकेन्द्रीयकरण करके जब तक हम पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करेंगे, उनके माध्यम से हम जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक इस व्यवस्था का जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

महोदय, मैं पैराग्राफ 20 के बारे में चर्चा कर रहा हूं, इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में कहा गया है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि समाज में महिलाओं का बराबर योगदान है। महिलाओं के लिए समानता की पूर्ण कानूनी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

महोदय, यूपीए सरकार ने देश को एक महिला राष्ट्रपति दी है। अभी भी देश में महिलाओं के प्रति भेदभाव है और उसे समाप्त करने की आवश्यकता है। भ्रूण हत्या होती है, एक मशीन चली है, जिससे गर्भ की स्थिति में ही लिंग का पता चल जाता है कि यह कन्या है या बालक है। जब यह पता लग जाता है कि गर्भ में कन्या है, तो उसकी वहीं भ्रूण हत्या होती है। आज पुरुष और महिला का अनुपात है, वह चौड़ा होता जा रहा है।...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): महिला आरक्षण विधेयक के बारे में भी बोलिए। **(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not an issue...*(Interruptions)*. आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। आप अपनी बात कहिए। ...**(व्यवधान)**...

प्रो0 राम देव भंडारी : महोदय, मैं अपनी बात और इनकी बात, दोनों बात कहूंगा। मेरी पार्टी महिला आरक्षण के लिए इनसे ज्यादा समर्पित है। मगर मेरी एक बात है। इस देश में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनका अभी भी समाज की मुख्यधारा में बहुत कम प्रतिनिधित्व है। महिला आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दीजिए, इस पर हमें ऐतराज नहीं है, मगर उसमें अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान कर दीजिए, इस आरक्षण के लिए हमारी पार्टी समर्पित है, मजबूती से समर्पित है। महोदय, मैं उस आरक्षण की बात भी करना चाहता हूं, जो उच्च शिक्षा में आरक्षण देने की है। सरकार ने हायर एजुकेशन में आरक्षण देने का बिल पारित किया है। इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, सरकार अगर कोई क्रांतिकारी कदम उठाती है, तो उसको रोकने के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं। हमें अपनी जुडिशरी में पूरा विश्वास है। हम यह भी जानते हैं कि हमारी जुडिशरी जो भी काम करेगी, ठीक ही करेगी। मगर कभी–कभी सरकार का जो प्रगतिशील कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ लोग कोई न कोई पेंच फंसा कर कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट में उसे लटका कर रखते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा ....**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : समाप्त कीजिए।

प्रो. राम देव भंडारी : Just a minute, Sir. मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन में जो आरक्षण का प्रावधान किया है, जैसे भी हो इसको शीघ्र लागू किया जाए। महोदय, मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जुडिशरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की चर्चा बरसों से हो रही है। मैंने पहले ही कहा है कि हमारी जुडिशरी में पूरा विश्वास है। इस देश का सही प्रतिनिधित्व, सही चेहरा जुडिशरी में भी दिखाई पड़े, इसके लिए जुडिशरी में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। वहां भी शैड्यूल्ड कॉस्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेज़ और मॉइनोरिटीज के लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए। महोदय, जिस समय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने लोअर लेवल पर जुडिशरी में आरक्षण का प्रावधान किया था, मगर वह भी कोर्ट के पेंच में फंसा दिया गया। मेरा यह कहना है कि जुडिशरी में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। महोदय, मैं सच्चर समिति की रिपोर्ट के बारे भी कहना चाहूंगा कि मॉइनोरिटीज के बारे में ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप समाप्त कीजिए क्योंकि जो आपकी पार्टी का समय था, आप उससे ज्यादा बोल चुके हैं।

प्रो. राम देव भंडारी : महोदय, मैंने पहले ही अनुरोध किया था कि मेरा टर्म खत्म हो रहा है। **(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आपके वापस आने के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं।...**(व्यवधान)**... मैं यह बात नहीं कर रहा हूं। आपकी पार्टी के जो 22 मिनट्स थे, ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम देव भंडारी : महोदय, अहलुवालिया जी कह रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूं। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी पर निर्भर है। **(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : हमारी शुभकामनाएं हैं, बस। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखंड): पूरे हाऊस ने रेकमेंड करके ...**(व्यवधान)**... कर दिया है।...**(व्यवधान)** हम लोगों ने यह सर्वसम्मति से कर दिया है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : अभी मौके मिलेंगे, अभी मौके मिलेंगे...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिम बंगाल) : और वापस लाने के बाद, उनकी स्पीच पर आप पाबंदी न लगाएं। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम देव भंडारी : सर, मैं अपनी पार्टी का प्रधान महासचिव भी हूं और यहां नेता भी हूं। मैंने बहुत ईमानदारी और निष्ठा से नेता और पार्टी की सेवा की है। अब नेता पर निर्भर करता है कि वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। **(व्यवधान)**...मुझे और दस-पन्द्रह मिनट बोलना था। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : समाप्त कीजिए। ...**(व्यवधान)**...आपको बजट और रेलवे बजट पर तो बोलना ही है।

प्रो. राम देव भंडारी : महोदय, सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान,

मध्याह्न भोजन, मॉडल स्कूल, नए केन्द्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण स्वच्छता, निर्मल ग्राम पुरस्कार आदि की चर्चा की है। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, भारतीय रेल के बारे में चर्चा की है। जब रेल बजट पर बहस होगी, उस समय जो भी हमारे साथी होंगे, वे बोलेंगे। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी ने इस देश की बुजुर्ग महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तक टिकट माफ किया है। ग्रेजुएशन स्तर तक की जो लड़कियां हैं, उनके मासिक सीजन टिकट को माफ किया है। और भी बड़े-बड़े काम किए हैं। सभी ने उनकी सराहना की है और आगे भी हम उनकी सराहना करेंगे। महोदय, मैं भारत-नेपाल के बारे में भी दो शब्द कहना चाहूंगा । नेपाल में लगभग 48 प्रतिशत भारतीय मूल के लोग रहते हैं। जिनको हम मधेशी कहते हैं। नेपाल में इस समय लोकतंत्र की स्थापना हुई है, यह स्वागत योग्य है। मगर हमारे जो नागरिक वहां रहते हैं, उनमें से बड़ी संख्या ऐसे भी हैं जिन्हें अभी नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है। सरकार को इस दिशा में प्रयास करनी चाहिए। नेपाल सरकार से बात करके, जो भारतीय मूल के नागरिक वहां हैं, उनकी रक्षा और उनके अधिकार उन्हें मिलते रहें, मैं यह सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं।

महोदय, समानता के आधार पर देश का निर्माण होता है। जिस देश में अमीरी और गरीबी का इतना बड़ा फर्क होगा, उस देश में समानता नहीं होगी। समानता के आधार पर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूपीए गवर्नमेंट इस देश की जनता के हित के लिए कौमीटेड है। देश की जनता की प्रगति और विकास के लिए कई काम यूपीए सरकार ने इन चार वर्षों में किया है और आगे आने वाले समय में भी यह यूपीए सरकार इस देश की जनता के लिए सभी कुछ करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, साथ ही आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं भंडारी जी का बहुत आदर करती हूं। ये बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छे हैं और इम्पार्शियल हैं।

प्रो. राम देव भंडारी : मैं भी आपका बहुत आदर करता हूं।

श्रीमती जया बच्चन : वे अपने भाषण में नेपाल के बारे में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग वहां बहुत हैं, मगर उन्होंने महामहिम की स्पीच में महाराष्ट्र में मध्य भारतीय लोगों के साथ जो हुआ है, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। आप तो बिहार के हैं, महाराष्ट्र में बिहार के जो लोग हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया है। एटलीस्ट आप इस पर कमेंट कर दीजिए।

श्री उपसभापति : उन्होंने नोटिस दिया है।

प्रो. राम देव भंडारी : महोदया, ऐसा है कि मैंने इस सवाल को सुबह ही चेयरमेन साहब के समक्ष करना था।

श्रीमती जया बच्चन : इन्होंने नोटिस दिया है, मगर इतना बड़ा काण्ड हो गया और इन्होंने अपनी स्पीच में कुछ नहीं कहा। बिहार के लोग वहां से ज्यादा भगाए गए हैं, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

प्रो. राम देव भंडारी : मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा कराएंगे और बोलने का मौका देंगे।

श्री उपसभापति : इस पर कल चर्चा होगी, कल रिप्लाई के बाद होगा।

प्रो. राम देव भंडारी : मैं इसे जीरो ऑवर के बाद ही उठाने वाला था, उन्होंने कहा कि कल इस पर चर्चा होगी, अभी बात कहेंगे।

श्री उपसभापति : श्री आर.के. धवन।

श्री राजनीति प्रसाद : हमें मौका मिलेगा तो हम बोलेंगे।

श्री उपसभापति : मौका पार्टी के समय के अनुसार होता है।

श्रीमती जया बच्चन : प्रेसिडेंट की स्पीच में इसका मेंशन नहीं है, मैं यह कहना चाहती हूं।

SHRI R.K. DHAWAN (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, with your permission, I rise to support the Motion of Thanks to the hon. President's Address. Sir, at the outset, I would like to thank the hon. President for her illuminating address to Parliament. Sir, as this august House knows, the President's Address is a statement made on behalf of the Government; the Address represents, generally, the programmes and policies of the Government. It is not a catalogue of what all the Government has done. It is a concise statement in the restrained language which gives the details, because it is not possible to give all the details that the Government wishes to give, if I may say so. My colleague Janardhan Dwivediji has made a very lucid analysis of the programmes and policies of the Government and Shri Singhviji has quoted various figures. I would not like to take the time of the hon. House in repeating all that. However, I would like to say a few words on some subjects, primarily on agriculture.

Sir, the Congress Party fought the 2004 elections on the philosophy that the objective of any Government is not the glory of the rulers but the happiness of the common man. I have no hesitation in saying, much to the discomfort of my friends in the Opposition, that this has been the major factor for the Government in framing policies and programmes, to be responsible and transparent on all counts, and the Government has achieved many strides.

Last year, while speaking on the same Motion, I emphasised the importance of having a second Green Revolution. Sir, it is a matter of great exhilaration for me that the Government during the last one year has made tremendous progress towards attainment of this indispensable national objective. Sir, it is heartening to note from the Address that the National Food Security Mission has been set up to enhance the production of rice, wheat and pulses by 10, 8 and 2 million tonnes during the Eleventh Plan period. Sir, another praiseworthy action taken by the Government is Rashtriya Krishi Vikas Yojana with an outlay of Rs.25,000 crores for farmers revival by setting up agriculture growth of 4 per cent in the Eleventh Plan by providing incentives to States. Sir, for understanding the need of Second Green Revolution to which our Bhandaryji also referred, one has to go back into the history of development of agriculture since Independence. Sir, when this country became independent, Shri Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, had the vision and foresight that India had to catch up with the rest of the world in the field of industrial development and without industrialisation economic growth will not be able to match the world. With that in mind, he set up public sector undertakings to have industrial infrastructure and took initiative for the private sector to grow. Sir, but for historical experiences India had gone through, it was not possible to regulate, it was not possible to allow private sector to have the growth in its own manner because of the limitation of resources at that time, much investment could not be made in the agricultural sector and result was the country in the sixties' had to face a very difficult situation so far as wheat was concerned and had to depend on import of wheat to save the millions of people from starvation. Sir, when Mrs. Gandhi took over the reins of office, and I am a witness to those events from 1966 onwards, she felt that economic progress would be an illusion only until and unless we become self-sufficient in the production of food and agricultural products. So, this was the vision that Mrs. Gandhi took and the initiative she took to have the Green Revolution and the manner in which production grew in few years, India got self-sufficiency in food is matter of record that is for nobody else to dispute. Sir, I have got no doubt in my mind that the gigantic step that the Government has taken in the field of agriculture will be the harbinger of Second Green Revolution in India. Sir,

the country has made tremendous economic progress, economic growth has been the phenomenon. But unless fruit and benefits of this economic growth reach the millions of people who toil and sweat in the fields to serve the country, it will be only a matter of speech. So, something has to be done about that to improve the lot of the farmers for which this UPA Government is totally committed. Sir, I feel gratified to the UPA Government that it is fully alive to the problems, needs, and predicaments of the farmers. It is no ordinary achievement that the Government has effected an unprecedented growth, steep hike of 50 per cent in the Minimum Support Price of wheat and 33 per cent for paddy in the last four years. There is no denying the fact that for better marketing facilities, more productive seeds, fertilisers, remunerative prices will all go a long way in solving the problems of the farmers. Sir, relief, which has been given to farmers who were groaning under burden for non-payment of debts because of their meagre income, could not be more timely. Sir, revolution budgetary help to the Indian farmers, inspired by the vision of Shrimati Sonia Gandhi, has been in the finest traditions of Nehru-Gandhi family and its total sense of commitment to that. Sir, as probably the House will remember, or, history is a witness to it, it was Shri Jawaharlal Nehru who dragged endless miles on foot in this scorching sun across the parched villages of Uttar Pradesh to share the suffering and hardships of the farmers and imbibe in them a spirit of oneness. It was Shri Jawaharlal Nehru who wrote in his Will that when he dies his ashes should be flown up and scattered in the fields where Indian farmers toiled. Sir, Indian farmers have always been the most endeared and revered entity of Indian nationhood for the Nehru-Gandhi family. Sir, it is the same shared feeling of oneness of Shrimati Sonia Gandhi with the Indian farmers and her total identification with the lot that has come to their rescue who were being weighed down by an unbearable burden of debt and blighted all their hopes, distress and suffering life. Sir, it is her total commitment to bring solace to those farmers and their families which has led to the unprecedented step in coming to their help and bringing new cheers to their life. In stretching the warm hand of help to them in their hour of agony, Shrimati Sonia Gandhi has exhibited the spirit of oneness with the Indian farmers in the sublime traditions of Nehru-Gandhi family. Sir, I have got no doubt in my mind that for years to come, this gesture which has been made to the farmers of India will be remembered as one of the greatest testimonies to the commitments of Shrimati Sonia Gandhi to welfare of the poor and the downtrodden of this country.

SHRI ARUN JAITLEY (Gujarat): Sir, I am on a point of order. Is my learned friend speaking on the President's Address or the Congress President's Address?

SHRI R. K. DHAWAN: You think I should speak about Golwalkar or Nathuram Godse? If he wants me to speak on Golwalkar I will speak. If you want to me to speak on Nathuram Godse I will speak.

SHRI V. NARAYANASAMY (Puducherry): What Shri Arun Jaitley said is a point of disorder. *(Interruptions)*

श्री उपसभापति: आप बैठिए, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश): कभी-कभी तो प्रैज़िडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लीजिए ना।

SHRI R. K. DHAWAN: I can understand Mr. Arun Jaitley's hatred for the Gandhi-Nehru's family right from the university days when he was in college. So, I am not surprised by his hatred. It is a well-known fact. So, there is nothing wrong in your saying but I am not going

to speak about Nathuram Godse. It will further be remembered as a great step to correct the progressive growth of India with the hundreds and thousands of villages where these farmers reside and work day and night in all weather conditions to produce the food, which fed the country. I hope Mr. Jaitley will try to agree or tend to agree with this at least. I would refer to what Shri Jaitley wants to say. Some newspapers have described this budgetary relief to the farmers as pole-vault. Am I right, Mr. Jaitley? Yes, it is a pole-vault. It is not a pole-vault to the election year; it is a pole-vault, much to the discomfort of Mr. Arun Jaitley, of Shrimati Sonia Gandhi to the history of Nehru-Gandhi family. I hope he does not object to this. But, Sir, the UPA Government is committed for better decentralised Governance in democracy. The Congress Government with the vision of Shri Rajiv Gandhi got success to provide Constitutional status to Panchayati Raj institution in 1992. Sir, democracy has been further strengthened again at grassroot level by assuring transparency in administration and information to every citizen through Right to Information Bill. Sir, the Right to Information Bill is a historic and unique piece of legislation. By ensuring greater transparency in functioning of the Government it will help in reducing corruption and red tapism also. I think, Mr. Jaitley will agree. Sir, I must congratulate the Government for having expanded the coverage of the National Rural Development Act from 300 districts to cover all rural districts of India. The transparency in implementation has been improved by making muster rolls available on the Internet. Sir, the Govenrment has shown its commitment to provide rural health care facilities by strengthening the functioning of the National Rural Health Scheme to more than 22,000 primary health centres and nearly five lakhs Accredited Social Health Activists (ASHA) are now in position in the villages. Sir, the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission is another milestone. 8,000 houses have already been sanctioned for urban poor. In line with the commitment to welfare of common man, the Central Government will promote affordable housing through National Housing and Habitat Policy.

Another striking step taken by the Government is in the field of education. We all know that children are the heritage of the future. The UPA Government realised the importance of giving them the best possible education and it is education alone...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir, can any hon. Member readout a statement? I am not objecting to it. But, I need a ruling whether any hon. Member can readout a statement.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ramachandraiah, don't insist on ruling, because there are a number of Members who read from their notes...*(Interruptions)*...

SHRI R.K. DHAWAN: Reading from notes is no bar. I have seen that you also read many times...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, it is being done for the last so many years.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Poojary, please sit down.

SHRI R.K. DHAWAN: Sir, probably, they do not like the points that I am making. These are disturbing them. They have nothing else to say. That is why they are disturbing. They are in the opposition. They are supposed to oppose it. Since they do not have any positive points to oppose, they just stand up to say all these things for which I am not bothered.

Sir, it is education alone can establish...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I have got a doubt. That is why I have raised this point. There was a ruling from the Chair that no Member can readout a statement. That is all. I am not objecting to his reading a statement.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It was there in the rules.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I am not objecting to your reading, Mr. Dhawan...*(Interruptions)*...

SHRI R.K. DHAWAN: I am not reading...*(Interruptions)*...If you close your eyes, I cannot help it. I am just holding a paper.

Sir, it is education alone which can establish connectivity between the economic growth of the country and small towns and villages. Sir, it is extremely happy that the hon. President said in her Address that the Government seeks to provide universal access to secondary education by supporting 6000 new high quality model schools. We all know that in the primary stage itself there are many dropouts and the Government has taken a decision to extend Mid-day Meal Scheme to upper primary level so that there are lesser dropouts.

Sir, the Government is fully conscious of the fact that internal and external security of the country are the twin issues which figure foremost in the agenda of any country. No country can afford to ignore its basic internal and external security. I hope that the House will agree with me that this Government has, in spite of threats from terrorism and Leftwing extremism, succeeded in controlling the internal and external security of the country. The basic achievement of the Government is that it has not allowed the terrorism to be communalised and internal security to be communalised. This is one of the basic achievements of this Government.

Sir, the credit goes to this Government and it deserves all congratulations as India's cherished values of secularism have not been allowed to be sullied by the incidents of terrorism. The Government, through peaceful means, has been able to establish peace in the North-East, Naxalite-affected areas, Jammu & Kashmir and in some other parts of the country. There have been communal disturbances which tried to destroy the basic fabric of our country. The Government has successfully kept it on its toes. The Government has been able to restore the pluralistic ethos and control the dangerous trend of intolerance that had begun to eat into the vitals of this nation. We all know that the North-Eastern region, historically and politically, was, is and will always be a regular part of India. Different parts of North-East have different cultures. It is the pride of India that the nation has, within its own role, diversity of different cultures flourishing in different parts of the country. Sir, the political and historical integration of the North-East with the rest of India has to be translated into its economic and geographical integration. Sir, it is this Government that has formulated specially accelerated roads programmes, development programmes and more than Rs. 44,000 crores have been set apart for these development programmes. It is geographical integration and the spread of education which are keys to economic development of this area. They will usher in almost Industrial Revolution, providing tremendous opportunities of employment.

I congratulate the Government for the step that is taken to improve the defence capabilities of India.

I also congratulate the Government for looking after the interests of the soldiers, who protect our frontiers.

The Government has to be further congratulated for furthering and strengthening the policy of peace and stability with its neighbour.

I welcome advent of democracy in Pakistan, especially so because I had migrated from that country. I would like the peace to be there so that we can go there and visit our birthplace. That is the cherished desire. I am sure the new dispensation, the new Government, will be able to fulfil this.

When this Government took over the reins of office, it was the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, who declared that India and Pakistan should work in such a manner that the borders between the two countries become irrelevant. I hope this would be achieved soon and I will be able to visit my birthplace.

Towards the end, I would like to say, if someone asks me as to what has been the most important achievement of the UPA Government, I would have no hesitation to say that it is the inspiring leadership of Shrimati Sonia Gandhi that has led to the retreat of rising menace of communal virus in the country.

Sir, I have listened to the various points raised by various Members. I have listened to the views of my dear friend, Shri Arun Jaitely, also. But I cannot refrain from saying that they have talked in, what I consider, the most unrealistic fashion. I would like to remind them that they have, especially Shri Arun Jaitley, not refrained themselves from passion and prejudice — prejudice towards the Nehru-Gandhi family. I would like to quote here what Jawaharlal Nehru once said, while replying to the debate on the Motion of Thanks. I quote, "If you condemn everything your condemnation is really worth nothing. Your point of view can be valuable if you look at the whole picture and give credit that is due, and blame where it is necessary." I think Mr. Arun Jaitley will advise his friends to follow this, and so will he do.

Sir, I am grateful to you and to the House for the indulgence with which it has listened to me. With these words, I support the motion.

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Deputy Chairman, Sir, certainly our gratitude and thanks are due to the President for having addressed the Joint Session of Parliament. But when we oppose the motion of Mr. Dwivedi, no disrespect is intended to the hon. President. It is only our complete disagreement with those who drafted the Address of the President because we believe that this Government, for the past four years, has been a Government that has been directionless, which, as I will demonstrate, have been divisive, and which has sacrificed larger interests for the sake of vote bank politics. But before I do that, I must respond to a comment that the hon. Member, Shri R.K. Dhawan, made. I could have sought your permission to intervene when he made that comment, responding to my interjection, that I have hatred for a particular family, who are very respectable and honourable leaders of the Congress Party. There is no question of having any personal dislike or any hatred for any leader or particularly important political personalities. We only have political differences with them. But I would like to respond to what Mr. Dhawan said by merely saying that the converse of * is not hatred. The converse of * ...*(Interruptions)*

SHRI JANARDHANA POOJARY: He narrated the history. It is a part of history. *(Interruptions)*

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the converse of * is merely a desire for meritocracy. We are a

*Expunged as ordered by the Chair.

democracy, and democracies must always elect the best available leaders on the basis of merit and talent. We are a republic; we are not an elected monarchy. I have always believed, and many of those who share our kind of views believe, that the real worth of a republic or a democracy is realised only when these myths shrouded by *, surviving on the charisma of surnames, are demolished. The most developed democracy in the world, the United States, may, perhaps, in the next twenty-four hours, witness this process. And, I do hope that sooner than later the largest democracy in the world, that is, India, also realises....*(Interruptions)*....

श्री उपसभापति : आप बैठिए। Mr. Jaitely, please come to the President's Address. *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: He has nothing to do with the President's Address. ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि : आपकी समझ से परे है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बैठिए।... *(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए।...*(Interruptions)*... Mr. Narayanasamy, please allow the debate to go on. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Mr. Jaitley, please speak on the President's Address.

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): पहले उनको भी बैठने के लिए बोलिए, सर। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : बोल तो रहा हूँ। ... *(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, so many Members of Parliament have spoken respecting their leaders. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Everybody has a right to respect the leaders. Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: There are so many leaders. I can mention their names. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can speak when your turn comes. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए। ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I was only hoping that the real worth of the world's largest democracy, that is, India is also realised when we really have the best available talent across the board, which leads the country, in various political parties. I was saying this only to clarify that there is no question of having dislike or hatred or any such expression for any honourable leader, as far as this country is concerned. Sir, the people of this country ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I would like to draw your attention that this morning we got a bulletin from the Secretariat how a Member should behave. Now, the Chief Whip of Treasury Bench is behaving like this. Is he reminded of...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. Mr. Narayanasamy, please help the Chair. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

Mr. Jaitley, you have used the word *. This word is unparliamentary. I am removing it. It is there in the list of unparliamentary words. There are rulings. *(Interruptions)* I have removed it.

---

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI R.K. DHAWAN: Mr. Arun Jaitley may please withdraw those words.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have removed it.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I will leave that debate apart. ...*(Interruptions)*... There are many synonyms which are capable of having the same meaning. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...*(Interruptions)*... We have to follow certain rules. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: But, I am sure, my friends have got the sense of what I intended to say. Sir, the UPA Government is on the verge of entering the fifth year of its governance. The President's Address is full of kudos and praises that the Government has chosen to confer on itself. But, if the UPA looks at the ground around it, what is the political reality as far as the country is concerned? You have had a series of elections in the last two years. Do my friends in the UPA even remember when was the last significant political victory that they scored? Two years ago, they lost Bihar. They lost Punjab. They lost Uttarakhand. They were routed in Uttar Pradesh. Now, they lost Gujarat. They lost Himachal Pradesh. These are States I am counting in a row where elections were held. ...*(Interruptions)*... A large number of these States were under the Congress rule. Additionally, they even lost States like Jharkhand and failed to get a majority in Goa. It was only a process of political manipulations that put them in power in those States. ...*(Interruptions)*... But the tragedy is, and as this Address represents, that they have unleashed a propaganda. But there is always a temptation and this temptation costs many people. It has cost us in the past also. The lesson of this kind of propaganda is that when you overstate that propaganda, you end up buying your own propaganda, nobody else buys that propaganda. ...*(Interruptions)*.. These are lessons which people have learnt. And this is a lesson which the UPA refuses to learn. ...*(Interruptions)*... They are living in an illusion of some illusory glory under an arrogance that they are going to continue in power indefinitely. But, if they see, as I said, the political reality around them, which is now reflected, it is becoming even more difficult to remember as to when the UPA partners won their last election. It is a series of defeats which stares them in the face. After the Budget a few days ago, I heard my friends getting very enthused and saying that we are ready for an early poll. They even taunted our friends in the Left saying that we will call the bluff of the Left and go for an early poll. Well, a poll is due in Karnataka. The President's rule ends in Karnataka on 28th May. Every effort is being made to make sure that one more defeat does not get added to the chain of these defeats. And, therefore, constitutional devices are being brought about how to make sure that the Karnataka election is deferred. ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Mr. Jaitley, we are ready for elections. ...*(Interruptions)*... What we want is a perfection in the voting list. ...*(Interruptions)*... You people are managing in such a way that ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. ...*(Interruptions)*...Mr. Poojaryji, please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: We are ready for elections. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no practice here that the Members should reply to each other. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the Delimitation Commission submitted its report on Karnataka on 23rd March, 2007. It is eleven months ago that the Delimitation Report on Karnataka was

submitted. Under this present delimitation, the whole country is not taken as one unit. Every State is taken as a separate unit. We knew the dates when Karnataka Assembly was dissolved months ago as to when elections are supposed to be held. The outer limit is 28th of May. If you are so confident of holding the election in Karnataka — the Delimitation Commission Report was there — preparatory work should have started. The geographical area of the constituencies is notified. Only polling booths have to be superimposed on them. There is a statutory rule, Rule 24 of the Registration of Electoral Rules, which says that when delimitation takes place and elections are to be held, do not postpone elections but on a fast-track, do this superimposition exercise. Nothing is done. Shrimati Indira Gandhi, through the 42nd amendment – the hon. Law Minister is here, he knows the provision— brought an amendment to the Constitution saying that when delimitation takes place, till such time it takes place, do it under the old, but don't postpone the elections. Here, you have a rule, you can do it under the new by going on a fast track. You choose to violate the provisions of law and then, you say, a situation has arisen that governance cannot be carried on according to the Constitution because I am violating the law; therefore, one more spell of President's Rule, let Karnataka be postponed. According to me, we have had a series of elections, the results are obvious. The next election is due in Karnataka. There is no reason why it should be postponed. Please follow the law which says, "Do the superimposition of polling booths on Constituencies on a fast track basis which law mandates and hold an early election in Karnataka" but you will choose to put this responsibility on the shoulders of the Election Commission and say "we now want to postpone the polls"... *(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: The Election Commission has written to the Law Ministry stating that they want eight months' time.

(THE VICE-CHAIRMAN), SHRI DINESH TRIVEDI (in the Chair)

SHRI ARUN JAITLEY: Therefore, Sir, if what Mr. Poojary says is correct, that is precisely the reason that the Government or the Election Commission should not have woken up in the month of February, 2008, but should have woken up six months ago when the Delimitation Commission's report was with them and not postponed the notification of delimitation so as to enable you to postpone yet another defeat. That is what you are doing. Sir, let us look at the track record of this Government. The Finance Minister has said there is nothing wrong in planning policy or Budget, keeping elections in mind. Shri Dhawan also said, elections are there; therefore, we will plan it accordingly. This country is paying for the political insecurity of the Congress Party on the eve of the election year, and we will continue to do that for the next few months till the elections are held. Look at the track record of this Government. What have they done to various institutions? Even your past record has not been one of glory, but we thought that perhaps we would have learnt lessons from history. From the day one since the UPA Government has been formed, the primary institution in a democracy is the institution of the Prime Minister. A very honourable gentleman occupies that office. I was hearing the speech of Shri R.K. Dhawan. The best evidence is, when Mr. Dhawan was making his speech, I interjected, all kudos to a person other than the Prime Minister for the success of the UPA. Systematically, you debase and devalue that office. You create centres of power outside the Prime Minister's office and make them taller than the Prime Minister. Therefore, the structure of the Government in this country stands upside down.

SHRI R.K. DHAWAN: But not the RSS... *(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: You have a situation when we complained, when this Government was formed in 2004, that for the first time we have a whole string of tainted Ministers joining

the Cabinet. First time, this country witnessed that you had a series of Ministers, who had criminal cases, as a part of the Council of Ministers. The country was shocked that there is a criminalisation of the Council of Ministers taking place. Then, you start subverting one institution. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): As a Law Minister, he allowed a convicted person to continue as a Chief Minister. As a Law Minister, he allowed that. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Sir, what can he do? People elected us. ...*(Interruptions)*...Please understand that. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHAHID SIDDIQUI (Uttar Pradesh): Sir, what is this? Is it a Rajya Sabha debate or a TV debate? All the people are rising and raising questions after questions. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY (Puducherry): Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Under which rule?

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, let me tell the fact. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Okay.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Member has been making a point about the Central Ministers whose cases are pending in the court. That means, on criminal cases, whether they have been convicted or not. This matter is pending in the Supreme Court. Any matter that has been pending in the Court cannot be raised in the august House. This matter is *sub judice*. Therefore, Sir, he cannot raise that issue in this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Please carry on.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I have not raised any issue pending in a court. I don't intend to raise so. I am not on what is pending in courts. I am on subversion of institutions. Take them one by one. What has happened to the CBI under this Government? I saw on the television channel yesterday what the Government has said. Regarding the former Chief Minister of Haryana, it said, 'yes, we intend prosecuting him.' He belongs to the Opposition. Regarding the former Chief Minister of UP, Samajwadi Party, it said, 'we intend to proceed against him.' On the former Chief Minister of Tamil Nadu, different Departments, including, Tax Departments, were let loose. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Please don't disturb. Let him carry on. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: The whole country would be shaken. Fortunately, the report of the CBI has come which is a slap on the face of this Government. Somebody whose ethics and integrity was not only proven but inspired confidence — even Arun Shourie's integrity — had to undergo this test of fire, and then what happened to each of the tainted Ministers? You find either prosecutors are changed or you find courts are being changed or you find appeals are not being filed. In the case of each one of them, persons close to the Congress Party, you witness a complete subversion of each of the institute. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, what about my point of order? Why I am asking it is because he himself has admitted that the matters are pending in the court. This matter is *sub judice*. How can he raise it? ...*(Interruptions)*... What about the procedure? ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, my grievance is, one by one, the matters are coming to an end ...*(Interruptions)*... and they are not pending in the court.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): There are more point of orders than anything else.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I have a submission. This morning I got a bulletin from the Rajya Sabha Secretariat.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): You have already mentioned that once. ...*(Interruptions)*... You have already mentioned that.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I want a ruling. You either withdraw this bulletin or implement it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): I appeal to the hon. Members that kindly let hon. Arun Jaitley have his say and whenever you are speaking, you can add on to whatever you want to.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, we complained at the time when these actions took place. You use or misuse the institution of a Governor in order to install Governments which don't have a majority, then engineer defections and create a majority. Jharkhand witnessed this, Goa witnessed this. Sir, but some institutions were sacrosanct. ...*(Interruptions)*...

SHRI R.K. DHAWAN: What about the re-induction of ... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Please, please.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, some institutions were sacrosanct. ...*(Interruptions)*...

SHRI R.K. DHAWAN: What about the re-induction of George Ferdnandes? ...*(Interruptions)*... The report had not come and you inducted him again in the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Except Shri Arun Jaitley's speech, nothing else is going on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, some institutions were sacrosanct and one of the main reasons why compared to some of our neighbouring countries, we not only survived but we strengthened ourselves as a democracy was that we had an independent judiciary; we had a military which was non-political and professional; we also had an Election Commission which never rigged elections. There are other countries around us which did not have the same privilege. And, in the last 60 years, we saw that they suffered because of these three weaknesses. Today, in an institution like the Election Commission, a large section of this House and the other House feels that even in the matter of making appointments, precaution is not being maintained in ensuring complete freedom from bias. This House and the other House debated and passed, obviously with our dissents and disagreements, the Office of Profit Bill. Persons should have been disqualified for violating the law, but we tried to legitimise everything that they had done. This is the manner in which this Government has functioned in the last four years. When I see statements of leaders of the Government, I find that your Health Minister is busy fighting the medical fraternity. I find that your Sports Minister is busy fighting the Indian Olympic Association. I find that your Commerce Minister is busy fighting the Finance Minister. I find that your two Ministers from Bihar, Shri Paswan and Shri Yadav, disagree on everything except remaining in power in the same Government. This is the collective responsibility that this Cabinet has shown to us in the last four years. ...*(Interruptions)*...

Sir, I can only put in a word of caution for this Government. The last few months have now witnessed even increased attacks on the judicial institution when no tensions existed in either the Legislature or the Judiciary. Some of the statements made even by constitutional functionaries and holders of important offices are now intending to create a tension, something which would be otherwise very unhealthy for the functioning of a democracy. Whenever all this happened in the past — it happened in the 1970s and we protested — a large number of our friends from the Left were also busy protesting with us. They objected even when we at times tended to go wrong. But our regret is that in the last four years, when all this is happening, our friends in the Left, who otherwise claim to be very strong defenders of the institutions, adopted a very strange course. They thought that they could influence Government policy from within and try and occupy the Opposition space outside. But this kind of dialectics cannot last indefinitely. Only time will tell how they have been caught in their own contradictory games and how they themselves stand to suffer on account of what is happening.

Sir, I find that a large part of the President's Address is confined to the economic achievements of this Government. The Government is priding itself on the fact that the last four years, rather five years if 2003-04 is included, have witnessed an average 8.8 per cent growth in the GDP. It is a growth rate which can make any country proud. But what the UPA does not realise is this growth rate is not on account of any of the policies of the UPA. Sir, you have a 10 per cent growth rate in the manufacturing sector and a close to ten per cent growth rate in the services sector. The services sector in this country is fortunately surviving without governmental support. The manufacturing sector needs a policy impetus and you have a Government, which on the economic policy front, has been paralysed in the last four years. It is a Government which does not take decisions. I had earlier said that in the past, when our present Prime Minister was the Finance Minister, from 1991 to 1996, or when Mr. Chidambaram was the Finance Minister in the United Front Government, they did take the reforms forward. Despite opposition they had made reforms an art of the possible. But in the last four years, they have made absence of reforms as the art of survival. You do nothing for the chances of going wrong will not be there and, therefore, you can last your Government till end. This 8.8 per cent growth rate is not because of the UPA; it is not policy driven. It is predominantly driven either by the impetus of the policies from 1991 to 2004 when several Governments took several initiatives; it is entrepreneur driven and somebody, who in the policy domain has been a rank usurper because nothing has been done, just steps into trade because this was the coincidence that I happened to be the Finance Minister during that period even if I did not take a decision the credit goes to me because my term was coextensive with this growth period. What are we passing through? We are passing through a phase where infrastructure is being ignored. The ports in the country are clogged. The priority to the highway sector, the rural roads and the power sector reforms — the priority to them was brought in the NDA Government — has gone to the back burner. You today have a regime where there is a high cost of housing, there is high cost of education, there is high cost of healthcare, there is high interest rate and inflation is again on the rise. After the recent Budget, even the Finance Minister has been, at least, fair to caution that in months to come the foodgrains inflation will grow even higher. This has been the management of the economy by those who claim to be the protagonist of *Aam Admi*. You are now coming at the fag end of your term and shedding crocodile tears for the *kisans*. Sir, today if 60 per cent of India is in the agricultural sector, the plight of the farmer is apparent, that only about 18 to 19 per cent

of the GDP contribution comes from the farm sector. Forty per cent of India is involved in manufacturing and services. They take away 82 per cent of the GDP. For the poor farmer, in the rural sector, only 18 per cent is there. The farmer is in a distress that you need a situation where he needs rural infrastructure, he needs irrigation and he needs input cost to be brought down. Why does he commit suicide? He commits suicide because he is caught in a debt trap. Why is he caught in a debt trap? He is caught in a debt trap because his input costs are much higher than what the output he gets and, therefore, the debt continues. But you think if you can just try and inject once some instant relief the problem of the farm sector will be over. What will happen two years from now? Sir, we would like the Government to, at least, give us a few clarifications, particularly when the Prime Minister responds to this debate. If Rs.60,000 crore worth of debt is to be written off and waived, this House will unanimously welcome it and hail the Government for it. But already doubts are creeping up in the minds of the country and these doubts are not only in the media and these doubts are not only in the farmers' mind and our mind, I find even several Members of the Government and the Treasury Benches asking a question to each other, where is this money coming from. Sir, Rs.60,000 crore is a very large amount. It cannot be spent without a budgetary allocation. The economics is very simple. On 31st March, 2007, as per the Reserve Bank Report, the total non-performing assets of the agricultural sector were Rs.7237 crores. Now, out of this, if we take only the small and the marginal farmers, the amount may be even lesser because this is the total bad debt in the form of non-performing asset of the farm sector and that has already been written off as a bad debt being an NPA by the banks. If we now support the banks, it will go into their Balance Sheets as profits. It is now being said that this amount of Rs 7,237 crores by 31st December, 2007, has probably, become Rs.11,000 crores. So, if this is the position of the scheduled banks, is the balance Rs. 49,000 crores going to be given to the Regional Rural Banks and Co-operative Banks? Well, if on 31st March, 2009, somebody shows us a Balance Sheet account and says that Rs. 49,000 crores have been given to the Co-operative Banks and Regional Rural Banks by the Finance Minister, we will hail him, without a budgetary provision, as the greatest magician in history. Sir, the tragedy of Mr. Chidambaram's Budget is being that the next morning's headlines never give a true image of that Budget. The devil in his Budget is always in the detail. It is only after two or three days you realise what has happened. There is a phrase that the Americans use. They call it 'fudgy maths'. It is a simple phrase which means fudging mathematics. It is very simple what we learnt as students of preliminary Economics in school and college that there are three kinds of lies - lies, damn lies and statistics. So, fudgy maths cannot become the hallmark of a Government. On 31st March, 2009, probably, the Finance Minister will not be there to be held accountable when we would ask him to please show us from which budgetary provision, this Rs. 60,000 crores came and he has spent it. But, if he actually allocates Rs.60,000 crores for this purpose, as I said, not only the greatest magician, I would be willing to bow before him as the greatest Finance Minister in the history who could invent Rs.60,000 crores without a budgetary provision and give it to the co-operative sector of this country. But, Sir, it is only history and history, which is very near to us, which will make its final judgement as to what really happens, as far as this proposal is concerned. But, if this proposal is implemented, as I said, we will all welcome it. Sir, as far as economic planning is concerned, all I have to say is that the Prime Minister has been a very distinguished economist. But, we would now like, at some stage, the real economist in him to stand up. It cannot be that you are a very distinguished economist, but you are a conservative during the regulatory regime; you are a liberaliser during Mr. P.V. Narasimha Rao's Government; you become a do-nothing economist in the first four years of this Government because the Government has been changed; and, in the

fifth year when elections are nearing, you resort to desperate politics as Economics. That is not the kind of Economics any economist would have learnt. Bhandaryji was just now mentioning and Dhawanji was mentioning about the NREG Scheme. Well, if you can give employment to the most needy in Indian society, it would be welcome. Only today morning, I was reading a comment by a very distinguished person, who is very favourably inclined to this Government, and he was the Member of the erstwhile National Advisory Council, who, quoting the AGCR Report, has said, "No wonder that the legal guarantee of hundred days' wages, according to the Comptroller and Auditor General of India, has been fulfilled only in three per cent cases." This is the comment of a Member of the former National Advisory Committee headed by hon. President of the Congress appears in *The Business Standard* on the front page today. Sir, when you have a Government which is faced with the situation of this kind, what does the Government do when elections are approaching? You have a Government which puts national security into the background and starts linking up all national security requirements not with the need to protect India but with the concerns of vote bank politics. What has happened today? Let us analyse the situation. Cross-border terrorism has not ended. We hope our neighbour on the western front is stable. Any instability there will add to our problems. There is still no comfort of long-lasting stability. In Kashmir, except for two failed round-table conferences, the last four years witnessed nothing more. There is a situation where you are now calling groups to meet, where somebody starts demanding autonomy, somebody starts demanding pre-1953 status. Is it the time to open up these issues in the context of Kashmir? You have Nepal in turmoil and that turmoil is affecting 170 Districts in this country when it becomes an epicentre for Maoist training, which has made life unstable in several parts of the country. With Bangladesh, you have an open border from where illegal migration takes place. The Supreme Court quashed the provisions of the IMDT Act. You brought the Foreigners Control Order where the onus is not on the illegal intruder but on the Government to show that he is an intruder. The Supreme Court quashed that. And, today, you find it is not only Lashkar-e-Taiba or Hizbul-Muzahideen operating from Pakistan but organisations, which have been outsourced by the Al-Qaeda such as Huji, are now based in Bangladesh also. Those activities take place in Nepal also and this provides an infrastructure, logistical support to acts of terrorism. In all incidents that have taken place — you had Mumbai blasts, you had Malegaon, Hyderabad, Bangalore, Varanasi, Lucknow, Gorakhpur last year, Rampur and also Delhi — in each one of them, the logistical support comes from within, and, therefore, we have to be very vigilant that we do not allow this kind of situation to take place. What is your response? We are withdrawing POTA. What did we see as a consequence of that two days ago? The Maharashtra Government, which is a UPA Government, said under normal law, we cannot even prosecute who blasted Bombay on 7/11 in those train blasts. They got an identical version of POTA, that is, MCOCA to prosecute those people. Now, those persons who are being tried are saying, POTA, which was for terrorists, has been withdrawn, MCOCA is for local *goondas*, why are we being proceeded for terrorism and insurgency under this law. The trials have now been stayed by the Supreme Court. We need an easy legal regime to deal with terrorism. This is proclaimed policy of the UPA Government. This is how instances of terrorism are going to be handled as far as this Government is concerned.

You start policies of worst kind of divisiveness to create a vote-bank politics. Religion-based reservation, there is no place for such things in our Constitutional scheme, but you will do it. Another is, 'communal budgeting'. Communal budgeting — which would have been a political sin sixty years ago, before Independence, if somebody had suggested it — is now becoming the rule today, and, budgets are hailed on the strength that allocations are

made on the basis of communal budgeting. You have a proposal for those who have converted, the *dalits* who have converted to Christianity and Islam — I am not on the issue of conversion — to extend reservation. What will happen? Has anyone of us realised as to what will be the consequence on the ground? Under our Constitutional schemes, minorities are entitled to one set of protection. Nobody at the moment is quarrelling with that. The socially and economically weaker sections are entitled to another set of protection. But if you belong to Article 16 category, that is, you are entitled as a *dalit* to reservation, and, you convert your religion, suddenly you have a bonanza in both hands; you are entitled to both the privileges. So, a normal *dalit* will get the Article 16 benefits; the converted *dalit* will get Article 16 and Article 29 benefits and you will open a Pandora's Box by giving this incentive on conversion and bring demografic disaster in this country by creating tensions. But, because you need the votes, you will say, "Let us give reservation of this kind". You will be creating not only a social upheaval but also in the process creating the creamiest of the creamy layers. You convert and you get an economic advantage. How can this be a policy of any Government? Shri Rajnath Singh yesterday referred to Ram Setu. Ultimately, slowly but surely the policy of this Government is being that somehow we must see that the Ram Setu or the Adam's Bridge is dismantled. You do it and realise the political consequences of this. The Government appointed a Committee of eminent people. We always respect eminent people. But, eminent people must produce eminent documents. I was going through the report which has now been made as the basis for the latest affidavit before the Supreme Court. The Committee of eminent people says, "if he", by 'he', they refer to Lord Ram, "If he were alive today, he himself would not have opposed a project of this nature meant for improving the welfare of the people". So, the Committee on Ram Setu has come out with a document that if Lord Ram were alive today, even he would have supported the demolition of the Ram Setu. ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: You are not aware ...*(Interruptions)*... You created it. ...*(Interruptions)*... Your party has created it. ...*(Interruptions)*... Your party has supported it. ...*(Interruptions)*... Answer this to the nation. You said it. ...*(Interruptions)*... Why you said? ...*(Interruptions)*... Answer this question. ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि : पुजारी जी, आप इतना क्रोधित क्यो हो जाते हैं? ...**(व्यवधान)**... क्या इसलिए कि कर्नाटक की विधान सभा भंग है? ...**(व्यवधान)**...

SHRI ARUN JAITLEY: Now, Sir, Mr. Janardhana Poojary, yesterday also I found he referred to me by name and today also he is referring to by name. I think, he must hold his Minister responsible for misguiding him because he misguides you and does not show you the file. The Government has filed an affidavit in the Supreme Court now. A proposal which merely says, "Before taking any decision, you must first have a techno-economic study", it is sad that Mr. Poojary's Minister misguides him and says this was the approval of the project. This is what your affidavit before the Supreme Court says. I am sure, at least, this time the Government have spoken the truth before the Supreme Court. Sir, we have a whole set of promises which this Government has not kept. Women's Reservation Bill, it was a part of your Common Minimum Programme. You don't even introduce it. You don't even make an endeavour for a consensus or a discussion. You don't take it even an inch further. Creation of a separate State of Telangana, you do nothing in the matter and don't move which has led now to the resignation of Members from the Lok Sabha. Sir, if we look at the last four years, your economic governance is at a standstill. You only want the taxpayer to pay for projects and we all willingly support you on that without being sure as to what the real intention of

this Government is going to be. So, we are at that stage of history where India needs a determined leadership, India needs a decisive Government, India needs firmness in matters of national security. Let us test this UPA Government on all these three counts. You have a leadership which is incapable of taking decisions. It takes decisions and then rolls them back, can't implement them. You have an indecisive governance. As I said, the major achievement of this Government is, it has managed to last four years and the secret of this Government's success in lasting four years is a do-nothing approach. Sir, Governments are not judged by the praise that they confer on themselves in the Presidential Address. Governments are not even judged by the number of months they stayed in power. They are judged by the kind of decisions they take and the kind of course that they put the nation on to.

When we judge this UPA Government, I think that the time has come for the country to realise that this country needs a decisive Government; this country needs a determined leadership; and the country realises that the UPA is incapable of providing that. Thank you, Sir.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, what about the ruling on the point which I raised? I quoted it. It is on the matter which is pending in the court relating to the speech. But you have not given the ruling.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): The rule is very clear. For the benefit of the House, I will read it. This is Rule 238 which everybody knows.

It says, "A Member while speaking shall not —

(i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending;"

So, if any such mention has been made, we will ensure that that does not go on record, as per the Rule.

SHRI V. NARAYANASAMY: Thank you, Sir.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, while thanking the hon. President for addressing the Joint Session of Parliament, I oppose the Motion.

Sir, the Address made by the hon. President is taken as a policy document of the UPA Government. Sir, the UPA Government is a post-poll alliance Government. Each constituent has got a separate agenda and a separate manifesto. The present Government has miserably failed in tackling the problems of farmers, workers, weaker sections, youth, students and minorities. Sir, they have made tall promises through the NCMP, but they have not just implemented them. I would like to remind the Government to have an introspection on the NCMP.

Sir, every constituent of the UPA Government, as I said earlier, has got a separate agenda and they are literally dictating the hon. Prime Minister and one constituent has gone ahead by announcing the Ministry Portfolio and date of taking oath also from a different corner of the country. Sir, they have made the office of Prime Minister a defunct organisation. And it has become a non-entity.

Sir, I would like to remind them that yesterday one of its constituents left the UPA. Sir, the very purpose of the UPA is to usurp power and to hang on to it. Otherwise, they have got no specific agenda for the improvement of the nation and for the welfare of the people.

Sir, coming to the problems of farmers, the Economic Survey has confirmed that there is an agrarian crisis in the country and the foodgrains production is not adequate for the growing population of our nation. We have started importing foodgrains from small countries and that also by paying exorbitant prices.

Sir, the investment in agriculture is declining and now agriculture has become unremunerative. Many people are leaving this profession. The cultivable land in the country is also shrinking. One of the reasons is Special Economic Zones which are mentioned by the hon. President in her Address.

In the Special Economic Zones, those who have grabbed them, they are treating them as Special Exploitation Zones; and the people who are losing their land, for them, it is Special Elimination Zone. Sir, more than one-and-a-half lakh people have committed suicides and this Government has not woken up. In my own State, Andhra Pradesh, more than five thousand farmers have committed suicides. Sir, the package announced by the hon. Finance Minister has not at all helped them. Now, the Government has come out with a proposal of waiver of loans, that too, when the UNPA was agitating since many months. We have been going around the country, enlightening the farmers, mobilising them and creating pressure on the Government. Now, the hon. Finance Minister, while presenting his Budget, has given a concession of waiver of loans to the small and marginal farmers who are holding less than five acres or two hectares of land, that too, to those who have availed loans up to 31st March 2007 and have defaulted by 31st December, 2007.

Sir, there is a report wherein more than Rs.3,25,000 crores are in debts by the farmers. Sir, they are in distress by virtue of raising loans from private money-lenders. Other than institutional finance, they are borrowing from private money-lenders by paying exorbitant interest rates. Sir, they are not covered under this scheme. Sir, there is a discrimination with small and marginal farmers and other farmers. Sir, farmers in one area, if they are having more than ten acres of land, it is not equivalent to two acres of land in other parts of the same State. So, there is a clear discrimination, dividing the farmers. Sir, the Government has to apply its mind and come out with a proposal to waive off all the loans of all the farmers including the loans raised from private money-lenders. Sir, otherwise, it's going to a big problem and the suicides, according to the Agriculture Ministry itself, will not stop.

Sir, I read a statement of the hon. Agriculture Minister saying, "Don't pay the money to the private money-lenders." Sir, farmers have self-respect. Having borrowed money, they try to pay back the money. I demand that the Government should come out with a legislation. Have moratorium in the beginning and then come out with a legislation, compensate those people who have given money to the farmers and come to the rescue of the farmers. Otherwise, it is going to be a big problem. Sir, according to a newspaper report, only eight to ten per cent farmers are covered by virtue of this package. Others are just left out. How are you going to solve the problem of farmers, and that too, when you are importing foodgrains from smaller countries?

Sir, I would like to mention another thing. Sir, the National Agricultural Insurance Scheme is not at all helpful to the farming community. We were demanding for a change in the National Agricultural Insurance Scheme. But, the hon. Finance Minister chose to continue the scheme with the same specifications. The Address of the hon. President says that they are implementing the insurance scheme. Sir, I would like to demand that there should be a change and it should be a farmer-friendly one.

Sir, coming to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs, the President's Address says that they are extending financial assistance to them. I demand that you come out with a white paper as to what are the details. In view of the larger Budget and outlays, the money allocated to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs is very meagre. Sir, I have got an answer from the hon. Minister yesterday. I am holding it. Sir, the reservation for SCs, STs and OBCs in judiciary is not there. The answer says that they need a constitutional amendment. Why don't you come out with that? The Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances and Pension, Law and Justice has given a detailed report on this aspect. I demand that there should be a constitutional amendment to help the SCs, STs and OBCs to have reservations in the judiciary.

Sir, coming to essential commodities, the NCMP and the President's Address speaks about *aam admi*. But, they have forgotten about the essential commodities and rising prices. *Aam admi* is not in a position to purchase them. Having raised the prices of petroleum products seven times, it has got multiplier effect on *aam admi*. Sir, I demand that the Government should take concrete steps in containing the prices of essential commodities; otherwise, it's going to be a very big problem for the rural poor. Sir, coming to the health sector, the report says that there are some flagship programmes like National Rural Health Mission and Bharat Nirman. All those phrases are good, but in reality, people are forced to go for private treatment, and all the primary health centres have become defunct. There are no doctors in rural areas, no medical facilities are available and people are forced to go to the private hospitals by paying higher prices. They are not in a position to afford these medical expenses. Sir, the hon. Health Minister, while introducing the National Rural Health Mission programme, and that was also mentioned in the President's Address, referred to ASHA. For everything, they say that ASHA is in place. Sir, for everything, ASHA! I don't understand this. Sir, I come from the rural area. I was also a *sarpanch* of the village. I know the practical difficulties in this. Ultimately, this ASHA programme is going to end up in *nirasha*. For everything, they are depending on ASHA. They are not fully equipped, they are not experts in medical field, they will only assist the people. But, where are the doctors? Where is the facility? Where is the infrastructure? So, all these things need attention.

Coming to education, very high appreciation is placed on record by the hon. President. I would like to refer to the Sarva Shiksha Abhiyan. As announced yesterday in this august House, a lot of money diverted is misused, is misappropriated. In the answer, the CAG report for 2005-06 says, the money involved is Rs. 6.8 crores in Assam, Rs. 15.8 crores in Bihar, Rs. 22.9 crores in Gujarat, Rs. 4.7 crores in Karnataka and Rs. 15 crores in Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh, in this scam, one officer who is working in the hon. Chief Minister's office, is himself involved. The Government of India is not at all taking any concrete steps in recovering the money, in booking the culprits so as to save the money and help the poor people for whom we are paying cess to the Sarva Shiksha Abhiyan programme. I would like to demand a total inquiry into this scam. For the Mid-day Meals scheme also, the infrastructure is inadequate. Infrastructure like kitchen shed, storage room, plates, glasses, utensils, all these things are not at all put in place. I request the Government of India to help the State Governments to help the school committees in upgrading the present infrastructure.

Coming to the other infrastructure like roads, the condition of rural roads is very bad except the Golden Quadrilateral roads, north-south corridor, east-west corridor and other programmes, the rural areas roads are totally neglected, and in the Bharat Nirman programme, it is mentioned that roads are improved and a lot of money is spent on that. Practically,

nothing is happening on the rural roads. I would request the Government to concentrate on these things.

Under the National Rural Employment Guarantee programme, they have given promise to the nation through their NCMP. I would read out the opening sentence of this NCMP. They said: The UPA Government will immediately enact a National Rural Employment Guarantee Act. This will provide a legal guarantee for, at least 100 days of employment. In the initial stage, they have introduced it for 150 districts. Thereafter, it is made into 300 districts. Now, at the fag end of their tenure, they say that it is going to be implemented for the entire nation. I would like to caution the Government on this count that there are reports from the special audit and they are not placed before the people. They should be made public. The social audit reports say that a lot of misuse is taking place, and the job cards which are meant for the poor workers, now have become ATM cards for the Congress party workers. They can draw money any time. For the convenience of the Congress party workers, this programme has become a Congress Party Workers Employment Programme, not for the common poor people, who are really in distress in the rural areas. I have an instance. I have the record with me wherein, in the name of a dead person, money is drawn. A lot of reports are there from districts like Anantapur, Cuddapah and Mahbubnagar of my own State, where the hon. Prime Minister launched the Programme. There is a total misuse, Sir. And the people who went there for social audit were not allowed to enter the village; they were locked up in the room. This is the state of affairs as far as the National Rural Employment Guarantee Programme is concerned. I would like the Government to have a total review of the Programme and book the culprits.

Women reservation, as my earlier speakers mentioned about it, my party is committed to this, and we have been demanding one-third reservation for women. This was promised in the NCMP: "The UPA Government will take lead to introduce a legislation for one-third reservation for women in Vidhan Sabhas and Lok Sabha." Sir, nothing is happening; not even the introduction of the Bill. No concrete steps have been taken in this regard. Just for sake of their votes, they are saying that they are interested in one-third reservation for women. A legislation should immediately be brought to this august House and should also be passed.

I come to the Reports which are pending with the Government. For example, there are Reports like the Swaminathan Commission Report—that was submitted in October, 2006—Sachar Committee Report and Arjun Sengupta Commission Report which are pending with the Government. So many Reports are there with the Government, but the Government is not at all implementing them. They are just lying over there. I demand that those Reports should be placed before the House; there should be a discussion, and they should be implemented *in toto*. Otherwise, the very purpose of constituting those Committees will be defeated.

Coming to the Indo-U.S. nuclear deal, again, the hon. President has stressed on the Indo-U.S. nuclear deal. We oppose the deal. It is a threat to our sovereignty. And the amount involved is Rs.3,30,000 crores. This money will go only to private companies and a few individuals. Otherwise, our people are deprived of roads, health, education, and everything. When we are in a position to generate one megawatt of power with Rs.4 crores, why should we pay Rs.11 crores for one megawatt though this Indo-U.S. nuclear deal? We fail to understand that. We demand that the deal should be stopped. Otherwise, it is going to be a threat to the sovereignty of our nation.

Coming to para 35 wherein the hon. President has mentioned about the coming up of

airports in Hyderabad and Bangalore, Sir, these airports were conceived, contemplated and started during the previous dispensation, and my leader, Mr. Chandrababu Naidu, was in the forefront in getting this Greenfield Airport to Hyderabad. They are going to inaugurate the Hyderabad Airport on March 14, this month only. Who is inaugurating? Not the President; not the P.M. An M.P. from Uttar Pradesh is going over there to inaugurate! How she is entitled, I don't understand. They are going to create a very bad precedent. What is her capacity? Sir, we object to this, and at the same time, we also object to the naming of the airport. They are closing the Begumpet Airport, which was called the Rajiv Gandhi International Airport, with an N.T. Rama Rao domestic terminal. Now, they are going to shift the entire airport on March 14, and they are naming in only after Shri Rajiv Gandhi while ignoring the name of Shri N.T. Rama Rao. Sir, we object to this. The Government of India is habituated; the present dispensation is habituated in changing the names of great people like Shri N.T. Rama Rao. To this, we take strong objection, and the Government should definitely amend it and take steps for that; otherwise this is going to be a big problem.

Sir, coming to other aspects like infrastructure and irrigation, recently, the Government of India has given a lot of money for 14 irrigation projects as national projects, but not for even one project in Andhra Pradesh. The southern States are totally neglected. And in case of sanctioning other institutions, Central Universities and everything, Andhra Pradesh is neglected. I demand that there should be a reasonable distribution of institutions, a reasonable distribution of assets to Southern India.

With these words, I oppose the Motion. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Thank you, Shri Reddy.

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन करते हुए अभिभाषण के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

महोदय, महामहिम के अभिभाषण में भारत निर्माण की चर्चा आई है। इसमें रंच-मात्र भी संदेह नहीं कि आजादी के बाद भारत के निर्माण जरूर हुआ है और चतुर्मुखी विकास भी हुआ है, इसके लिए मैं देश के वैज्ञानिकों, देश के किसानों और उद्योगपतियों को बधाई देता हूं जिनकी मेहनत का परिणाम आज हमारे सामने है कि सकल घरेलू उत्पाद 8 से 9 प्रतिशत के बीच में है। सरकार ने 9 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को प्राप्त कर के बहुत से लोग सुखद अनुभव कर रहे हैं। यह अच्छी बात है, किंतु भारत निर्माण में दूसरे पहलू पर कम ध्यान दिया जा रहा है जोकि एक चिंता का विषय है। आजादी के बाद जहां भारत के विकास की गति बढ़ी है, वहीं मेरी राय में आजादी के बाद अमीर-गरीब की खाई भी बढ़ी है और अमीर-गरीब के बीच की खाई के बढ़ने के फलस्वरूप आज देश की स्थिति यह है कि जहां चंद लोग खा-खाकर मर रहे हैं वहीं बहुत सारे लोग खाने के बगैर मर रहे हैं। यह एक चिंता का विषय है और ऐसे लोगों के प्रति अभिभाषण में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदय, आज आधुनिकता के नाम पर हम अपने संतों और गुरुओं को भी नज़रंदाज करते जा रहे हैं। यहां मैं देश निर्माण में लगे संत शिरोमणि रविदास जी को उद्धृत करना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि,

"ऐसी चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न,

छोटे बड़े सब सम-बसैं, रैदास रहै प्रसन्न।"

महोदय, यह मैं इसलिए उद्धृत कर रहा हूं कि आज हम आधुनिकता के वेग में बह रहे हैं और अपने संतों की बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम संत रविदास की बात को ध्यान दें तो शायद अमीर-गरीब की खाई को पाटा जा सकता है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया है जोकि एक अच्छा कदम है। सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर देश के समस्त 596 जिलों में लागू करने का ऐलान

किया गया है। यह भी एक सराहनीय कदम है, लेकिन केवल सौ दिन के रोजगार से उन लोगों का काम चलने वाला नहीं है। महोदय वर्ष में 365 दिन होते हैं और गरीब का काम सौ दिन से नहीं चल सकता है। इसलिए मेरी राय में दिनों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है क्योंकि हर हाथ को काम और देश के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैय्या कराना सरकार का नैतिक कर्त्तव्य होता है। महोदय, सरकार जन-हित के लिए होती है, जन-कल्याण के लिए होती है, लाभ-हानि के लिए नहीं होती है।

महोदय, सर्व-शिक्षा अभियान को सार्वभौमिक मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम द्वारा और सुदृढ़ किया गया है। मेरी राय में गरीबों के बच्चों को यह लॉली पॉप देने के समान है। जहां एक तरफ इस देश में कुछ लोगों के बच्चे ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर खाते-खाते ऊब जाते हैं.. वहीं दूसरी तरफ मध्याह्न भोजन में चल रही तुच्छ व्यवस्था से गरीबों के बच्चों का काम नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कोई कारगर व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, कदम उठाना चाहिए ताकि गरीबों के बच्चों को भी भरपेट भोजन उनके घर पर मुहैया हो सके, जिससे सर्वशिक्षा का यह अभियान सार्थक हो सके, सफल हो सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सरकार का एक अच्छा कदम है, किन्तु इसे और व्यापक बनाने की जरूरत है ताकि अगर हर गरीब को यह सरकार रोटी नहीं दे पा रही है, तो कम से कम दवा की एक गोली तो जरूर उपलब्ध करा सके।

महोदय, खेतिहर किसानों के प्रति अभिभाषण में चिंता व्यक्त की गई। यह एक अच्छी बात है, किन्तु भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के विषय में कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई है, जिनकी हालत इस देश में काफी दयनीय है और जिनकी संख्या देश में लगभग 20 से 25 प्रतिशत है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या ज्यादा है। ये भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो हैं, सामंतों की जुल्म-ज्यादती के कारण गांवों से पलायन करते हैं और केवल रोटी पाने के लिए गांवों को छोड़कर शहरों और कसबों में जाकर सड़कों के किनारे, रेल पटरियों के किनारे, गंदे नालों के किनारे बसने का काम करते हैं। यहां ये लोग अपने श्रम को बिना किसी शर्त पर बेचकर अपनी आजीविका चलाने का काम करते हैं। ऐसे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की ओर अभिभाषण में ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदय, जो ऐसे भूमिहीन खेतिहर मजदूर शहरों में जाकर बसते हैं, शहरों के सौन्दर्यीकरण के नाम पर इन्हें उजाड़ने का भी काम होता है और यहां तक कि कभी-कभी इनकी झोपड़ियों में भी आग लगा दी जाती है। इतना ही नहीं, आज तो महाराष्ट्र में कानून को हाथ में लेकर ऐसे ही लोगों को खदेड़ने का काम वहां किया जा रहा है, जो एक चिंताजनक विषय है। इस अभिभाषण में ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो के सशक्तीकरण पर अत्याधिक जोर लगाया जा रहा है, जिसकी चर्चा अभिभाषण में पैरा 13 में की गई है कि अनुसूचित जाति के 30 लाख बच्चों के लिए 900 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के 10 लाख बच्चों के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह एक अच्छी बात है, किन्तु पिछड़ी जातियों की संख्या जो देश में 52 प्रतिशत है, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी अभिभाषण में चर्चा नहीं हुई है। इसी संदर्भ में मैं एक हवाला देना चाहता हूँ कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू में हजारों बच्चों की वर्ष 2006-07 की छात्रवृत्तियां नहीं दी गई हैं, उन्हें लौटा दिया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उन हजारों बच्चों, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू के है, जिनको छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया है, उसकी जांच कराकर उनकी छात्रवृत्तियां उनको दिलाने का काम किया जाय और जिसकी वजह से यह छात्रवृत्ति लौटाई गई, उस दोषी अधिकारी को दंडित करने का काम भी किया जाए।

महोदय, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जो बनाया गया है, यह एक अच्छा कदम है, किन्तु महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, श्रीमती रेणुका चौधरी के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के 43 प्रतिशत बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं और प्रति हजार 76 बच्चों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, यह देश के बच्चो

का हाल है। यह भारत की एक दयनीय स्थिति है और इसे रोकने के लिए सरकार को कारगर उपाय करने की जरूरत है। अभिभाषण में इस पर भी दृष्टि नहीं गई है।

(उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी०जे० कुरियन) पीठासीन हुए)

महोदय, इतना ही नहीं, हम लोग महानगरों में रहते हैं और चौराहे पर जब लाल बत्ती जलने लगती है, तो गाड़ी खड़ी होने पर अधनंगा बच्चा, मैला-कुचैला बच्चा, भले ही वह स्वयं मैला-कुचैला कपड़ा पहने हो, लेकिन वह अपने हाथ में एक साफ कपड़ा बचाए रखता है और उस साफ कपड़े से दौड़कर गाड़ी को साफ करने का काम करता है, लेकिन ऐसे नौनिहालों के प्रति अभिभाषण में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहां तक कि बंधुआ बाल मजदूरों को मुक्ति दिलाने के प्रयास की ओर भी अभिभाषण में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय श्री जनेश्वर मिश्र जी आज यहां पर नहीं हैं, न उनकी पार्टी के लोग ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं श्री जनेश्वर मिश्र जी का स्वागत करता हूं कि ब्राह्मण परिवार मे पैदा होने पर भी वे इंसान और इंसानियत की बात करते हैं। आज जातिवाद देश में भयावह रूप धारण कर चुका है, किन्तु अभिभाषण में इस बात की चर्चा नहीं की गई है।

मैं इस सदन में अपने देश में पैदा हुए संतों, गुरुओं और महापुरुषों को उद्धृत करना चाहता हूं। महोदय, आज 2,500 वर्ष पहले इसी भारत की धरती पर तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। उन्होंने उस समय इस देश में व्याप्त सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए और समता मूलक समाज बनाने के लिए नारा लगाया था, किन्तु कतिपय कारणों से भारत देश में गौतम बुद्ध का संदेश नहीं पनप सका, सारी दुनिया के दूसरे देशों में गौतम बुद्ध का संदेश गया। गौतम बुद्ध का संदेश जापान में जाने के कारण, इंसान और इंसानियत वहां पैदा होने के कारण, जापान जैसा छोटा देश आज दुनिया की ताकत बना हुआ है, लेकिन हमारा भारत देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए भी, गौतम बुद्ध के भाइचारे के संदेश को, इंसानियत और मानवता के संदेश को एडॉप्ट न करने के कारण आज जापान जैसे छोटे देश के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। महोदय, 14वीं शताब्दी में संत शिरोमणी श्री रविदास जी पैदा हुए थे, उन्होंने साहस भरे शब्दों में कहा था

रविदास जनम के कारणे होत न कोई नीच
नर को नीच कर डारी है, ओछे करम की कीच।

जातिवाद पर संत शिरोमणि रैदास ने आगे और कहा है —

"जात-पात के फेर में उलझ रहे सब लोग।
मनुष्यता खात रहे, रैदास जात का रोग।।"

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जाति-विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य की कल्पना करना भी निरर्थक है। इसी बात को मान्यवर कांशीराम ने आगे बढ़ाते हुए अभियान चलाया था, उन्होंने मंच से नारा लगाया - जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। मुझे इस देश की मीडिया पर फख्र है कि इस देश की मीडिया के लोगों ने जो कांशीराम, मायावती जी ने जाति तोड़ो, समाज जोड़ो का नारा मंच से लगाया, उनको इस देश की मीडिया ने जातिवादी घोषित किया और जिन्होंने इस देश में जातिवाद पैदा किया, उनको समाजवादी की संज्ञा दी। मेरी राय में आज आतंकवाद और नक्सलवाद, यह सब जातिवाद का ही प्रतिफल है।

महोदय, आज मैं देश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने संतों, गुरुओं और महापुरुषों से सबक लेकर, उनकी बात को आगे बढ़ाया और बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। कभी गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर हम सब का भला न कर सकें, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था - 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'। मैं अपनी नेता

बहन मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेकर, अन्य संतों और महापुरुषों की बातों को आगे बढ़ाने के लिए आज जो देश की जरूरत है, जन-जन की जरूरत है, आज वह अभियान उन्होंने चला दिया है कि देश को आज बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय नहीं, बल्कि सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की जरूरत है।

महोदय, आरक्षण की चर्चा आई है। माननीय राजनाथ सिंह जी अभी यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके दल के लोग यहां बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि श्री राजनाथ सिंह जी ने कल कहा कि धर्म और मज़हब के नाम पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं उनसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, उनके दल के लोगों से सीधा सवाल करना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि देश के अनुसूचित जाति के लोग किसी धर्म और मज़हब के मानने वाले हैं या नहीं? अगर हैं, तो उनको आरक्षण किस आधार पर दिया गया है? माननीय राजनाथ जी को मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपके हिंदू धर्म की कुव्यवस्था के शिकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, जो सामाजिक और शैक्षणिक धारा से वंचित रहे, उनको मुख्य धारा में, सामाजिक और शैक्षणिक धारा में पुनः लाने की कोशिश का नाम ही आरक्षण है। इसलिए आज जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, मुख्य धारा से अलग हुए लोग हैं, उनको आरक्षण देना न्यायसंगत है ....(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, माननीय गांधी आज़ाद जी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी के दल के लोगों से वे सीधा पूछना चाहते हैं .... (**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): You can reply to it when your turn comes. ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनार ण पाणि : मैं सीधा नहीं पूछना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस्लाम में, क्या ईसाई धर्म में जाति-व्यवस्था है?

श्री शाहि सिद्दिकी : हिंदुस्तान में जो आ गया, वह जाति के रंग में रंग गया। यहां जाति ऐसी है कि वह सबको खा जाती है .... (**व्यवधान**)...

†[شری شاہد صدیقی : ہندوستان میں جو آگیا، وہ جاتی کے رنگ میں رنگ گیا۔ یہاں جاتی ایسی ہے کہ وہ سب کو کھاجاتی ہے ۔۔مداخلت۔۔]†

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, 1993 की.... (**व्यवधान**) Don't try to teach us ... *(Interruptions)*... Don't try to teach us ... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Pany, please sit down. *(Interruptions)* Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री शाहिद सिद्दिकी : आप कभी धर्म पर जा रहे हैं, कभी राजनीति पर जा रहे हैं, उसको छोड़िए, देश की बात कीजिए ... (**व्यवधान**)...

†[شری شاہد صدیقی : آپ کبھی دھرم پر جارہے ہیں، کبھی راجنیتی پر جارہے ہیں، اس کو چھوڑئے، دیش کی بات کیجئے ۔۔مداخلت۔۔]†

श्री रुद्रनारायण पाणि : देश की बात सबसे ज्यादा हम ही करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात हमसे ज्यादा कोई नहीं करता है ..(**व्यवधान**)... ।

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Pany, please keep quiet.

श्री गांधी आज़ाद : पाणि जी, जरा धैर्य रखिए, मैं सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, सच सुनने की हिम्मत

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

रखिए। सामाजिक धारा से पिछड़े हुए लोगों को बराबरी में आरक्षण देना न्यायसंगत है, इसीलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को आरक्षण देना भी न्यायसंगत है। इतना ही नहीं, मैं अपने नेता बहन कुमारी मायावती जी को बधाई देना चाहता हूँ, जो मंच से ऐलान करती हैं कि जो दलि. . धार्मिक रूप से अगर अपना धर्म परिवर्तन करके इसाई और मुस्लिम या चाहे जिस धर्म में चले गए हों, बुद्धिस्ट बन गए हों, उनको भी आरक्षण देना न्यासंगत है। इतना ही नहीं, मैं अपनी नेता को पुनः बधाई देना चाहता हूँ कि देश के सवर्ण समाज के भी जो गरीब लोग हैं, उनको भी आरक्षण देने की हमारी नेता ने केवल वकालत ही नहीं, बल्कि देश के प्रधान मंत्री को लिख करके भी दिया है कि उनके लिए यानी देश के सवर्ण लोगों को भी आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। अगर इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत है तो संवि.ान में संशोधन करके विधेयक लाया जाए, बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करेगी।

महोदय, माननीय राजनाथ सिंह जी नहीं हैं, मैं उनके राम की आस्था पर बोलना चाहता हूँ। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी के राम की आस्था पर प्रश्नचिह्न तो नहीं लगाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वे और उनकी पार्टी क्या सचमुच राम के प्रति आस्था रखती है या केवल राम का नाम ले करके राम के आस्थावान भक्तों को धोखा देने का काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि छः साल तक यहां सरकार चलाने वाले, राम के नाम पर सरकार बनाने वाले लोग, जो बार-बार कहते हैं, आज भी कहते हैं कि श्राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगेछ, आज भी कहते हैं, श्राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगेछ, यह धोखा नहीं तो और क्या है? यह धोखा नहीं तो और क्या है?

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज राम मंदिर और राम सेतु बनने से पहले देश के करोड़ों राम भक्तों के रहने की व्यवस्था करने की जरूरत है। मैं सदन के इधर और उधर, दोनों पक्षों से कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर और राम सेतु बनने से पहले देश के करोड़ों राम भक्तों, जिनके पास झोपड़ी भी मयस्सर नहीं है, के रहने की व्यवस्था और इंतजाम करने की जरूरत है, यह नैतिकता का तकाजा है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, now please conclude.

श्री गांधी आजाद : महोदय, मैं एक-दो मिनट में समाप्त करता हूँ। श्री राजनाथ सिंह जी ने गांधी के राम राज की कल्पना किया था, बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि राम राज न होता तो गांधी जी कई बार राम-राम किए ... मैं उनकी बात को मानता हूं, उसको उन्होंने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, दोनों पक्षों से कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर सचमुच राम राज्य की बहाली करना चाहते हैं, इस सदन के माध्यम से मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर सचमुच राम राज्य चाहते हैं, तो इस देश में जब भारत के संविधान के शिल्पकार डॉ.अम्बेडकर के सपनों का भारत और कांशीराम के सपनों का भारत होगा, तभी राम राज्य हासिल हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुनः अभिभाषण का स्वागत करते हुए एवं महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं, धन्यवाद।

श्री मनोहर जोशी (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार सदन में एक महिला राष्ट्रपति का भाषण सम्पन्न हुआ, इस बात की मुझे खुशी है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि वह महिला महाराष्ट्र की है, मराठी है। यहां के सब भाषण मैं बहुत ही ध्यान से सुन रहा हूं और इसीलिए जब मैं अपना वक्तव्य कहूंगा तो आपने अपने भाषण में जो कुछ कहा है, उसका आधार लेकर ही बोलना चाहूंगा।

सर, एक बात सच है कि इस डिबेट की शुरुआत माननीय जनार्दन द्विवेदी ने की। मैं द्विवेदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सब लोगों का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित किया, लेकिन

यह बात सच है कि द्विवेदी जी के भाषण के बाद मैं सोचता था कि सदन में इस विषय पर बहुत गंभीरता से चर्चा होगी, लेकिन चर्चा हुई नहीं। द्विवेदी जी ने अपने भाषण के अंत में कहा था कि राष्ट्रपति के भाषण में एक विषय का उल्लेख नहीं है और वह विषय था कि आज की राजनीति दूषित हो रही है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि राजनेताओं की तरफ लोग सम्मान से नहीं देखते हैं और इसके कारण लोगों के मन में राजनीति करने वालों के बारे में प्रतिमा अच्छी नहीं है। मैं यह सोचता था कि शायद यहां जब डिबेट चल रही है, तो इस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी और सर, आप तो जानते हैं कि यह विषय बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। राजनीति में कितने क्रिमिनल्स हैं, लोक सभा और राज्य सभा में भी ऐसे लोग चुनकर आते हैं। इनकी प्रतिमा खराब होने के कारण और दूसरे अनेक कारण हैं, जिन कारणों से लोगों के मन में राजनीति की प्रतिमा बहुत ही दूषित हो रही है। मैं इतना ही कहूंगा कि राजनीति में काम करने वाले लोग यदि चाहते हैं कि हमारी प्रतिमा अच्छी रहे तो स्वयं से शुरुआत करने की आवश्यकता है। जब तक, जो लोग राजनीति में हैं, वे खुद की प्रतिमा सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि उनके बारे में लोगों का मत अच्छा होगा। जब मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं, चुनकर आए हुए सांसदों या विधायकों की बात कर रहा हूं, तो मैं यह भी कहूंगा कि सदन में हमारा बर्ताव बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण रहना चाहिए। मैं यह नहीं कहूंगा कि हर समय ऐसा होता है लेकिन कभी-कभी घर के बच्चे भी अपने पिता से पूछते हैं कि सदन में इतनी गड़बड़ी क्यों होती है। द्विवेदी जी के मत से मैं बिल्कुल सहमत हूं और मैं यही चाहूंगा कि सदन अच्छे तरीके से चले, पूरा दिन चले। जैसे राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा होती है, ऐसी ही चर्चा हर विषय पर होनी चाहिए। इससे हम लोग इस विषय की शुरुआत कर सकते हैं। मुझे दूसरा भाषण जो बहुत अच्छा लगा, वह जनेश्वर मिश्र जी का भाषण था। मैंने कल उनका भाषण सुना था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी बहुत अच्छा भाषण किया था। अनेक मुद्दों पर उन्होंने अपने पक्ष की भूमिका रखी और उसके साथ-साथ सरकार के दोष भी गिनाए। अरुण जेटली जी का जो भाषण था, वह बहुत विद्वतापूर्ण था। वह भाषण भी सुनने का मुझे मौका मिला। लेकिन सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री जनेश्वर मिश्र जी के भाषण से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने मुम्बई की घटना पर अपने भाषण में जिस शांति और सभ्यता का परिचय दिया, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनके भाषण की सराहना करता हूं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुम्बई में जो घटना घटी, उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ जो घटना हुई, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, देश के संविधान का सम्मान करना चाहिए और मैं यह बात बालासाहेब ठाकरे जी से कहूं और बालासाहेब ठाकरे जी अपने भतीजे को कहें कि ऐसी बात न करे जिसके कारण देश को खतरा हो और जो भाषण संयम से होगा तो इस देश में होने वाली बहुत गड़बड़ियां नहीं होंगी और इसीलिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और उनकी पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनकी इच्छा के अनुसार उनकी भूमिका मैं अपनी पार्टी के प्रमुख तक जरूर पहुंचाऊंगा।

सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मुम्बई की घटना के बारे में कुछ नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं, पहला यह कि राष्ट्रपति जी ने नहीं सोचा होगा कि मुम्बई की घटना कोई बहुत बड़ी हुई हो और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उनके पास केबिनेट के माध्यम से जो भाषण जाता है तो शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इसमें मुम्बई का मुद्दा आने की आवश्यकता है। 28 जनवरी, 2008 को राज ठाकरे जी ने भाषण दिया। शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं बताऊंगा कि राजठाकरे इससे पहले शिव सेना में थे, अब उन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी बनाई है और उनकी पार्टी का काम शुरू है। 28 जनवरी, 2008 के भाषण में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में केवल महाराष्ट्र दिन -महाराष्ट्र डे हो तथा महाराष्ट्र में दूसरे किसी भी स्टेट का दिन नहीं मनाना चाहिए, यह उन्होंने कहा था। यह कह कर वे रुके नहीं, उन्होंने आगे चलकर अमिताभ बच्चन जी के बारे में भी कहा और उन्होंने यही कहा कि अमिताभ बच्चन जी सुपर स्टार हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं, उनका महाराष्ट्र में ही घर है। जब चुनावों की बात होती है कि तो वे उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव में खड़े रहते हैं तथा वह महाराष्ट्र में खड़े क्यों नहीं रहते। ब्रांड अम्बेस्डर बनना है तो उत्तर प्रदेश के ब्रांड अम्बेस्डर बनते हैं, यही राज ठाकरे का आक्षेप था और इन मुद्दों पर उनका भाषण होने के बाद मुम्बई में गड़बड़ी हुई। शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा या जानबूझकर भी इस विषय पर नहीं बोलते

होंगे, मेरी पार्टी के प्रमुख बाल ठाकरे जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और इस निवेदन में बाला साहब ने कहा था कि अमिताभ बच्चन जी इस देश के बड़े अच्छे एक्टर हैं और अमिताभ बच्चन जी को यह बोलना कि वे महाराष्ट्र के नहीं हैं, यह मूर्खता है, यानी बालासाहेब ठाकरे ने कहा था कि अमिताभ बच्चन जी का सम्मान रखना आवश्यक है और उनका कोई भी अपमान न करे, ऐसी इच्छा भी उन्होंने व्यक्त की थी। इतना सब होने के बाद अमर सिंह जी की मुम्बई में एक प्रेस कांफ्रेंस हुई और उस प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने जो बात की, वह बात राज ठाकरे के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी हैं और उद्धव ठाकरे जी ने पार्टी में बहुत अच्छा काम चलाया है और इसी कारण राज ठाकरे जी उनसे संघर्ष करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने यह विषय उठाया है। उसी प्रेस कांफ्रेस में राज ठाकरे जी के कुछ लोगों ने निषेध किया, और अमर सिंह जी के खिलाफ नारेबाजी की और वह नारेबाजी जब की तभी से यह सब गड़बड़ी शुरू हुई है। सर, मैं यह बैकग्राउंड इसके कारण दे रहा हूं कि मेरी दृष्टि से एक छोटा विषय देश में बहुत बड़ा बन रहा है और उसका कारण लोगों को मालूम होना चाहिए, इसीलिए यह पृष्ठभूमि मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारे इसी सदन के सदस्य अगर यहां उपस्थित होते तो और अच्छा होता। श्री अबू आसिम आज़मी जी ने कहा था कि हम उत्तर भारतीयों के हाथ में लाठी देंगे और कहेंगे कि आप प्रतिकार करो, संघर्ष करो, तो फिर राज ठाकरे जी ने कहा कि आप हाथ में लाठी देंगे, तो मैं भी मराठी लोगों के हाथ में तलवार दूंगा। सर, यह जो भाषणबाजी हुई, इससे मुम्बई में थोड़ी गड़बड़ी हुई । ...**(व्यवधान)**... मैं बताऊंगा कि कितनी गड़बड़ी हुई, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। ....**(व्यवधान)**...

श्री शाहिद सिद्दिकी : इसके लिए अबू आसिम आज़मी जी कैसे जिम्मेदार हैं ? ....**(व्यवधान)**...

†[اس کیلئے ابو عاصم اعظمی جی کیسے ذمہ دار ہیں؟۔مداخلت۔ : شری شاہد صدیقی]

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Siddiqui, let him complete...*(Interruptions)*...Please, no interference...*(Interruptions)*...

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश): सबसे पहले लाठी की बात वहां के जो गृह मंत्री, श्री पाटिल साहब हैं, उन्होंने कही। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You will get your chance. ...*(Interruptions)*... आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप बैठ जाइये। Mr. Joshi, you please proceed.

श्री मनोहर जोशी : सर, मैं यह बात मानता हूं कि पाटिल साहब ने यह बात कही थी और इनकी बात सच है। लेकिन गृह मंत्री ने कहा, तो भी एक पार्टी के जिम्मेदार नेता को ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह आपको भी मानना पड़ेगा। शब्द से शब्द बढ़ता है और फिर इस तरह की बातें होती हैं। ...**(व्यवधान)**... सर, छठ पूजा के बारे में बात हुई कि राज ठाकरे जी ने कहा कि मुम्बई में छठ पूजा नहीं होनी चाहिए। सर, बात ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा का नाम लेकर राजनीति करना गलत है, यह उनका खुद का एक दृष्टिकोण है। लेकिन यह जो बात हो गयी, उस बात के बाद भी छठ पूजा में हम लोग गए थे, इतना ही नहीं, उत्तर भारतीयों का जो सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में भी हम गये थे। हमारी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी भी गए थे। ...**(व्यवधान)**....यही कारण है कि जड़ क्या होगी, मैं यह जरूर कहूंगा। ...**(व्यवधान)**...

सुश्री मैबल रिवैलो (झारखंड): राज ठाकरे जी, तो आपके चेले हैं। ..**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : You don't reply to that. Why do you reply to that?...*(Interruptions)*...Please take your seat. You make your speech. You are very smoothly presenting your view-point.

श्री मनोहर जोशी : मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे मित्रों को जरूर जवाब दूंगा। ...**(व्यवधान)**....

---

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): सर, मैं बिहार से आता हूं। हम लोग छठ पूजा को बहुत आदर से मनाते हैं, महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ पूजा बहुत ही समर्पण का त्योहार है, लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं और छठ पूजा को इस कम्पटिशन की राजनीति का अंग अगर हम नहीं बनायें, तो बड़ी कृपा होगी। उसमें आस्था और धार्मिक भावना निहित है। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Mr. Joshi, beware your time is being taken away by others.

श्री मनोहर जोशी : सर, उनका टाइम आप मुझे देंगे। ...(व्यवधान)... इसीलिए मैं कहता था कि राज ठाकरे जी ने छठ पूजा का विरोध किया, तो लोगों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। जैसा कि मैंने पेपर में पढ़ा, उन्होंने छठ पूजा का विरोध नहीं किया था। उसके पहले भी जब छठ पूजा होती थी, तो छठ पूजा में उद्धव ठाकरे जी खुद गए हैं, यह मुझे मालूम है। इसलिए आप जैसा कहते हैं, वैसी भावना छठ पूजा के बारे में हमारे लोगों में नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : उसके बारे में लालू जी ने जो कहा, वह भी ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री मनोहर जोशी : सर, अब मैं लालू जी पर भी आता हूं। बात को ठीक तरह से समझने की आवश्कता है। सर, इतनी छोटी सी घटना का इतना बड़ा होने का एक कारण यह भी है कि इस घटना को बहुत पब्लिसिटी मिली। मैं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में देख रहा था। एक घटना हुई, एक टैक्सी ड्राइवर को मारा, थोड़ा-सा पीटा और थोड़ा-सा उसको पीटने के बाद बार-बार यह घटना दिखाई जाती थी और इसीलिए पूरे देश को लगा कि मुम्बई में क्या हो रहा है? सर, मैं जब से यहां आया हूं हर बार मुझे पूछा जाता है कि मुम्बई में क्या हो रहा है, हमारे यहां के मित्र भी मुझे बोलते हैं कि हम मुम्बई में आयेंगे, तो सुरक्षित रहेंगे ? आपको तो मालूम है कि मैं चार-पांच दिन बाद मुम्बई जाता हूं। मैं बार-बार सभी को कहता हूं कि मुम्बई में ऐसी कोई बात नहीं है, मुम्बई में कोई बड़ी बात नहीं हुई है और बड़ी बात नहीं होने के बाद भी जो अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं, उनका यह काम है। जैसा मैंने कहा कि भाषण बाजी, मीडिया का काम और तीसरा यही कि अफवाह उड़ाने वाले लोग ...(व्यवधान)...

श्री राजनीति प्रसाद : एक मरा है, वह भी ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी.जे. कुरियन) : नो प्लीज़।

श्री मनोहर जोशी : शायद इनको यह बात मालूम नहीं है कि जो मरा है, वह मराठी है। ...(व्यवधान)... नहीं, वह औरंगाबाद का नहीं है, वह नासिक का है। ...(व्यवधान)... वह मराठी है और जो पत्थरबाजी हुई, सर, मैं यही बोलता हूं कि गलतफहमी ज्यादा है। सच बात तो यह है कि सच को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं आप से एक दूसरी बात और कहूंगा तो आपको सुनकर अचरज होगा कि इस घटना के बाद केवल दो-तीन दिन में मेरे बिहार के चार मित्र ट्रेन में जा रहे थे ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): जोशी जी, आपका टाइम खत्म होने वाला है। You please try to conclude. ...(व्यवधान)... आपके 18 मिनट्स हो गए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मनोहर जोशी : सर, ऐसा मत कीजिए। ...(व्यवधान)... मुझे थोड़ा तो टाइम दीजिए, नहीं तो गलतफहमी रहने दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं बैठ जाऊंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Don't be disturbed by others. Concentrate on what you want to say.

श्री मनोहर जोशी : सर, बिहार के चार लोगों ने एक मराठी आदमी को उठाया और ट्रेन से फैंक दिया। मैं केवल अफवाह नहीं फैलाना चाहता हूं। यह बात सच है और मेरे पास हर बात की यहां पर प्रैस कटिंग है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। यह करने वाला बिहारी था, इसलिए सब बिहारी खराब हैं, ऐसी बात कभी भी शिव सेना की तरफ से नहीं आई। यह बात और बढ़ने का मैं चौथा कारण यह बताता हूं कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने यह घटना जब से शुरू हुई तब से कुछ नहीं किया। मेरा महाराष्ट्र की

गवर्नमेंट पर आक्षेप है और आरोप है। एक घटना घटती है, उनको मालूम है कि घटना की जो बातें हैं वे पूरे देश में फैलती हैं। इसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कार्यवाही करने में क्या होता? इससे भी ज्यादा अचरज की बात यह है कि दिल्ली सरकार में बताने के बाद भी सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस विषय पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है, तो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कार्यवाही नहीं की, क्यों नहीं की? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जब ये बातें होती हैं तो तब ये सब इकट्ठा करके महाराष्ट्र को दोष देना बिल्कुल गलत है। पूरे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में गुंडागर्दी हो रही है, महाराष्ट्र देश तोड़ रहा है, मैं सब सुन रहा था। लोक सभा में जो चर्चा हुई, वह भी मैंने सुनी। महाराष्ट्र को देश-प्रेम सिखाने की जरूरत नहीं है। इस देश को जितने बड़े नेता महाराष्ट्र ने दिए हैं, शायद ही किसी दूसरे स्टेट ने दिए होंगे। महाराष्ट्र के ऊपर पूरे देश को अभिमान है और महाराष्ट्र एक देश-भक्त स्टेट है। मैं यह भी कहूंगा कि शिव सेना की तरफ से जब कभी कहीं पर भी भाषण दिया जाता है तो भाषण के बाद अंत में कहते हैं कि ज्जय हिन्द, जय महाराष्ट्रछ। इसका मतलब यह है कि पहला सम्मान हिन्दुस्तान का है और बाद में महाराष्ट्र का है और इसलिए संविधान को कोई भी खतरा नहीं है। ऐसा कुछ भी महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। देश का कोई भी आदमी वहां जा सकता है और देख सकता है कि वहां पर क्या होता है और फिर खुद का अपना मत बना सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए इस विषय पर मुझे यहां बोलने की आवश्यकता है। ...(समय की घंटी)...सर, और एक बात कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि 1992-93 में क्या हुआ था? उस समय मुम्बई में बड़े दंगे फसाद हो गए थे। उसमें अनेकों लोग मारे गए और उसमें हिन्दू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग मारे गए। तो यह सब बातें सच नहीं थी कि उस समय वहां पर लोग उत्तर भारत के नहीं थे? मुझे याद है क्योंकि मैं चुनाव के लिए बार-बार खड़ा हुआ था। मैंने यह भी देखा है कि उत्तर भारत के लोगों ने भी हमें मत दिया है, बिहार के लोगों ने भी वोट दिया है। जब वहां पर रक्षा करने का समय आया तो हिन्दुओं के पीछे शिव सेना खड़ी रही। उसने यह नहीं सोचा कि यह बिहारी है, इसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए और उत्तर भारतीयों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। शिव सेना ने बार-बार लोगों के सामने अपनी भूमिका रखी है और इसी भूमिका को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं दूसरी एक ही बात कहूंगा कि जब मैं महाराष्ट्र का मुख्य मंत्री था, तब मैंने एक स्कीम लागू की थी। आप झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की बात कर रहे थे, इसलिए मैं यह कह रहा हूं। मैंने एक स्कीम लागू की थी कि जो-जो आदमी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको फ्री ऑफ चार्ज ऑनरशिप बेसिज पर 225 स्क्वेयर फुट जगह दी जाएगी। अभी तक मेरे पास एक भी कम्पलेंट नहीं आई कि वह दूसरे राज्य का आदमी है और उसको जगह नहीं दी। जो बात कही गई, वह पूरी की गई। जो बात अभी हुई है, वह एकदम छोटी बात है, इसके लिए मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि इसे बढ़ावा देने की कोशिश न करें। इस विषय पर बार-बार चर्चा करना भी ठीक नहीं होगा। अब ऐसी चर्चा नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में जो गलतफहमी हो रही है, वह गलतफहमी दूर हो सकती है। इसके लिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि यह विषय यहां ही बोलना चाहिए। बार-बार चर्चा करने से, विषय बढ़ाने से, हम क्या बोलते हैं और इसका क्या असर समाज पर होता है, यह सोचना चाहिए। मैं सोचता हूं कि सदन के सभी सदस्य यह सुनेंगे, ऐसी मेरी आशा है।

सर, मैं एक विषय पर दो-चार मिनट के लिए बोलना चाहता हूं। यह कर्ज़ माफ़ी का विषय है। कर्ज़ माफ़ी के विषय में अभी जो चल रहा है, वह कर्ज़ माफ़ी करने के बाद भी बहुत गंभीर स्वरूप धारण कर रहा है। कर्ज़ माफ़ी हो गई, पूरी नहीं हुई, सभी को देनी चाहिए, वह ठीक है, लेकिन क्रेडिट लेने की जो स्पर्द्धा शुरू हो गई है, वह बहुत खराब है। हर पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाहती है। मेरे कारण हो गया है, यह कांग्रेस कहती है, एन.सी.पी. कहती है, शिव सेना, बीजेपी कहती है। हमने आंदोलन किया, इसलिए यह बात हो गई। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि यदि सचमुच किसी को क्रेडिट चाहिए होगा तो यही सोचना चाहिए कि सभी किसानों की कर्ज़ माफ़ी करें।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You should also take some credit.

श्री मनोहर जोशी : यह जन हित में होगा, ऐसी मेरी सोच है। सर, मेरे पास अनेक मुद्दे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि समय की मर्यादा है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। महोदय, आपने बोलने का जो मौका दिया

है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर सभी से प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके यह जो मुंबई का विषय है, उसे न बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): आपको ज्यादा टाइम देने की मेरी भी इच्छा थी, लेकिन मैं क्या करूं, बहुत स्पीकर्स हैं। डा. पी.सी. अलेक्जैंडर।

DR. P.C.ALEXANDER (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussions on the Motion of Thanks to the President's Address. I am conscious of the fact that this is the last opportunity for me to participate in a discussion the President's Address because in a very short time I will be completing my tenure in this House.

I mention this because I would like to raise a few basic issues regarding the functioning of our democracy and share with you some of my concerns about the directions that our democracy has taken in recent years. I will be basing my speech mainly on the observations made by the President in her speech on three points. And my fourth point will be on a conspicuous omission that I wish to point out in the President's Speech.

My first point, Sir, is concerning the last paragraph of the President's Speech which gives a ringing exhortation to the people of this country about the functioning of democracy in our country. I quote this sentence. It is a very inspiring sentence. It says, "Therefore, what you say and do in these hallowed portals of democracy will have a bearing not just on the destiny of our people, but also on the future of democracy and free societies around the world."

Sir, the question that I wish to raise before the hon. House is this. Is this assumption about the health of our democracy really justifiable? We are implementing the parliamentary system of democracy for the last 60 years. The foundations for this system were truly laid by the greatest democrat of that time, not the greatest democrat of India, but the greatest democrat of that time, Pandit Jawaharlal Nehru. By the time he finished his 18 years of stewardship of the State, people had begun to feel confident that our democracy was on proper lines. But if we now look at the direction our democracy has taken and the manner in which it is functioning in our country, I feel genuinely concerned whether we will last as a democracy for a long time. The basic principle of Parliamentary democracy is that it has to be founded on a sound and healthy party system. Some other systems of Government can be practised without reference to political parties, but the Parliamentary system can function only if you have a good, healthy and sound party system in the country. Let us ask ourselves this question honestly. Do we have a good party system in this country? At any rate taking into account the manner in which parties are functioning today, can we call that really healthy? Or, have we distorted the basic concepts of democracy in the working of our parties? How can we think of having a healthy democracy at the Government level, if at the party level we do not practise democracy? It is unthinkable because it is a contradiction to have democracy being implemented by political parties which do not practise democracy within the parties. I am concerned, Sir, at the trend that has set in today, by which parties are run without any elections. The people seem to have forgotten that the functionaries of the parties have to be elected according to the will of the party members. But we have converted elections into nominations. And, the culture that is prevailing in most political parties, with the exception of three, or, four, which I do not want to name today, is the nomination culture masquerading as elections. It is all settled somewhere as to who is to be the President of the State party, who is to be the convenor of this, or, the chairman of that, and, then, there are supposed to have been approved by the people through elections. This will eat into the

vitals of the political system in our country. After some time, a whole generation will grow up thinking that this is how party system should be done, and, then, our democracy will get completely devalued. Sir, this is a warning signal that I am raising, after deep study and full sense of responsibility. When the Freedom House conducted a survey of 193 countries of the world, they listed only 90 countries as democracy; they had listed 60 countries as partly democratic and the rest has non democratic. India has been included in the 90 countries. But if the present trend, continues for some more years, of dispensing with elections at the party level, depending entirely on nominations, we will very soon get into the category of partly-democratic countries. And, God knows what will happen then. The way the Parties are being run by individuals would really be a matter of envy for the great dictators of the world . That generation dictators has gone. They also called themselves democratic and we looked at them with contempt; but this is the way our Parties are being run today. Certain individuals run the parties as it God has given them the wisdom and the right to do so and we call that democracy. If we continue this trend, we will not be justified in claiming that the world outside will be looking to us for inspiration and our democracy will be having greater lustre and eminence.

The second point connected with the future of democracy I wish to flag on this occasion is the devaluation of the institutions of democracy. Sir, how many minutes are given to me?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Fifteen minutes.

DR. P.C. ALEXANDER: Thank you, Sir. I don't have the time to refer to devaluation of all the institutions of democracy. But let me take the devaluation of the institution to which we all belong, namely of the institution of legislature. Sir, among all the institutions of democracy, namely, legislature, executive, Civil Service, Judiciary for forces and non-political military service, the most important is the one in which we are members, the legislature. Can we honestly say, Sir, that the legislatures in our country at the central level and at the State level are being run in the manner in which the legislatures should be run?

Sir, I came to this House six years ago. Looking around the Benches, I could see some of the brilliant parliamentarians, some very brilliant minds in this House and I always used to tell my friends that the Rajya Sabha is very rich in talents. On this side and that side and in the back Benches of the nominated Members, we find men of outstanding talents. But do you give them a chance to participate in debates, to contribute to the working of democracy in this hallowed institution? Do we find even the most talented people being able to make their contribution effectively in the legislature? Do we discuss the problems which should be really worrying us almost day-to-day as the custodians of democracy in this country. Take some of these problems. Farmers are committing suicide, not in hundreds but in thousands. The Rural Employment Guarantee Scheme is supposed to be the star scheme and I agree it has to be the star scheme for fighting poverty. There are issues like the corruption in this country, the all-pervasive corruption that is eating into the vitals of our nation. Do we get the time to discuss any of these issues in depth ? The only debate that I can recall, which has been seriously conducted in this House both by the Opposition and by the Government and which will stand out as one of the best debates this House has witnessed in the past six years that I know of , was the debate on the 'Indo-US Nuclear Cooperation.' But what about the other subjects which are of equal importance to us? Why are we not spending days to consider them, discuss them and why are we not giving freedom to the Government Benches to express their views during those discussions? No voting is involved, but still a whip is

indirectly given to them not to oppose Government policies, most unlike the working of democratic institutions in western countries. We really have to revise the way we conduct our own business in this House. Otherwise, this institution will get devalued and become a subject of ridicule.

Sir, let me raise another warning signal. The problems, which should be worrying us, causing us sleepless nights, seem to be completely forgotten and we try to build up our dreams and to live in a dream world of our own. We go about telling the people that in twenty years' time or now in twelve years' time, India is going to be one of the developed countries of the world. By merely making *bhasans* to people who are not aware of facts and figures that by 2020 India will join the ranks of the most developed countries of the world, we are deceiving them and we are deceiving ourselves. It is because as I see the situation today, most unlikely, we will — and I say again with full sense of confidence and with all humility — reach most unlikely the levels of the developed countries of the world even in a hundred years. Sir, the United Nations Development Programme Report is very significant. They have put us down at the 128th rank in the countries of the world from the point of view of human development based on income, literacy or education and healthcare. Our per capita income is one-tenth that of the developed countries. The UNDP Report says that even if the developed countries do not add one dollar to their income and remain static and India tries to reach that level, it will take one hundred years to reach that level. When that is the reality and when we have to face that problem with that reality in mind, we go on telling people that within 12 or 20 years from now, we are going to enter into the ranks of the developed countries of the world. Selling dreams is easy, Sir. You can win votes for five years but you cannot be doing this every fifth year because you will get into trouble. Once the disillusioned masses feel the winds of change and feel the winds of what is happening in the country, the distortions in the distribution of wealth, they are not going to keep quiet. And then our democracy itself would face new problems which may be dangerous for its very existence.

I now come to strategies for development. Since the time is limited, I would refer to only the main strategy that should be relied upon, that is, the Rural Employment Guarantee Act. I have great faith in this Act; I have great faith in this scheme. Mr. Manohar Joshi was Chief Minister of Maharashtra when I was the Governor of the State. During the ten years that I was Governor of Maharashtra, the State had contributed so much to the reduction of unemployment in rural areas that they had practically snubbed the edge of poverty, the de-humanising poverty in certain rural areas of the country. The Employment Guarantee Scheme, according to the President, is expected to soften the sharp edges of poverty and offer basic livelihood and security. Sir, the way we have started does not give me any hope; if this scheme is implemented, We may spend Rs. 20,000 crores, but the number of households helped, the number of unemployed people assisted, will be much less than what we have ever bargained for. I will give you one piece of statistics which should make us think about the direction in which this scheme has been proceeding. It has been seen from the report published by the Ministry that during the year 2006-2007, 2.10 crores of households have benefited by the Employment Guarantee Scheme. I request the House to note these figures carefully. According to the published report of the Ministry of Rural Development during the year 2006-07, 2.10 crores of households have benefited from the scheme. But if you go deep into the report — not that report but other reports published by the same Ministry — you will find that, in the same year, when you claimed that 2.10 crores of households have benefited, actually, only 37 days was the average number of days when employment was provided. While 100 days' employment has been provided for in the Act, only 37 days of

average employment had been provided during this period. Where are the 100 days? Where are the 2.10 crores of households said to have benefited by the scheme? Not only that, only 7.59 lakhs of households out of the 2.10 crores of beneficary had received 100 days of employment. This is a dismal story. This is not the way that this scheme should have started. If we go at this rate, people would lose confidence in that. And, therefore, it is time that a Parliamentary Committee is appointed to give a new direction to this scheme and to ensure that the hopes and aspirations of those who introduced this scheme are really fulfilled on proper lines on which this scheme was expected to be implemented.

One simple point that I will mention as a success story in Maharashtra. They gave practically complete flexibility to the local bodies and to the local officers to decide about entitlement and the type of employment to be given and one direction they gave was that they can link the Rural Employment Scheme with Horticulture Development Scheme. It was a wonderful decision. The result was, Maharashtra which had hardly 173 thousand hectares of horticulture in 9 or 10 years, from 1990 to 2000, because of the linkage of the Employment Guarantee Scheme with the Horticulture Development Scheme, the number of hectares under employment cultivation increased from 117 thousand to 971 thousand hectares and women were the greatest beneficiaries. Instead of asking them to dig mud and carry heavy loads on their starved heads and bodies, they were doing cultivation, which they like even without assistance, of fruits and vegetables and they earn much more than they could. Like that, we could give direction and there should be some special committee of the Parliament to give direction. Otherwise, this ambitious scheme can go waste. Sir, I now come to the most important point that I wish to make and that is with regard to some of the real sad problems of our nation which seem to have escaped our attention and concern. We speak of poverty, but the type of poverty that our people have is what Arjun Sengupta has brought out in his Report. I do not know whether he is present here. It is a very useful and valuable Report on the unorganised sector in our country and we got that astonishing figure that 79 per cent of 395 million workers in the unorganised sector are living with Rs.20 a day or less. To keep a cat in our house or to keep a dog in our house, we have to spend, at least, Rs.300 or Rs.400 a month, and here we are keeping our own workers, our own flesh and blood, calling them workers in the unorganised sector, and allowing them to live within Rs.18 or Rs.20 a day. Arjun Sengupta Report has not even been brought before this House. I wonder why it is not being discussed in this House. Such a Report should have got top priority over many other reports and should have been discussed here. But we have not done it. These are the points that arise from the Speech. There is my last point and that is an omission in the Speech. I do not, Sir, why there was no mention of it in the Speech. When all other matters have been discussed and when a whole catalogue of scheme has been introduced or referred to, why we — those who drafted the Speech — have not advised the President to say a paragraph on all pervasive corruption that has destroyed all development schemes as is threatening to put us back to where we were even 10 years earlier. Sir, to speak about corruption is to invite criticism because people say that they have heard the story before or they will say put your search light inside and see whether your civil servants are not corrupt or more corrupt than we politicians. Whatever we may say, Sir, the unfortunate situation today is that civil servants, and that to senior civil servants, politicians, educationists, and even those who control the temples, mosques and churches are also indulging in corruption. And, this corruption is so prevalent that we are all tolerating it as if nothing is of consequence in this land of Mahatma Gandhi. It is not only a tragedy but it is a crime. The greatest man ever born in this

world in the 20th Century, Mahatma Gandhi, is great not because he gave us freedom, others have given freedom to their countries; not because he showed us a new way of attaining freedom, others have followed different course; the greatest claim for his greatness as Mahatma is cleanliness in public life, absolute, impeccable, unquestionable integrity. In his land, if we have descended to this level of corruption, no amount of praise for the development schemes will be of any avail. Therefore, this has been a conspicuous omission in the speech. With these words, I conclude my speech.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri Ali Anwar.

श्रीमती जया बच्चन : सर, एक मिनट। जोशी जी जा रहे हैं, I have just heard his speech and he has made certain comments about Maharashtra, and I would like to say, because it is going to be recorded, that the entire version of his has not reflected exactly what has happened.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can say about it when your chance comes. Now, Shri Ali Anwar.

श्री अली अनवर (बिहार) : शुक्रिया, महोदय। यह अजीब इतफाक है कि जब आप वहां होते हैं, तभी हमारा नंबर यहां आता है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): But, I will not give you more time.

श्री अली अनवर : महोदय, इसी तरह से हमारी मेडेन स्पीच हुई थी। जोशी साहब चले गए। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि पहली दफा हम लोग मैडम प्रेसिडेंट की स्पीच पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर बहस कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि मैडम प्रेसिडेंट उन्हीं के सूबे महाराष्ट्र की हैं। हम लोगों को भी इस बात पर खुशी है, पूरे देश को खुशी है, लेकिन जब हम लोग उनकी स्पीच को सेंट्रल हॉल में बैठकर सुन रहे थे, तो एक बात मन को कचोट रही थी कि आज देश की एकता और अखंडता को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उस खतरे की आवाज खुद महाराष्ट्र से आ रही है, असम से आ रही है, वहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग और दूसरे सूबे के लोगों को मारा-पीटा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है। यह केवल उत्तर भारतीयों की पीड़ा का सवाल नहीं है, यह पूरे देश का मामला है और उसकी ध्वनि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहीं भी, एक वाक्य में भी नहीं सुनाई पड़ती है।

महोदय, जितने हल्के ढंग से माननीय जोशी जी ने इस के सवाल को लिया है, मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, जो असम में लगातार घटनाएं हो रही हैं, वे एक बड़ी बीमारी का लक्षण है और यह बीमारी फैल सकती है, आगे उत्तर प्रदेश में हो सकती है, बिहार में हो सकती है, बंगाल में हो सकती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के किसी राज्य में हो सकती है। इससे पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए इस मामले को इतने हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि जिन दिनों यह वारदात वहां हो रही थी, उन दिनों मैं वहीं महाराष्ट्र मुंबई में था। दो-दो कमिटियां वहां गई थीं, संयोग से मैं दोनों कमिटियों का मैम्बर था और दो दिन एक कमिटी के मैम्बर के नाते और दो दिन दूसरी कमिटी के मैम्बर के नाते, चार दिन मैं वहां रहा और वहां के हालात को देखा। वहां के बुद्धिजीवियों से बात की, वहां के ड्राइवर से बात की, होटल में वहां जो दूसरी जगह के लोग ठहरे थे, उनसे बात की, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बात की। लोगों ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि पंजाब के अंदर किसी जमाने में जिस तरह का *भस्मासुर* पैदा किया गया था, उसी तरह का *भस्मासुर* महाराष्ट्र में भी पैदा करने की कोशिश हो रही है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं बताऊंगा, आज़मी साहब, कौन कर रहा है, आपका भी हम जिक्र करेंगे। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह वहां के लोग कह रहे थे, वहां के लोग, वहां के बुद्धिजीवी, वहां के सियासी मामलों के जानकार और पत्रकार कह रहे थे कि एक पार्टी का inner conflict था और बाला साहब ठाकरे को नीचा दिखाने के लिए, उनकी ताकत को कम दिखाने के लिए, एक दूसरे शख्स को, जिसकी औकात बहुत कम थी, उसको बढ़ाने की कोशिश एक सियासी पार्टी कर रही है।

पंजाब में भी ऐसा किया गया था और उसके बाद नतीजा क्या हुआ, कितनी बड़ी कीमत इस देश को चुकानी पड़ी। *फिर वही बेतलवा डाल पर*, फिर वही हश्र हो रहा है। अभी जोशी साहब ने और दूसरे लोगों ने कहा कि लाठी बांटने की बात होती है, फिर तलवार बांटने की बात होती है, मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों तरह की बातें गलत हैं, लाठी बांटने की बात भी गलत है और तलवार बांटने की बात भी गलत है। मैं उससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि लाठी बांटने की बात करने वाले लोग और तलवार बांटने की बात करने वाले लोग किसी होटल में मिलते हैं रात के अंधेरे में, यह तय करके कि तुम्हारे गरम बात बोलने से हमारी सियासत चमकेगी और हमारे गरम बात बोलने से तुम्हारी राजनीति परवान चढ़ेगी। ...(**व्यवधान**)... इस तरह की भी बात करते हैं। ...(**व्यवधान**)... अब हमारी बात सुन लीजिए, आपने अपनी बात कही है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन : आप तो वहां घूमने गए थे, हम तो वहां रहते हैं, प्लीज़ यह बात मत करिए।

श्री अबू आसिम आज़मी (उत्तर प्रदेश): मैंने इनको बुलाया था, ये क्यों नहीं आए। पूछिए, पूछिए इनसे कि ये क्यों नहीं आए। ...(**व्यवधान**)...

†[شری ابوعاصم اعظمی: میں نے ان کو بلایا تھا، یہ کیوں نہیں آئے۔ پوچھئے ان سے کہ یہ کیوں نہیں آئے۔ ـــمداخلتـــ]†

श्री अली अनवर : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक जगह का मामला नहीं है, इस तरह की सियासत करने वाले लोग आपस में ऊपरी तौर पर मिले होते हैं और उसका खमियाजा हमेशा जनता को और आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए, इन बातों को मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन हमारे पूर्ववक्ता ने इस तरह की बात रखी है, इसलिए मुझे यह दोहराना जरूरी हो गया।

मैं अब आता हूं राष्ट्रपति जी के सम्बोधन पर। महोदय, अपनी स्पीच में उन्होंने प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की चर्चा की है। मैं कहना चाहता हूं कि अब प्रधानमंत्री का जो 15 सूत्री कार्यक्रम है, वह एक सफेद हाथी की तरह है। एक आदमी को स्टेट मिनिस्टर का दर्जा मिल जाता है, उसके बाद वह लाल बत्ती लेकर घूमता रहता है। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के नाम पर अक़लियत के लोगों का, कोई भला नहीं हुआ है। इसमें कहा गया है कि *निर्दिष्ट अनुपात में विकास परियोजनाएं अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्थित होंगी और जहां संभव होगा, विभिन्न स्कीमों के तहत उद्देश्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए विनिर्दिष्ट होगा।* यह पंद्रह परसेंट खर्चा नहीं होता, आज भी जो सरकार सच्चर कमेटी के बहाने कह रही है कि हम लोग यह कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं, यह सिर्फ वादे की बात है। इसमें कुछ भी concrete नहीं है, कुछ भी time bound नहीं है, यह election manifesto की तरह है। वह चाहे इनका बजट भाषण हो, चाहे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी का ढिंढोरा तो बहुत पीटा गया, लेकिन सच्चर कमेटी की चार सौ पेज की रिपोर्ट है और अगर सिर्फ कुछ स्कॉलरशिप्स ही बांटनी थीं, कुछ स्कूल ही खोलने की बात थी, कुछ बैंकों से लोन देने की बात थी, तो सच्चर कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? इतनी बड़ी स्टडी कराने की क्या जरूरत थी? आप स्कूल खोल सकते थे, आप वजीफे दे सकते थे, सौ लोगों को देते थे, पांच सौ लोगों को दे देते, इसमें इतना बड़ी स्टडी कराने की और इतनी हाय-तौबा मचाने की क्या जरूरत थी?

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी ने कई और बातों की तरफ भी, जो देश के दस्तकार हैं, जो देश के artisans हैं, जो देश के शिल्पी हैं, जो बुनकर हैं, उनकी हालत सुधारने के लिए भी कई सुझाव दिए हैं। क्या हुआ उन सुझावों का? वे बजट में कहां हैं? वे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहां हैं?

महोदय, इस देश में आज भी खेती के बाद सबसे ज्यादा रोज़गार अगर कहीं मिलता है, तो वह बुनकरी के धंधे से मिलता है और बुनकरी का जो धंधा है, वह कोई कूड़ा-कचरा पैदा नहीं करता, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन महोदय, क्या हालत है? 60 हज़ार करोड़ आपने किसानों का माफ कर दिया, यह अच्छी बात है, हम सभी उसमें खुश हैं, हम सबकी रज़ामंदी है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमारे

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

यहां भोजपुरी में एक कहावत है कि "जैसे मुर्दा पर साठ मन, वैसे एक मन और", तो हम कहना चाहते हैं कि 60 हज़ार करोड़ आपने किसानों का माफ कर दिया, लेकिन 1 हज़ार करोड़ रुपया इस देश में बुनकरों पर भी बकाया है, उनका कर्ज़ा आपने क्यों नहीं माफ किया? इस देश में अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो इस देश में बुनकर भी आत्महत्या कर रहा है, बुनकर भी suicide कर रहा है। खबरें अखबारों में छपती हैं कि कहीं बनारस में कोई औरत अपने ढाई साल के दुधमुंहे बच्चे को 2 हज़ार में बेचती है, इसलिए कि कई हफ्ते से उसके घर में चूल्हा नहीं जला है। कोई औरत नकाब पहनकर सरकारी अस्पताल में जाती है और ढाई सौ रुपए में अपना खून बेचकर आती है। लोग suicide कर रहे हैं, हज़ारों लोगों का पलायन हो रहा है। महोदय, यहां दिल्ली के अंदर red lights पर आप देखिएगा कि औरतें जो फूलों के गजरे बेचती हैं, जिसे औरतें बालों में लगाती हैं, वह फूल का गजरा बेचने वाली आंध्र प्रदेश की महिलाएं हैं, बुनकर महिलाएं हैं। यहां हज़ारों की तादाद में बुनकर बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर रिक्शा चला रहे हैं। जो हाथ बेहतरीन कपड़े बना सकते थे, अब उन्हीं हाथों में ठेला पड़ रहा है और वे आज ठेला चला रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं।

महोदय, पिछली 9 मई को, इसी सदन में, मेरे सवाल के जवाब में बाघेला साहब ने कहा था कि 8 सौ करोड़ से लेकर 12 सौ करोड़ का आकलन किया गया है कि बुनकरों पर कर्ज़ है। उसकी माफी के लिए पी.एम.ओ. से हमारी बातचीत चल रही है। आप यह मंगाकर देख लीजिए और उन्होंने कहा था कि हमारी उम्मीद है कि हम यह माफ करेंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों को जिस rate of interest पर, 7 परसेंट interest पर कर्ज़ मिलता है, उसी rate of interest पर हम बुनकरों को कर्ज़ देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा छल हुआ है, एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है।

महोदय, हम कांग्रेस पार्टी के अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि ये जो बुनकर हैं, ये जो दस्तकार हैं, कोई हम आप पर आक्षेप करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने कलेजे पर हाथ रखकर देखिए कि आज़ादी के पहले से यह जो बुनकर समाज है, यह artisan समाज है, वह कांग्रेस के साथ रहा है। जो nationalist फोर्सिज़ हैं, उनके साथ रहा है। लेकिन आपने निश्चित को छोड़कर अनिश्चित को चुना है। संस्कृत में एक श्लोक है - योध्रुवाणी परित्यज्य, अध्रुवाणी निषेवते। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ दौड़ता है, अनिश्चित तो अनिश्चित है ही, उसका निश्चित भी अनिश्चित हो जाता है — यह मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बच्चा मां के गर्भ से पैदा होता है तो उसकी नाभि काटने के क़ाम आने वाला सूत नारा कहा जाता है। उस नार को बांधने के लिए जो तागा होता है, बुनकर उस तागे को पैदा करता है। इसी प्रकार बुनकर कफन भी पैदा करता है — इस बात को भी आप जान लीजिए। अब यह कफन लेकर निकलेगा और आपको बताएगा। इसका सियासी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपने वादा करके वादाखिलाफी की है* साठ हजार करोड़ रुपया किसानों का माफ किया, लेकिन आप आठ सौ या एक हजार करोड़ रुपया बुनकरों का माफ नहीं कर सकते हैं।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। कल आप ही का सवाल था। मुझे मौका नहीं मिला। हमारे तारिक अनवर जी को पहले मौका मिल गया। आज मेरे बाद तारिक अनवर जी का नाम है। मैं कहना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी का ढिंढोरा बहुत पीटा गया। मीडिया को बुलाकर प्रधान मंत्री जी फोटो खिंचवाया। सच्चर कमेटी से ज्यादा पॉवरफुल कमेटी कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत गठित रंगनाथ मिश्र कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने उस कमेटी का चेयरमैन बनाया — आप ही की सरकार ने बनाया था। 11 महीने हो गए हैं। रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को आप क्यों नहीं टेबल कर रहे हैं? आपको क्या हक है, कल श्रीमती मीरा कुमार आप ही के सवाल के जवाब में उस रिपोर्ट से कोई बात कोट करके बता रही थीं और बहुत नियम और प्रक्रिया का हवाला दे रही थीं। हम सदन से कहना चाहते हैं कि यह सदन का अपमान है। आप 11 महीने से रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को रखे हुए हैं, उसे हाउस में ले नहीं कर रहे हैं — बहस कराने और उस पर कार्यवाही करने की बात तो दूर रही — और नियम और प्रक्रिया का हवाला देते जा रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है। दलित मुसलमान और दलित इसाई इस बात को समझते हैं। आप उन्हें घुमाए जा रहे हैं। महोदय, जब इस देश का संविधान बना।

* Expunged as ordered by the Chair.

हमारे सिख भाई उस समय दलित की केटागरि में नहीं थे। बाद में उनको दलित की केटागरि में शामिल किया गया। वे भी अकलियत के लोग हैं। हमारे एक मित्र संविधान की धारा 16 और 29 का हवाला देते हुए कह रहे थे कि माइनॉरिटी का स्टेटस और शेडयूल्ड कास्ट का स्टेटस कैसे मिल सकता है? महोदय, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि जैसे सिख भाइयों को शेडयूल्ड कास्ट का भी स्टेटस है। शेडयूल्ड कास्ट में भी दलित सिख हैं और वे माइनॉरिटी में भी हैं तो फिर मुसलमान और इसाई क्यों नहीं माइनॉरिटी के हो सकते? माइनॉरिटी के लिए अलग से कोई रिज़र्वेशन नहीं मिलता है। चाहे मुसलमान हों, चाहे इसाई हों, नौकरी में मुसलमान करके कोई रिज़र्वेशन नहीं है, यहां असेंबली और पार्लियामेंट में मुसलमान और इसाई करके कोई रिज़र्वेशन नहीं है। जब वी.पी.सिंह जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने नव बौद्धों को भी दलित की केटॉगरि में रखा। दलित मुसलमान के मामले पर, दलित इसाई के मामले पर एक कंसेंसस बन गया है। मज़हब की बुनियाद पर उनके साथ तफरीक हो रहा है। संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 मजहब की बुनियाद पर किसी तरह के तफरीक की मनाही करता है। इसलिए महोदय, यह बात अब आ गयी है। अब आप घुमा रहे हैं, इसको बैकवॅर्ड कमीशन में ले गए। क्यों ले गए? जब सिख भाइयों को शामिल किया गया था तो उनको एक झटके में शामिल कर दिया गया था, इस तरह से घुमाया नहीं गया। .....(घंटी)..... वी. पी. सिंह साहब ने नवबौद्धों को शामिल किया, लेकिन आप शैड्यूल्ड कॉस्ट के बारे में ऑपिनियन ले रहे हैं। महोदय, यह केवल टाइम पास करने की बात है। हम कहना चाहते हैं कि गरीबों को यह अनुभव है कि चुनाव से पहले ही उनको कुछ मिलता है, चुनाव के बाद कुछ भी नहीं मिलता है। महोदय, आपने भी दलित इसाई का सवाल उठाया है। यह एक जेन्युअन सवाल है, इस देश की मिट्टी का सवाल है और इस सवाल पर पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। इस सवाल पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कंक्लूड कीजिए।

श्री अली अनवर : महोदय, हम कंक्लूड कर रहे हैं। 1950 का जो प्रेजीडेंशियल आर्डर है, हम तो यह भी गुमान कर रहे थे और राष्ट्रपति महोदया से यह उम्मीद रख रहे थे कि उनका जो सम्बोधन होगा, उसमें वे राष्ट्रपति का 1950 का जो आदेश है, उसको वापिस कर लेंगी, उसी आदेश के जरिए किसी शैड्यूल्ड कॉस्ट कमीशन में जाने की जरूरत नहीं है, बैकवॅर्ड कमीशन में जाने की जरूरत नहीं है। जब वी0पी0 सिंह की सरकार थी, तब केवल सेंसस कमिश्नर से पूछ कर के नव बौद्धों को शामिल कर लिया गया था। आप सिखाइए मत, आप घुमाइए मत, इनको शामिल कर लीजिए तथा इनको शैड्यूल्ड कॉस्ट का स्टेटस दे दीजिए। आखिरी बात, महोदय, हमको दो मिनट और दे दीजिए।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह पौलिटिकल मामला है, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देने जा रहा था। शैड्यूल्ड कॉस्ट के स्टेटस के लिए इसाई भाइयों का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था। लेकिन भारत सरकार के एटार्नी जनरल ने कोर्ट को रोका। वैसे वह मामला फैसले के स्टेज में आ गया था, उसकी सुनवाई हो चुकी थी, उसकी हियरिंग हो चुकी थी, केवल फैसला होने वाला था। भारत सरकार के एटार्नी जनरल ने कहा कि यह मामला बहुत सेंसेटिव है, पौलिटिकल है, इसलिए मेहरबानी कर के इस पर आदेश मत दीजिए, हम इस पर कार्यवाही करेंगे तथा इसमें हमको छः महीने का अवसर दे दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको छः महीने का समय नहीं दिया, छः हफ्ते का समय दिया। उसी के बाद रंगनाथ मिश्र कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 'अन्य धर्मों में दलित की पहचान का काम' मामला उनको सौंपा गया। जब पहले रंगनाथ मिश्र कमीशन बना था तब यह मामला उनके जिम्मे नहीं था। अब उस कमीशन की रिपोर्ट आ गई है और दूसरी बड़ी बात यह कि इस देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है, अभी हमारे साथी बी0एस0पी0 के नेता बोल रहे थे उनकी पार्टी का समर्थन है, मुलायम सिंह जी की पार्टी का समर्थन है, लालू जी का समर्थन है, हमारी पार्टी का, नीतीश कुमार जी जब एम0पी0 थे, तब उन्होंने संसद में इस सवाल को उठाया था। करुणानिधि जी ने समर्थन किया है, तमाम लोगों ने समर्थन किया है। उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से पश्चिम से चारों तरफ समर्थन हो रहा है। आप इसको किस बात के लिए घुमा रहे हैं और किस को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए अपने कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहते हैं कि यह कोर्ट के दायरे से बाहर है और शैड्यूल्ड कॉस्ट

कमीशन के अध्यक्ष श्री बूटा सिंह जी ने भी इसकी सिफारिश कर दी है, तमाम पार्टियों ने इसकी सिफारिश कर दी है। बाकी लोगों से भी हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर उनसे गुजारिश है कि दलित मुसलमान और दलित इसाइयों के मामले को, बुनकरों के मामले को पार्टी से ऊपर उठ करके विचार करें। कितने दिन हमको इंतजार कराइएगा। 60 साल हो गए, हमारे लोग तड़प रहे हैं। इसलिए महोदय, आप सबके समर्थन के लिए गुजारिश करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी भी सरकार के कार्यकलाप का और उसकी नीति का आइना होता है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सम्भवत: सारे पहलुओं को छूने का प्रयास किया है। भविष्य में सरकार का क्या लक्ष्य है, क्या नीति है, उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली है।

मैं अपने उन साथियों से सहमत नहीं हूं जिन्होंने अपने भाषण में यह कहा है कि पिछले 4 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है, जिसकी सराहना की जाये और उन्होंने यह भी कहा है कि यह सरकार दिशाविहीन रही है, यह सच्चाई नहीं है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को देखने के बाद वह तमाम चीजें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं कि पिछले 4 वर्षों में क्या-क्या महत्वपूर्ण निर्णय इस सरकार द्वारा लिए गए और किस तरह से सरकार इस देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए और सभी समुदाय, सभी वर्ग के बीच में एक समन्वय बनाते हुए इस देश को आगे ले जाने का काम यह सरकार कर रही है। भारत निर्माण का कार्य, नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी प्रोग्राम, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील प्रोग्राम, नेशनल रूरल हैल्थ मिशन, जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनुअल मिशन, राइट टू इन्फॉरमेशन एक्ट इत्यादि बातों का जिक्र इस अभिभाषण में किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो भारत निर्माण की बात कही गयी है, मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक कार्य इस सरकार ने अपने हाथ में लिया है, क्योंकि आज जो भारत है, जिसे हम गांवों का देश कहते हैं, उस भारत की अवहेलना होती रही और 60 सालों में जितना विकास ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए था, गांवों की जितनी उन्नति होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई और इस सरकार के आने के बाद उस पर ध्यान दिया गया। भारत निर्माण की एक योजना बनाई और उस योजना के तहत गांवों को सड़क से जोड़ने का काम, गांवों में बिजली पहुंचाने का काम, पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम, सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम, उन गरीब बच्चों को जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही थी, उन तमाम कामों की शुरूआत इस सरकार ने की और उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है और उसकी ओर बढ़ने का काम किया है। यह ठीक है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, महान है और हमारी समस्याएं भी उसी तरह से बड़ी हैं, महान हैं, उनका समाधान निर्धारित समय में नहीं हो सकता है, उसके लिए समय की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है, लेकिन यह जो तमाम कार्यक्रम हैं, उनमें इस सरकार की नीति और उसका क्या लक्ष्य है, यह उसको दर्शाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो इस सरकार का एक लक्ष्य है, अगली जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें अभी जो हमारा ग्रोथ रेट 9 प्रतिशत है, उसको 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत पर ले जाने का लक्ष्य है। यह इस बात का संकेत भी है कि पिछले 4 साल तक लगातार हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है, वह लगभग 9 प्रतिशत के आसपास रहा है, यह अपने आप में सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सरकार ने इस ग्रोथ रेट को लगातार 4 साल तक मेंटेन किया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस अभिभाषण में सभी तबकों को छूने की कोशिश की है, शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेज़, माइनारिटीज़, सबकी जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उन पर ध्यान दिया गया है। खासतौर पर शैड्यूल्ड कास्ट के लिए, उनके बच्चों को शिक्षा, उनके लिए स्कालरशिप की व्यवस्था की गई है, इसके लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिं 30 लाख शैड्यूल्ड कास्ट के बच्चे लाभान्वित होंगे। उसी तरह से शैड्यूड ट्राइब्स के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे दस लाख ट्राइबल चिल्ड्रन लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त राजीव नेशनल फैलोशिप दी जाएगी। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल्स यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प भी है। इन

4.00 P.M.

बातों से यह साबित होता है कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, उन पर भी सरकार का पूरा-पूरा ध्यान है। हम राजनाथ सिंह जी की उस बात से सहमत नहीं हैं, जो खासतौर से उन्होंने 15 सूत्री कार्यक्रम को लेकर मुस्लिम समाज के बारे में कही है। इस सरकार ने यह निश्चित किया है कि प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत वह अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए काम करेगी। हम बहुत दिनों से यह सुनते आए हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का और खास तौर पर मुस्लिम समाज का वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण होता है। महोदय, जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद और जस्टिस रंगनाथ मिश्र जी की रिपोर्ट आने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई और साफ हो गई कि जो बातें बहुत दिनों से कही जाती रही हैं, यह जो आरोप लगाया गया कि इस देश में मुस्लिम समुदाय का तुष्टिकरण हो रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आज इस देश में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनकी स्थिति इस देश के दलितों के समकक्ष हो गई है। अगर यही स्थिति बनी रही और सरकार ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में यह आबादी, यह जनसंख्या इतनी पिछड़ जाएगी कि इसको फिर से मुख्य धारा में जोड़ना बहुत कठिन होगा। महोदय, सरकार ने यह फैसला लिया कि जो जस्टिस राजेन्द्र सच्चर की रिपोर्ट है और जो उनके सुझाव हैं, उन पर अमल किया जाए। उसी को ध्यान में रखकर यह फैसला हुआ कि अल्पसंख्यकों के लिए या जहां अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या ज्यादा है, ऐसे जिलों में या ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम यह सरकार करेगी और यह आवश्यक भी है। महोदय, अगर हमें इस देश को एक रखना है, इस देश को एक साथ लेकर चलना है, तो समाज का कोई भी वर्ग चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट हो, शैड्यूल्ड ट्राइब्स हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन सबको ऊपर उठाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। श्री सीताराम येचुरी जी ने ठीक कहा है कि किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि उस समाज मे जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनके ऊपर उस सरकार की या समाज की क्या दृष्टि है, इस बात से एक सभ्य समाज की ही पहचान बनती है। अगर इस सरकार ने मुस्लिम समाज के लोगों को ऊपर उठाने के लिए और देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह फैसला लिया है, जब सरकार उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है! ऐसा करने पर सरकार के बारे में कहा जाता है कि यह वोट बैंक बना रही है। हम एक तरफ भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, भारत को बनाने की बात कर रहे हैं, उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो विश्व के विकसित देश हैं, भारत को उनकी पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं, तो क्या हम समाज के एक वर्ग को दरकिनार करके भारत को आगे बढ़ा सकते हैं? ऐसा करके क्या हम भारत को मजबूत कर सकते हैं ? आज हमें राजनीति से ऊपर उठकर इन बातों पर भी सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जो हमारे मित्र इस तरह की बातें करते हैं, वे राजनीति से प्रेरित हैं। अगर हम देश और समाज को बनाने की बात करते हैं, तो हमें राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है और सबको एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि इस देश में रहने वाला कोई भी वर्ग अछूता न रह जाए, उसके साथ नाइंसाफी न हो और उसको हर तरह का अवसर मिले, मौका मिले।

महोदय, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, जिसका ज़िक्र यहां कई वक्ताओं ने किया, कई माननीय सांसदों ने किया है। इसमें अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा गया। यह बात सही मायनों मे बहुत गंभीर है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जो बातें मैंने पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं, उससे अंदाजा होता है कि जहां हम एक तरफ गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, गरीब और अमीर के बीच की खाई पाटने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की 78 प्रतिशत आबादी को मात्र बीस रुपए रोजाना मिल रहे हैं। यह अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया है, कहा गया है। यह मामला बहुत गंभीर है। यह चिंता का विषय है कि हम इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बात को हम आगे आने वाले समय में कैसे ठीक कर सकते हैं, यह सोचने की बात है। हमारे समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है, अगर उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा तो लोगों का लोकतंत्र में जो विश्वास है, आज की व्यवस्था में जो विश्वास है, वह विश्वास घटता जाएगा और फिर हमारे देश के अंदर जो इस तरह का एक दूसरा वातावरण बनाने की बात हो रही है, खूनी क्रांति की

बात हो रही है या हथियार उठाने की बात हो रही है या जिसे हम कह सकते हैं कि लोग एक्स्ट्रिमिज्म की तरफ जा रहे हैं, यह सारी चीजें हो सकती हैं। इसका लाभ उन शक्तियों को मिल सकता है, इसलिए उन्हें रोकने के लिए भी आवश्यक है कि हम ऐसा कदम उठाएं जिससे उस तरह के लोगों को उसका लाभ न मिले और सही मायनों में जो गरीब लोग हैं, उन्हें अहसास हो कि यह सरकार और यह व्यवस्था उनके पक्ष में है, हम उनकी मदद करना चाहते हैं।

जहां तक भारत निर्माण का सवाल है, भारत निर्माण के माध्यम से, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अभी तक गरीबों को 40 लाख मकान दिए जा चुके हैं, 44,000 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है, आज टेलीफोन भी देश के करीब-करीब सभी गांवों में उपलब्ध है, इसकी सुविधा उपलब्ध है। ये सारे काम हुए हैं, इनको करने की आवश्यकता थी।

रोजगार गारंटी योजना, मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि बेरोजगारी सारी बीमारियों की जड़ है। अगर हम बेरोजगारी का कोई रास्ता निकाल लें, लोगों को रोजगार दे दें, तो जो पलायन की बात होती है, खास तौर पर जो पिछड़े राज्य हैं, वहां से लोग दूसरे राज्यों में, महानगरों में जाते हैं, वहां वे खुशी से नहीं जाते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार, अपने बच्चों, बूढ़े मां-बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। वह उसकी मजबूरी है, बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके पालन-पोषण के लिए उसे पलायन करना पड़ता है। वहां जाकर उसे बेइज्जत भी होना पड़ता है, लेकिन इन सबके बावजूद भी इसलिए पलायन होता है, क्योंकि उसे गांव में रोजगार नहीं मिलता है। सरकार ने यह जो कदम उठाया है, यह सौ दिन का है, मैं मानता हूं कि यह कम है, परंतु सरकार ने यह अच्छा निर्णय लिया है कि देश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया है। पहले तो कुछ सीमित जिलों में था, अब इसे पूरे देश के पैमाने पर कर दिया है। यह अच्छा काम हुआ है, लेकिन इसे 365 दिन करना चाहिए। पूरे वर्ष करना चाहिए ताकि जिसको भी रोजगार नहीं मिले, वह उसका लाभ उठा सके। इस तरह से हम पलायन रोक सकते हैं और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं और समाज में जो असंतोष है, उसे भी समाप्त कर सकते हैं। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है, यह बहुत ही सराहनीय है।

इस सरकार द्वारा राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन का फैसला लिया गया। यहां पर भ्रष्टाचार की बात कही गई कि भ्रष्टाचार मिटाने का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन का फैसला करके इस सरकार ने ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, जो बेसहारा थे, जो अपनी बात नहीं कह सकते थे, जिनको कोई जानकारी नहीं मिलती थी कि उनके साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, उनके साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है। आज हर आदमी को यह अधिकार है कि वह राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत सभी तरह की जानकारी ले सकता है और उसके खिलाफ जहां भी वह मुनासिब समझे, चाहे अदालत या शासन का दरवाजा खटखटा सकता है। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. अलका क्षत्रिय (गुजरात) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपके माध्यम से उस क्रांतिकारी फैसले के बारे में, जिससे करोड़ों किसानों को राहत मिली है, उसके लिए सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। महोदय, अभिभाषण का समर्थन करते हुए चर्चा शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह सत्र भी एक ऐतिहासिक सत्र है। भारतीय लोकतंत्र का जो इतिहास लिखा जा रहा है, इस इतिहास का यह पल एक श्रेष्ठ पल माना जाएगा, उसे सदैव याद रखा जाएगा कि इस देश के सर्वोच्च नागरिक के रूप में एक महिला को स्थान प्राप्त हुआ है और उसके सम्बोधन पर आज इस सदन में चर्चा हो रही है। आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ महिलाएँ कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, वहीं पर हमारी यूपीए की अध्यक्षा, जो स्वयं भी एक महिला हैं, उन्होंने एक ऐसा सुअवसर इस देश को प्रदान किया है, जिस पर इस देश की सारी महिलाओं को बड़ा गर्व प्राप्त हो रहा है और हम भी मानने लगे हैं और पूरी दुनिया मानने लगी है कि भारत में नारी का सम्मान सर्वोच्च है। इसके लिए मैं यूपीए की अध्यक्षा माननीया सोनिया गाँधी जी का धन्यवाद करती हूँ। महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ... **(व्यवधान)** ... आप पहले सुन तो लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए, आपकी भी बारी आएगी ... **(व्यवधान)** ...

चिन्ता मत कीजिए, आपकी भी बारी आ रही है ... (**व्यवधान**) ... उनकी भी बारी आ रही है, चिन्ता मत कीजिए।

महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण एक ऐसा दस्तावेज है, जो दर्शाता है कि सरकार की सोच और दिशा व दशा क्या है। सदन में जिस अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, उससे एक तथ्य तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भारत को विश्व स्तर पर आर्थिक सत्ता बनाने के लिए उस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कदम उठाए हैं, इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि उनके चार वर्ष के कार्यकाल में भारत एक आर्थिक सत्ता के रूप में उभरा भी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण से यह तथ्य भी स्पष्ट हो रहा है कि इस सरकार के कार्य व योजनाओं के केन्द्र में आम आदमी और सर्वसमावेशी विकास सदैव ध्यान में रखा गया है। मैं यह भी कह सकती हूँ कि आर्थिक विकास का लाभ आम आदमी तक पहुँचे, इसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारे विपक्ष के मित्र हर बार सदन में चर्चा करते वक्त हम पर यह आरोप भी लगाते हैं और यह ज़िक्र करना भी कभी नहीं भूलते कि यह सरकार आम आदमी की सरकार के नाम पर सत्ता में आई है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि हाँ, यह आम आदमी के द्वारा आम आदमी के लिए आम आदमी की ही सरकार है। इसीलिए हमारी सरकार की हरेक योजनाओं में आम आदमी हमेशा केन्द्र में रहता है। जहाँ तक अगर मैं खास आदमी की बात करना चाहती हूँ, तो हमारे विपक्ष के कुछ खास लोग कुछ खास सोच के साथ कुछ खास आदमियों की बात करते हैं और हम पर यह ताना लगाते हैं। मैं समझती हूँ कि यह खास आदमी उन्हीं को मुबारक हो। इनके बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहती। उपसभाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक आम आदमी का सवाल है, यूपीए सरकार ने आम आदमी के विकास को ध्यान में रखते हुए गाँवों व शहरों में अन्तर पाटने के लिए भारत निर्माण, शिक्षा के समान अवसर के लिए सर्व शिक्षा अभियान व मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ग्रामीण निर्धनों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत पाँच लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों की मदद, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2007, साथ ही क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे के प्रत्येक श्रमिक व उसके परिवार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए आम आदमी बीमा योजना ...। गरीबी रेखा के नीचे के वृद्धों के लिए पेंशन योजना जैसी अनेक विकास योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिसके बारे में हमारे काफी साथियों ने चर्चा की है। कृषि क्षेत्र के उत्तरोत्तर विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में चावल, गेहूं व दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हमने बनाई है।

सुरक्षा के क्षेत्र में आतंकवाद व नक्सलवाद से निपटने के लिए पुलिस व सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण को हमने उच्च प्राथमिकता दी है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए ब्लॉक व ग्राम स्तर पर पंचायत युवा खेल एवं क्रीड़ा अभियान लागू किए हैं। इतना ही नहीं हमने एससी, एसटी और ओबीसी के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत जोर दिया है। अनुसूचित जातियों के लगभग 30 लाख बच्चों को हमने 900 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के 10 लाख से अधिक बच्चों के लिए हमने 225 करोड़ रुपयों का प्रावधान भी किया है।

महोदय, हमारी यूपीए सरकार ने पंचायती राज को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है और इसके बारे में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसका कारण है कि पंचायत ही वह ईकाई है जो आम आदमी के विकास का पहला दरवाजा है। गांव के विकास के लिए पंचायत एक दहलीज़ है। महोदय, आम आदमी के विकास के लिए उपयोगी इन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए इस पंचायत के सबसे बड़े मुखिया हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉ मनमोहन सिंह जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूं और उनकी बहुत आभारी हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की चर्चा की गई है। यूपीए सरकार ने आम आदमी को ध्यान में रखते हुए कृषि व कृषकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। हमारे राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में हमने एक लक्ष्य रखा था कि तीन सालों के अंदर हम कृषि क्षेत्र के ऋण को दुगुना कर देंगे और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हम उस लक्ष्य को काफी पीछे छोड़ आए हैं। इसके अलावा

हमारी सरकार ने देश की रीढ़ की हड्डी समान किसानों के लिए भी काफी कुछ किया है, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आपने स्वयं ही देख लिया है कि सामान्य बजट में हमारी सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ किया है।

महोदय, इस सदन में किसानों की समस्या को लेकर कई बार चर्चा हुई है। हमारी सरकार में स्वयं हमारे प्रधान मंत्री जी ने काफी क्षेत्रों का दौरा भी किया है और इसके लिए विशेष राहतों की घोषणा भी की है। उन्हें राहत प्रदान करने के काफी प्रयास किए गए हैं और उसके परिणाम धीरे-धीरे दिख भी रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि मर्ज बहुत पुराना है, इसलिए दवा का असर भी धीरे-धीरे ही होगा।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कल से जो चर्चा हो रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि सभी के द्वारा किसानों की समस्याओं पर गहरी चिंता जताई जाती है। हमारे विपक्षी दल के प्रमुख श्री राजनाथ सिंह जी ने भी उनके लिए काफी चिंता जताई है। मैं मानती हूं कि चिंता करना बड़ी अच्छी बात है और चिंता करनी भी चाहिए। इस देश के किसानों की चिंता यदि हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? राजनाथ सिंह जी स्वयं को एक किसान नेता बताते हैं और एनडीए सरकार के राज्य में वह कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। मैं उनसे कुछ कहना भी चाहूंगी, हालांकि वह आज यहां पर हाजिर नहीं हैं, लेकिन उनके साथी यहां पर हैं और वे मेरा संदेश उन तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए यह बात मैं उनसे कहना चाहती हूं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मर्ज बहुत पुराना है और इसको समझना होगा। कोई भी किसान या कोई आम आदमी मौत को आसानी से कभी-भी गले नहीं लगाता है। एक साल, दो साल या तीन साल तक भी अगर फसल खराब होती है या कर्ज होता है तब भी वह कभी आत्महत्या नहीं करता है, लेकिन जब मर्ज पुराना होता है और जब उसका कर्ज बढ़ता जाता है, तभी वह किसान आत्महत्या करता है। इसीलिए मैं यह बात बहुत गहराई से कहना चाहती हूं और यह बात मैं इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि मैं स्वयं एक कोऑपरेटिव बैंक चलाती हूं और मुझे मालूम है कि ऋण की अदायगी किस तरह से की जाती है एवं उसका क्या तरीका होता है ...(**व्यवधान**)...। एक दिन में कोई नहीं करता। आपको जवाब देना ही है। मैं आपका जवाब भी माँगूंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एन.डी.ए. की सरकार के दौरान कृषि मंत्री रहे राजनाथ सिंह जी ने जो चिन्ता की एक लकीर खींची है, उस की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि क्या पूर्व मंत्री होने के नाते ये खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? क्या वे अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं? अगर ये इस बात को स्वीकार करते हैं, तो उनको इस सदन में स्वीकार करना चाहिए कि अपने कार्यकाल में किसानों के लिए कार्य करने में वे अक्षम साबित हुए। इस बात को स्वीकार करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यह बात मैं इस सदन के माध्यम से कह रही हूँ।

महोदय, इतना ही नहीं, गुजरात में अभी हाल ही में चुनाव हुए और गुजरात में इन्हीं की पार्टी की सरकार बनी, लेकिन बहुत कम समय में गुजरात के आदिवासियों पर सरकार की पुलिस ने गोली-बारी की और दो आदिवासियों को मार दिया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि सरकार इतनी जल्दी बैलेट से बुलेट पर कैसे पहुँच गई? ऐसी क्या परिस्थिति आई कि इतनी कम समय में सरकार बैलेट से बुलेट पर पहुँच गई और उसे आदिवासियों पर गोली चलानी पड़ी, जब कि हमारी सरकार अगर किसानों को राहत प्रदान करती है, तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। वे कहते हैं कि यह कैसे किया? यह कहाँ से लाएँगे? इसका जवाब हमसे माँग रहे हैं ये लोग।

महोदय, मैं अपनी आखिरी बात कहने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। अरुण जी ने एक सवाल उठाया था, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। उन्होंने हमारी नेता की सक्षमता के बारे में प्रश्न उठाया था। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की, हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने India Shining की उनकी पोल खोल कर जिस तरह आपकी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया, सत्ता से खारिज कर दिया और आपको अक्षम बना दिया, क्या इसके बाद भी हमारी नेता की सक्षमता के बारे में आप सवाल उठाना चाहते हैं? यह खुद इस बात के सवाल का जवाब है कि आज आप कहाँ पहुँच गए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि : अलका जी, प्रधान मंत्री जी आपके पीछे बैठे हैं ...(**व्यवधान**)...

प्रो0 अलका क्षत्रिय : प्रधान मंत्री जी हैं, वह मैं जानती हूँ ...**(व्यवधान)**... मुझे जहाँ प्रधान मंत्री जी का नाम लेना है, मैं ले भी रही हूँ। आप चिन्ता आप मत करिए ...**(व्यवधान)**... सवाल जिसके बारे में उठाया गया था, जवाब भी उसी के बारे में दिया जाएगा ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं अब आखिरी बात कहना चाहती हूँ। वह आखिरी बात यह है कि जो बात मैंने पहले दोहराई, उसी पर आ रही हूँ। मैं आम आदमी के बारे में बात कर रही हूँ। 'कांग्रेस ने आम आदमी का नारा दिया और सत्ता हासिल की' यह बार-बार कहा जाता है। मैं इसी बात पर वापस आ रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि हमने तो 'आम आदमी' का नारा दिया, तो हम 'आम आदमी' की बात कर रहे हैं। लेकिन, हमारे विपक्ष के मित्र तो भगवान राम की बात कर रहे हैं, उसकी चिन्ता कर रहे हैं, उस भगवान राम की, जो सारे जगत का ~~कल्याण~~ है। यह खुद इतना सक्षम है, उसकी चिन्ता ये लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने भगवान राम के बजाए भगवान राम के भक्तों की चिन्ता की होती, तो 2002 में गुजरात के अन्दर राम-भक्तों को जिन्दा नहीं जलाया जाता। उनको बचाने में इनकी सरकार नाकाम रही थी। अगर यह नाकामी है, तो इनकी सरकार की नाकामी है, राम भक्तों को बचाने में नाकामी। इसका जवाब इनको देना चाहिए। बजाय इसके, ये राम की चिन्ता कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि ये राम की चिन्ता कर रहे हैं। राजनाथ जी कल बड़ी चिन्ता कर रहे थे। इनकी चिन्ता से तो मुझे यह लग रहा था कि भगवान राम का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इस कलयुग के अन्दर विपक्षी दल भगवान राम को तो अक्षम मानने लगा है और खुद अपने आपको काफी सक्षम समझने लगा है। क्या यही उनकी सक्षमता है? इनकी बात से मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर खतरा महसूस किया है, हमारी आस्था पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। मैं बताना चाहती हूँ कि आप जितने राममक्त हैं, उससे कहीं बढ़ कर हम भी राम के भक्त हैं और इसीलिए हम राममक्तों के लिए, इस देश के आम लोगों के लिए काम करते हैं। ...**(व्यवधान)**... देख लीजिए, हम तो जीत ही गए। ...**(व्यवधान)**... परिणाम बतलाएगा ...**(व्यवधान)**... परिणाम बताएगा ...**(व्यवधान)**... हम आपके जैसे खास लोगों की चिन्ता नहीं करते ...**(व्यवधान)**...

श्री शाहिद सिद्दिकी : मस्जिद आपने तुड़वायी थी ...**(व्यवधान)**... मन्दिर आप बनवाएँगे? ...**(व्यवधान)**..

†[ ]شری شاہد صدیقی : مسجد آپنے تڑوائی تھی۔مداخلت۔ مندر آپ بنوائیں گے

۔مداخلت۔]†

श्री सुरेन्द्र लाठ : आप किसका समर्थन कर रही हैं? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0जे0 कुरियन) : आप बैठिए।

श्री सुरेन्द्र लाठ : आप इस इश्यू पर प्रश्न-चिह्न लगा रहे हैं, अपने को राम भक्त कह रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

प्रो0 अलका क्षत्रिय : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से इनसे पूछना चाहती हूं कि आप जिस खास आदमी की बात कर रहे हैं, अगर किसी खास आदमी के घर पर कोई पत्थर फेंक दिया जाता है या उसके घर का शीशा तोड़ दिया जाता है तब तो आप पूरे देश में हल्ला मचा देते हैं, लेकिन जब आपकी सरकार के राज निठारी में निठारी के अंदर आम आदमी के बच्चों को मारा गया तब तो आपको यह सामान्य बात लगी थी। तब आपने कोई हल्ला नहीं मचाया था। अब आप बात कर रहे हो खास आदमी की। मैं उन खास लोगों की बात नहीं कर रही हूं ..**(व्यवधान)**... मैं आम आदमी की बात कर रही हूं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष : सिद्दिकी जी, बैठिए।

श्री शाहिद सिद्दिकी : उसे बचाने में आप लगे हो। ...**(व्यवधान)**...

شری شاہد صدیقی : اسے بچانے میں آپ لگے ہو ۔مداخلت۔

---

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

प्रो0 अलका क्षत्रिय : मैं यहां आम आदमी की बात करने के लिए खड़ी हुई हूं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी. जे. कुरियन): आप बैठिए। Please conclude. Do not go into controversies.

प्रो0 अलका क्षत्रिय : मैं फिर से कहना चाहती हूं कि राम के अस्तित्व के बारे में ये लोग सवाल उठा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr Siddiqui, please allow her to complete.

प्रो0 अलका क्षत्रिय : सर, मैं जब इसके बारे में सोचती हूं ...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दिकी : इस ख़ास आदमी का नाम लें ...(व्यवधान)...

†[شری شاہد صدیقی : اس خاص آدمی کا نام لیں ۔مداخلت۔]†

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): अरे, आपका नाम बुलाया जाएगा। Mr Siddiqui, you can reply. Your turn is coming.

प्रो0 अलका क्षत्रिय : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह नहीं मालूम पड़ रहा ...(व्यवधान)... मैंने किसी का नाम तक नहीं लिया, किसी को कोट नहीं किया, फिर भी इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ...(व्यवधान)... इनको फिर भी दर्द हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी. जे. कुरियन): अलका जी, conclude कीजिए।

प्रो0 अलका क्षत्रिय : जब मैं इसके बारे में सोचने बैठती हूं और जब ये लोग राम के बारे में बात करते हैं, तब मुझे लगता है कि भगवान राम पर तो खतरा नहीं है, पर भगवान राम का राजनीतिकरण करने वाले का अस्तित्व जरूर खतरे में है और इसीलिए इनको चिंता हो रही है। लेकिन मैं इनको बताना चाहती हूं की "काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती।" एक समय था जब आप बताते थे कि मंदिर बनेगा, यहीं बनेगा। फिर समय चलते आपने कहा कि मंदिर बनेगा, यहीं-कहीं बनेगा और बाद में आपने बता दिया कि ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No please. Why are you interrupting? Do not make comments. You can reply. ...*(Interruptions)*...

प्रो0 अलका क्षत्रिय : मंदिर नहीं बनेगा। यह तो हमारे एजेंडे में ही नहीं है। अब आपका एजेंडा जिस तरह से बदलता है, उसे देखकर मैं क्या कहूं? यह मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी आप अपना एजेंडा क्यों बदल रहे हो? आप बार-बार राम मंदिर और राम सेतु की बात कर रहे हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि भा0ज0पा0 सदैव राम मंदिर और राम सेतु के मुद्दे को लेकर इस देश के करोड़ों लोगों की श्रद्धा व आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस देश की एकता और अखंडता के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब-जब धर्म का राजनीतिकरण हुआ है, जब-जब धर्म को राजनीति का मोहरा बनाया गया है तब-तब विनाश ही विनाश हुआ है और हमारे दोस्त उस विनाश को बुला रहे हैं। भगवान इनको बख्श दे। (समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (प्रो.पी. जे. कुरियन): थैंक्यू। श्री शाहिद सिद्दिकी।

श्री शाहिद सिद्दिकी : सर, धन्यवाद। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में आउट-साइड सपोर्ट की बात जैसे येचुरी जी ने कही थी, मैं भी आउट-साइड सपोर्ट प्रदान कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात inclusive growth की कही, लेकिन इस inclusive growth की पोल अर्जुन सेनगुप्ता रिपोर्ट ने खोल दी। उन्होंने किसानों की inclusive growth, आम आदमी की inclusive growth की बात की, लेकिन किस तरह से इस देश के 75 प्रतिशत से ज्यादा लोग 20 रुपए रोज पर गुजारा करने पर मजबूर हैं, यह इन्हें पता नहीं है। इस inclusive growth की असलियत को सच्चर कमेटी ने खोल दिया है कि किस तरह से 60 सालों में मुसलमानों को इस ग्रोथ से बाहर रखा गया है, उन्हें 60 साल से इस देश के डवलपमेंट से बाहर

†[ ]Transliteration in Urdu Script

रखा गया है। सच्चर कमेटी ने इस inclusive growth की पोल पूरी तरह से खोल दी। किसानों को विकास से किस तरह से बाहर रखा गया, इसकी पोल स्वामीनाथन कमेटी ने खोल दी। आपके ही बनाए गए कमीशनों ने आपकी पोल खोल दी कि किस तरीके इस देश में uneven growth हुई है। जो डवलपमेंट हुआ है, उस में किसी को भी बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिली है, चाहे वे किसान हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे महिलाएं हैं और चाहे आम आदमी है, सब को आप ने बाहर रखा है, वंचित रखा है। कुछ लोगों की ग्रोथ हुई है। सब को आपने बाहर रखा है, वंचित रखा है। कुछ लोगों की ग्रोथ हुई है, इसलिए इनक्ल्यूजिव ग्रोथ की बात कम से कम आपकी सरकार न करे, तो ज्यादा अच्छा होगा।

महोदय, किसानों की बात की गई है। हम इस पर तफसील में बजट पर चर्चा के दौरान बात करेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से किसानों को ठगने की कोशिश हो रही है, उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। मुझे और आपको नहीं, खाली सरकार को नहीं, क्योंकि आपने उन लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ा दी हैं जो अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हैं, उन लोगों की जो अपनी जान दे रहे हैं, जो जानते हैं कि उनकी शाम की रोटी का पता नहीं, कल को उनके तन पर कपड़ा होगा या नहीं, उनकी उम्मीदें आपने बढ़ा दी हैं और आप यह जानते हैं कि आप उनकी उम्मीदें पूरी करने वाले नहीं हैं। तो यह जो किसानों के साथ धोखा है, इस पर जेटली जी ने बड़ी अच्छी तरह से रोशनी डाल दी है, इसलिए मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो आप बाजार भाव की बात करते हैं, तो किसानों को उनके अनाज का बाजार भाव क्यों नहीं देते हैं? उनके अनाज पर आप क्यों कंट्रोल रखते हैं, जबकि हर चीज किसान बाजार भाव से खरीदता है, वह अपना कपड़ा खरीदता है बाजार भाव से, खाद खरीदता है बाजार भाव से, तेल खरीदता है बाजार भाव से? बाजार के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, आसमान पर जा रहे हैं, आप खुद कहते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ाने पर मजबूर हैं, क्योंकि दुनिया में तेल के दाम बढ़ गए हैं। क्या दुनिया में गेहूं के दाम नहीं बढ़े हैं? अगर दुनिया में गेहूं के दाम बढ़े हैं, तो वह आप मेरे किसान को क्यों नहीं देते हैं? आप अमरीका को, इंग्लैंड को, वॉलनॉट को, सबको दुनिया के भाव देने को तैयार हैं और हमारे बहुत बड़े-बड़े इकोनोमिस्ट जो इस देश को चला रहे हैं, वे इकोनोमिस्ट जानते हैं कि ग्लोबल इकोनोमी क्या है, ग्लोबल मार्केट क्या है, लेकिन किसान को आप वह दाम देने को तैयार नहीं हैं, किसान की प्रोडक्ट के दाम पर आप कंट्रोल रखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक किसान की जो प्रोडक्ट है, उसमें उन्हें मुनाफा नहीं मिलेगा, उसके मसले का हल नहीं होगा। यही हमारी डिमांड थी, इसीलिए हमने आवाज उठाई। आपने किसान को इस तरह से कर दिया है कि वह भूखा है, खाने को नहीं है, बच्चों के खाने को नहीं है और आपने उसकी बहुत भारी दावत कर दी, उस दावत में आपने बहुत सजा दिया कि पूड़ियां, हलवे खाओ, पेट भर कर खाओ एक दिन। अब अगर वह एक दिन खाएगा, तो वह एक दिन खाकर बीमार हो जाएगा, अगले दिन क्या करेगा? उसके अगले दिन का आपने इंतजाम नहीं किया। आप एक आदमी को पेट भर कर एक दिन, दो दिन खिला दो, उससे काम नहीं बनता। उसका, किसान का भविष्य क्या होगा, इसके लिए सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इस पर तो तफसील में बजट पर बात होगी, मगर एक और बुनियादी मुद्दे पर मैं आना चाहता हूँ, जिस मुद्दे को आप मुसलसल अंडर द कारपेट खिसकाते जा रहे हैं और वह है इस देश की माइनोरिटीज का सवाल।

महोदय, आपने सच्चर कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट पर बार-बार मांग के बावजूद यहां पर बहस नहीं हुई। जस्टिस रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट आई, उस पर आपने हाऊस में बहस नहीं कराई। सवाल यह है कि आप सर्वशिक्षा अभियान चला रहे हैं, आपकी जवाहर रोजगार योजना है, आपकी इंदिरा आवास योजना हैं, ढेरों योजनाएं आप लंबे अरसे से, साठ वर्षों से चला रहे हैं, तरह-तरह की योजनाएं कुछ लोगों के नाम से चलती रहती हैं, लेकिन उसमें आपने माइनोरिटीज को कोई हिस्सा नहीं दिया। यह हिस्सा क्यों नहीं मिला? ...(व्यवधान)... हिस्सा दिया होता, तो आज सच्चर यह न कहते, जो उन्हें कहना पड़ रहा है। आपने दो प्रतिशत भी हिस्सा नहीं दिया। मेरे पास बहुत सारे आंकड़ें मौजूद हैं, सारे आंकड़े सच्चर के दिए हुए हैं। अगर इसे पढ़ना शुरू करुंगा, तो बहुत समय लगेगा। मेरे कहने का मकसद यह है कि इन्क्ल्यूजिव ग्रोथ में आपने इनको कहीं शामिल नहीं किया है और इसकी वजह है, मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा हूँ, आपकी इंटेंशन्स अच्छी हो सकती हैं, लेकिन असल में इस देश में जो प्रोब्लम रही है, वह

इंटेंशन्स की नहीं, इंप्लीमेंटेशन की रही है। इंटेंशन्स अच्छे होते हैं, बंगाल में सरकार है, उसके इंटेंशन्स अच्छे रहे, बहुत सेकुलर सरकार है, मगर बंगाल में माइनोरिटीज की, खासतौर से मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी हालत अच्छी नहीं है। तो इस पर मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस पर गौर कीजिए कि क्यों इन अच्छे इंटेंशन्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है? मैं आपके सेकुलर इंटेंशंस पर डाउट नहीं कर रहा, लेकिन असल प्राब्लम पर हम नहीं जाते हैं। असल प्राब्लम इम्प्लिमेंटेशन की है और इम्प्लिमेंटेशन में ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है, वह रोल बहुत नकारात्मक रहा है, बहुत निगेटिव रहा है और मुझे लगता है कि डेलिब्रेट उनका ऐसा रोल रहा है कि अक़लियतों तक, खास तौर पर मुसलमानों तक उनका हिस्सा और हक न मिले। आज जब बड़ी-बड़ी बात हो रही है और यह कहा जा रहा है कि 90 जिले हमने मुन्तखिब किए हैं, मेरे साथियों को आपने एक हथियार भी दे दिया है, माइनॉरिटीज़ पर हमला करने का और यह कहने का कि उनका बहुत बड़ा तुष्टिकरण हो रहा है, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि 60 बरस से यह तो यही ऐलान कर रहे हैं, क्या 60 बरस में मुसलमानों का कोई भला हुआ, अगर नहीं हुआ तो आपको क्यों परेशानी हो रही है। अभी भी नहीं होने वाला, न पहले हुआ था, न अब होने वाला है, क्योंकि इनके इंटेशंस हमेशा यह रहे हैं कि सिर्फ दिखावा करो। हमें अगर इन पर ऐतबार होता, ग़ालिब का शेर है *'खुशी से मर न जाते, अगर ऐतबार होता'*, तो हमें तो ऐतबार नहीं है, अगर ऐतबार होता तो हम तो यहीं मर जाते खुशी से कि ये वाकई पूरा करने वाले हैं। तो इनका इरादा न पहले था, न आज है, न ईमानदारी से पहले किया था, न आज ईमानदारी से ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर : आप दोनों बातें कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री शाहिद सिद्दिकी : तारिक भाई, एक ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि : ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): आप तो खुद कह रहे हैं कि नीयत अच्छी है, तो फिर आगे बोलने की जरूरत ही क्या है। ...**(व्यवधान)**...

श्री शाहिद सिद्दिकी : सुनिए तारिक भाई, एक होता है इन्डिविज्युअल इंटेंशन, इन्डिविज्युअल इंटेंशन मनमोहन सिंह जी का बहुत नेक है, बहुत सेकुलर है, ...**(व्यवधान)**... क्लेक्टिव नहीं, क्लेक्टिव जो होता है, क्लेक्टिव इंटेंशन आप भी जानते हैं ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Siddiqui, you address the Chair. Please address the Chair.

श्री शाहिद सिद्दिकी : इन्डिविज्युअल इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन कलेक्टिव इंटेंशंस गलत रहे हैं, अगर न होते तो 60 बरस में यह हश्र न होता, जो आज 'सच्चर' कह रहे हैं।

सर, दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से हिन्दुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी बनाकर जगह-जगह पेश किया जा रहा है, जिस तरह से लड़के महाराष्ट्र में गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जिस तरह बंगलौर में गिरफ्तार किए जा रहे हैं, हम सारे मुस्लिम एम0पी0 मिलकर प्रधानमंत्री जी के पास गए थे, हम महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के पास भी गए थे, हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह मुसलमानों को मुसलसल बदनाम करने का एक पूरा अभियान है और हमारा हर बच्चा आज अपने घर में बैठा हुआ खौफ महसूस कर रहा है, आज वह नौकरी के लिए एप्लाई करते हुए खौफ महसूस करता है, वह जहां जाता है, उसे शक की निगाह से देखा जाता है, उसको यह समझा जाता है कि वह आतंकवादी है। इस माहौल को अगर हम ठीक नहीं करेंगे, तो यह मुसलमान के लिए तो नुकसानदेह होगा ही, वह तो कुचला जा चुका है बहुत ज्यादा, लेकिन यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इस माहौल को ठीक करने के लिए बाकायदा पॉलिसी की जरूरत है। श्री मुंशी जी मौजूद हैं, उनके पास तंत्र हैं प्रोपेगेंडे के, उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आज किसी को भी पकड़कर कह दिया जाता है, गिरफ्तारी होती नहीं है और उसको 'हुजी' आदि से जोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब खबर आती है कि यह गलत था तो उसका कोई प्रचार नहीं

होता, उसकी सच्चाई सामने नहीं आती। अभी देवबंद में इतना बड़ा इज्तमा हुआ, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तमा था और यह दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम हुआ है, जो देवबंद में तमाम मदरसों के तमाम उलेमाओं ने जमा होकर जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है, वह हिन्दुस्तान के हर मुसलमान के दिल की आवाज है और इन मुसलमानों के दिलों को छूकर ही आप आतंकवाद से लड़ सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी फौज, अमेरिका की मदद, इज़राइल की मदद आपको आतंकवाद से लड़ने में नहीं मदद करेगी, आतंकवाद से लड़ेगा तो हिन्दुस्तान का मुसलमान लड़ेगा और सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं, सर, कि पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान का मुसलमान आतंकवाद से लड़ने वाला है, क्योंकि हिन्दुस्तान का जो इस्लाम है, हिन्दुस्तान में इस्लाम की जो रूह है, जिस तरह से वह उभरी है, वह रूह मुहब्बत की, भाईचारे की, सबको साथ लेकर चलने वाली आत्मा है और उस बात का ऐतराफ पूरी दुनिया करती है, उस बात का ऐतराफ दुनिया को करना पड़ता है, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का किया है, लेकिन देवबंद का जो एक फैसला हुआ है, इसको जिस तरह से पब्लिसिटी मिलनी चाहिए थी, वह नहीं की गई। कोई थर्ड क्लास, कोई मुफ्ती, कोई छोटा-मोटा, जिसकी कोई पहचान नहीं है, वह कहीं कुछ कह दे तो कह दिया जाता है कि फतवा दे दिया, सारे मुसलमान इस फतवे के पीछे हैं। उसके बाद सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जब सारे उलेमा मिलकर एक फैसला ले रहे हैं, तो उसका जिस तरह से प्रचार होना चाहिए ...**(व्यवधान)**...

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : आपने सही फरमाया कि इतने बढ़िया ढंग से, बेहतरीन ढंग से, सभी प्राइवेट चैनल्स को बुलाकर इसका प्रोजैक्शन कराया, उनके लोग खुद हमसे आकर मिले। मदनी साहब, पता नहीं हाऊस में मौजूद हैं या नहीं? मैंने उनसे बात की तो उन्होंने खुद इस बात को कहा कि बहुत बढ़िया ढंग से हुआ। इस प्रयास को मैं अभी भी जारी कर रहा हूं कि चल क्या रहा है? पाकिस्तान के अखबार से लेकर बंगलादेश, इंडिया... इतनी भी मुझे खबर मिली है कि इंडोनेशिया के कुछ पत्रकारों ने भी इसका ज़िक्र किया। वह सारी चीज़ मैं आपको पेश कर दूंगा। आपने सही फरमाया ...**(व्यवधान)**...

श्री शाहिद सिद्दिकी : आपका बहुत धन्यवाद कि आपने उर्दू चैनल पर दिखाया, लेकिन उर्दू चैनल क्या किसी ने देखा है? ....**(व्यवधान)**....

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : डी.डी. पर दिखाया, दूरदर्शन पर।

श्री शाहिद सिद्दिकी : दूरदर्शन पर तो आपने वह छूटा हुआ दिखाया।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : सीएनएन आईबीएन पर, एनडीटीवी पर, ज़ी पर और आईएनएक्स पर, सब पर दिखाया, तीन दिन तक दिखाया।

श्री शाहिद सिद्दिकी : उसके ऊपर जिस तरह देश में चर्चा होनी चाहिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि खाली आपका कुसूर नहीं, हम सबका कुसूर है कि जिस तरह चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की तरफ से जब कोई पॉज़िटिव काम होता है, तो उसको दबाया जाता है। यह हम लोगों का रोज़ का experience है। अगर हम कोई अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, देशभक्ति का स्टेटमेंट देते हैं, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आदमी कोई negative स्टेटमेंट दे दे, जिसको कोई न पहचानता हो, उसको हीरो बना दिया जाता है, उसको बढ़ाकर पेश किया जाता है, तो मुसलमानों का जो एक बुरा चेहरा है, वह बार-बार पेश किया जा रहा है। उर्दू चैनल के बारे में मैं मुंशी जी से कहना चाहूंगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उर्दू चैनल की बात भी की है, अपनी पीठ थपथपाई है, सरकार की पीठ थपथपाई है, मैं इनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूं कि आपने उर्दू का चैनल पहले शायद आठ-दस घंटे का किया, फिर अब चौबीस घंटे का कर दिया है, लेकिन यहां बैठे हुए मेरे बहुत सारे साथी हैं, जो उर्दू जानते हैं, उर्दू देखते हैं, हमारे तो प्रधान मंत्री ही उर्दू जानने वाले आदमी हैं, लेकिन उर्दू का चैनल किसी को नज़र नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है। जंगल में मोर नाचा वाला मामला है, उसको आप एक घंटे का दिखाइए, दो घंटे का दिखाइए, लेकिन दिखाइए तो सही !

लोगों को मिले तो सही ! उर्दू भी आपका एक हथियार है जो लड़ने वाला है कम्युनलिज्म से। वह हथियार है, जो पाकिस्तान से लड़ने वाला है। वह हथियार है, जो आतंकवाद से लड़ने वाला है, तो इस उर्दू की ताकत को समझिए, यह हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने वाली ज़बान है। अंग्रेज़ी से पहले, पूरे हिंदुस्तान को अगर किसी ने बांधा था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो वह उर्दू ज़बान थी। यही उर्दू की ताकत है कि उर्दू पूरे देश में फैली हुई है और उर्दू की यही बदकिस्मती है कि यह किसी एक राज्य की ज़बान नहीं है और राज्य उसके साथ नहीं होता, राज्य का बजट नहीं होता, राज्य की ताकत नहीं होती, उसके पीछे पूरे देश की ताकत है, लेकिन यही उसकी कमज़ोरी बन जाती है। इसलिए उर्दू को उसका हक दीजिए और उर्दू चैनल को आप publicise कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है।

महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि विदेश नीति की बात हुई है, विदेश नीति आपकी जिस तरह से चलती रही है, उसमें जहां बहुत सी बातें हैं जिन पर हम कह सकते हैं, लेकिन एक खास बात की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं कि इज़राइल शायद हमारा दोस्त हो सकता है, लेकिन हम अपने देश की सिक्योरिटी इज़राइल के हवाले नहीं कर सकते। अभी कल ही इज़राइल के जो जहाज़ हैं, उन्होंने सैटेलाइट्स की मदद से कुछ Palestinian लीडर्स को खत्म किया, बच्चों के स्कूलों पर बम गिराए। आप उनको स्पाई-सैटेलाइट दे रहे हैं, जिनका प्रयोग वे हमले करने के लिए कर सकें, दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकें, क्या यह हमारे देश के हित में है? हम यह कहते हैं कि इसरो को इज़राइल से कुछ पैसा मिलने वाला था, लेकिन हमें जो पैसा मिलता है, वैस्ट एशिया से, जो हमारे लोग वहां काम करते हैं और जब वैस्ट एशिया में पीस खतरे में पड़ता है, अमन खतरे में पड़ता है ..**(समय की घंटी)**.. तो तेल के दाम बढ़ते हैं। उस तेल के दाम से हमें हज़ारों करोड़ का नुकसान होता है। क्या यह हमारे देश के हित में होगा कि ईरान के ऊपर हमला हो? अगर ईरान पर हमला होगा, तो हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। ...**(व्यवधान)**....

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन) : Conclude कीजिए।

श्री शाहिद सिद्दिकी : इसलिए हमें इस बात का ध्यान करना चाहिए। आपको परवाह नहीं है इस देश के बीसियों करोड़ लोगों की, इस देश के चौदह-पंद्रह करोड़ मुसलमानों के जज्बात की आपको परवाह नहीं है कि वे समझते हैं कि इज़राइल गासिब है। इज़राइल ने उनके साथ अन्याय किया है, उनके तीसरे सबसे मुकद्दस मक़ाम पर, मस्जिद-ए-अक्सा पर 1964 से कब्ज़ा कर रखा है। उनका अपमान हो रहा है पूरी दुनिया में ! जिस तरह से फिलिस्तीनियों को खत्म किया जा रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमान के दिल में बहुत बड़ा दर्द है।

यह बात बुश साहब भी जानते हैं कि सबसे बड़ा कांटा मुसलमानों के दिल में है तो वह Palestinians का है। यह कांटा हमारे दिल में भी है। उसके बावजूद आप इज़राइल से इतनी दोस्ती दिखाते हैं, इतनी मोहब्बत दिखाते हैं। आपको हिन्दुस्तान के मुसलमान की परवाह नहीं है, आपको अमेरिका की जुईश लॉबी की परवाह है, जुइश लॉबी हमारी फॉरेन पॉलिसी को influence कर सकती है लेकिन अगर हम कुछ कहते हैं तो कहा जाता है कि आप फॉरेन पॉलिसी को कम्युनलाइज़ कर रहे हैं। हम कम्युनलाइज़ नहीं कर रहे, हम नहीं करना चाहते। हम बिल्कुल मुखालफत करते हैं, हम देश के हित में बात कहते हैं। और हम देश के हित में कह रहे हैं कि इज़राइल से दोस्ती देश के हित में नहीं है, अमेरिका से दोस्ती देश के हित में नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी.जे.कुरियन) : सिद्दिकी साहब, अब खत्म करिए। Please conclude now.

श्री शाहिद सिद्दिकी : मैं खत्म कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि

न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की।
घुट के मर जाओ, ये मर्ज़ी है, मेरे सैयाद की।

हमें तो कलपने की भी इजाज़त नहीं देते। सर, मैं अपनी बात फैज़ के इन अशार से खत्म करूंगा, जो किसानों के लिए किया है और सच्चर कमेटी की जो डुगडुगी बजाई है, उस पर मैं यह कह रहा हूं:

ये दाग-दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सहर है,
वह इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।
ये वो सहर तो नहीं, जिसकी आरजू लेकर,
चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं।
फलक के दश्त में तारों की आखरी मंज़िल,
अभी गिरानी-ए-शब में कमी नहीं आयी।
निजात-ए-दीदा व दिल की घड़ी नहीं आयी।
चले चलो कि वो मंज़िल अभी नहीं आयी।

इस प्रकार अभी आपको और हमको बहुत दूर जाना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

†[شری شاہد صدیقی ''اتر پردیش'': سر، دھنیواد۔ راشٹر پتی جی کے ابھیبھاشن کے سمرتھن میں آؤٹ سائڈ سپورٹ کی بات جیسے پچوری جی نے کہی تھی، میں بھی آؤٹ سائڈ سپورٹ پردان کر رہا ہوں۔ راشٹر پتی جی نے سب سے مہتو پورن بات inclusive growth کی کہی، لیکن اس inclusive growth کی پول ارجن سین گپتا رپورٹ نے کھول دی۔ انہوں نے کسانوں کی inclusive growth، عام آدمی کی inclusive growth کی بات کی، لیکن کس طرح سے اس دیش کے ۷۵ فیصد سے زیادہ لوگ ۲۰ روپے روز پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں، یہ انہیں پتا نہیں ہے۔ اس inclusive growth کی اصلیت کو سچر کمیٹی نے کھول دیا ہے کہ کس طرح سے ۶۰ سالوں میں مسلمانوں کو اس گروتھ سے باہر رکھا گیا ہے، انہیں ۶۰ سال سے اس دیش کے ڈیولپمنٹ سے باہر رکھا گیا ہے۔ سچر کمیٹی نے اس inclusive growth کی پول پوری طرح سے کھول دی۔ کسانوں کو وکاس سے کس طرح سے باہر رکھا گیا، اس کی پول سوامی ناتھن کمیٹی نے کھول دی۔ آپ کے ہی بنائے گئے کمیشنوں نے آپ کی پول کھول دی کہ کس طریقے سے اس دیش میں uneven growth ہوئی ہے۔ جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اس میں کسی کو بھی برابری کی حصہ داری نہیں ملی ہے، چاہے وہ کسان ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے غریب ہیں، چاہے مہیلائیں ہیں اور چاہے عام آدمی ہے، سب کو آپ نے باہر رکھا ہے، وںچت رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کی گروتھ ہوئی ہے۔ اس لئے inclusive growth کی بات کم سے کم آپ کی سرکار نہ کرے، تو زیادہ اچھا ہوگا۔

مہودے، کسانوں کی بات کی گئی ہے۔ ہم اس پر تفصیل میں بجٹ پر چرچہ کے دوران بات کریں گے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے کسانوں کو ٹھگنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا خمیازہ پورے سماج کو بھگتنا پڑیگا۔ مجھے اور آپ کو نہیں، خالی سرکار کو نہیں، کیوں کہ آپ نے ان لوگوں کی امیدیں اتنی بڑھادی ہیں، جو اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہیں ان لوگوں کی جو اپنی جان دے رہے ہیں، جو جانتے ہیں کہ ان

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

کی شام کی روٹی کا پتہ نہیں، کل کو ان کے تن پر کپڑا ہوگا یا نہیں، ان کی امیدیں آپ نے بڑھادی ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ ان کی امیدیں پوری کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو کسانوں کے ساتھ دھوکہ ہے، اس پر

حیبلی جی نے بڑی اچھی طرح سے روشنی ڈال دی ہے، اس لئے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو آپ بازار بھاؤ کی بات کرتے ہیں، تو کسانوں کو ان کے اناج کا بازار بھاؤ کیوں نہیں دیتے؟ ان کے اناج پر آپ کیوں کنٹرول رکھتے ہیں، جب کہ ہر چیز کسان بازار بھاؤ سے خریدتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا خریدتا ہے بازار بھاؤ سے، کھاد خریدتا ہے بازار بھاؤ سے، تیل خریدتا ہے بازار بھاؤ سے؟ بازار کے بھاؤ بڑھتے چلے جارہے ہیں، آسمان پر جارہے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ پیٹرول کے دام بڑھانے پر مجبور ہیں، کیوں کہ دنیا میں تیل کے دام بڑھ گئے ہیں۔ کیا دنیا میں گیہوں کے دام نہیں بڑھے ہیں؟ اگر دنیا میں گیہوں کے دام بڑھے ہیں تو وہ آپ میرے کسان کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ امریکہ کو، انگلینڈ کو، وال۔ناٹ کو، سب کو دنیا کے بھاؤ دینے کو تیار ہیں اور ہمارے بہت بڑے بڑے اکانامسٹ جو اس دیش کو چلا رہے ہیں، وہ اکانامسٹ جانتے ہیں کہ گلوبل اکانامی کیا ہے، گلوبل مارکیٹ کیا ہے، لیکن کسان کو آپ وہ دام دینے کو تیار نہیں ہیں، کسان کی پروڈکٹ کے دام پر آپ کنٹرول رکھتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک کسان کی جو پروڈکٹ ہے، اس میں انہیں منافع نہیں ملے گا، اس کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ یہی ہماری ڈیمانڈ تھی، اسی لئے ہم نے آواز اٹھائی۔ آپ نے کسان کو اس طرح سے کردیا ہے کہ وہ بھوکا ہے، کھانے کو نہیں ہے، بچوں کے کھانے کو نہیں ہے اور آپ نے اس کی بہت بھاری دعوت کردی، اس دعوت میں آپ نے بہت مزا دیا کہ پوریاں، حلوے کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ ایک دن۔ اب اگر وہ ایک دن کھائے گا، تو وہ ایک دن کھا کر بیمار ہوجائے گا، اگلے دن کیا کریگا؟ اس کے اگلے دن کا آپ نے انتظام نہیں کیا۔ آپ ایک آدمی کو پیٹ بھر کر ایک دن، دو دن کھلا دو، اس سے کام نہیں بنتا۔ اس کا کسان کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے لئے سرکار نے کوئی پالیسی نہیں بنائی۔ اس پر تو تفصیل میں بجٹ میں بات ہوگی، مگر ایک اور بنیادی مدعے پر میں آنا چاہتا ہوں: جس مدعے کو آپ مسلسل انڈر ردی کارپیٹ کھسکاتے جارہے ہیں اور وہ ہے اس دیش کی مائنارٹیز کا سوال۔

مہودے، آپ نے سچر کمیٹی [illegible]، اس کی رپورٹ آئی اور اس رپورٹ پر بار بار مانگ کے باوجود یہاں پر بحث نہیں ہوئی۔ جسٹس رنگ ناتھ مشرا کی رپورٹ آئی، اس پر آپ نے ہاؤس میں بحث نہیں کرائی۔

†[]Transliteration in Urdu Script.

سوال یہ ہے کہ آپ سروشکشا ابھیان چلا رہے ہیں، آپ کی جواہر روزگار یوجنا ہے، آپ کی اندرا آواس یوجنا ہے، ڈھیروں یوجنائیں آپ لمبے عرصے سے، ساٹھ برسوں سے چلا رہے ہیں، طرح طرح کی یوجنائیں، کچھ لوگوں کے نام سے چلتی رہتی ہیں، لیکن اس میں آپ نے مائنارٹیز کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ وہ حصہ کیوں نہیں ملا؟.....مداخلت.....حصہ دیا ہوتا، تو آج سچر یہ نہ کہتے، جو انہیں کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے دو فیصد بھی حصہ نہیں دیا۔ میرے پاس بہت سارے آنکڑے موجود ہیں، سارے آنکڑے سچر کے دئے ہوئے ہیں۔ اگر اسے پڑنا شروع کرونگا، تو بہت وقت لگے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ iinclusive growth میں آپ نے ان کو کہیں شامل نہیں کیا ہے اور اس کی وجہ ہے، میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں، آپ کی انٹینشن اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں اس دیش میں جو پرابلم رہی ہے، وہ انٹینشنس کی نہیں امپلی مینٹیشن کی رہی ہے۔ انٹینشن اچھے ہوتے ہیں، بنگال میں سرکار ہے، اس کے انٹینشن اچھے رہے، بہت سیکولر سرکار ہے، مگر بنگال میں مائنارٹیز کی خاص طور سے مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے۔ اتر پردیش، بہار میں بھی حالت اچھی نہیں ہے۔ تو اس پر میں پردھان منتری جی سے کہنا چاہونگا کہ آپ اس پر غور کیجئے کہ کیوں ان اچھے انٹینشنس کا امپلی مینٹیشن نہیں ہو پاتا؟ میں آپ کے سیکولر انٹینشنس پر ڈاؤٹ نہیں کر رہا، لیکن اصل پرابلم پر ہم نہیں جاتے ہیں۔ اصل پرابلم امپلی میٹیشن کی ہے اور امپلی میٹیشن میں بیوروکریسی کا جو رول ہے، وہ رول بہت نکارا تمک رہا ہے، بہت نگیٹو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیلیور یٹ ان کا ایسا رول رہا ہے کہ اقلیتوں تک خاص طور پر مسلمانوں تک ان کا حصہ اور حق نہ ملے۔ آج جب بڑی بڑی بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ۹۰ ضلع ہم نے منتخب کئے ہیں، میرے ساتھیوں کو آپ نے ایک ہتھیار بھی دے دیا ہے، مائنارٹیز پر حملہ کرنے کا اور یہ کہنے کا کہ ان کا بہت بڑا تشٹی کرن ہو رہا ہے، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ۶۰ برسوں سے یہ تو یہی اعلان کر رہے ہیں، کیا ۶۰ برس میں مسلمانوں کا کوئی بھلا ہوا، اگر نہیں ہوا تو آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے۔ ابھی بھی نہیں ہونے والا، نہ پہلے ہوا تھا، نہ اب ہونے والا ہے، کیوں کہ ان کے انٹینشنس ہمیشہ یہ رہے ہیں کہ صرف دکھاوا کرو۔ ہمیں اگر ان پر اعتبار ہوتا، لب کا شعر ہے ۔

خوشی سے مر نہ جاتے، اگر اعتبار ہوتا

---

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

...تو ہمیں تو اعتبار نہیں ہے، اگر اعتبار ہوتا تو ہم تو یہیں پر مر جاتے خوشی سے کہ یہ واقعی پورا کرنے والے ہیں۔ تو ان کا ارادہ نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ ایماندرای سے پہلے کیا تھا، نہ آج ایمانداری سے --مداخلت--

شری طارق انور: آپ دونوں بات کر رہے ہیں --مداخلت--

شری شاہد صدیقی: طارق بھائی، ایک --مداخلت--

شری رودر نرائن پانی: زیادہ غلط نہیں ہے، لیکن صحیح بھی نہیں ہے --مداخلت--

شری راجیو شکلا: آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ نیت اچھی ہے، تو پھر آگے بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے --مداخلت--

شری شاہد صدیقی: سنیے طارق بھائی، ایک ہوتا ہے کہ انڈیو بجول اٹینشن، انڈیو بجول اٹینشن منموہن سنگھ جی کا بہت نیک ہے، بہت سیکولر ہے، --مداخلت-- کلیکو نہیں، کلیکو جو ہوتا ہے، کلیکو اٹینشن آپ بھی جانتے ہیں --مداخلت--]†

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Mr. Siddiqui, you address the Chair. Please address the Chair.

†[**شری شاہد صدیقی:** انڈیو بجول اٹینشن بہت اچھے ہیں، لیکن کلیکو اٹینشن غلط رہے ہیں، اگر نہ ہوتے تو ساٹھ برس میں یہ حشر نہ ہوتا، جو آج 'سچر' کہہ رہے ہیں۔

سر، دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح سے ہندوستان کے مسلمانوں کو آتنک وادی بنا کر جگہ جگہ پیش کیا جا رہا ہے، جس طرح سے لڑکے مہاراشٹر میں گرفتار کئے جا رہے ہیں، جس طرح سے بنگلور میں گرفتار کئے جا رہے ہیں، ہم سارے مسلم ایم. پیز مل کر پردھان منتری جی کے پاس گئے تھے، ہم مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کے پاس بھی گئے تھے، ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو مسلسل بدنام کرنے کا ایک پورا ابھیان ہے اور ہمارا ہر آج اپنے گھر میں بیٹھا ہوا خوف محسوس کر رہا ہے، آج وہ نوکری کے لئے اپلائی کرتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے، اسے شک کی نگاہ سے دیکھا

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

جاتا ہے، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آتنک وادی ہے۔ اس ماحول کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے، تو یہ مسلمان کے لئے تو نقصاندہ ہوگا ہی، وہ تو کچلا جا چکا ہے بہت زیادہ، لیکن یہ دیش کے لئے اچھا نہیں ہوگا۔ اس ماحول کو ٹھیک کرنے کے لئے باقاعدہ پالیسی کی ضرورت ہے، شری منشی جی موجود ہیں، ان کے پاس تنتر ہیں پروپیگنڈہ کے، ان کا صحیح استعمال ہونا چاہئے، کیوں کہ آج کسی کو بھی پکڑ کر کہہ دیا جاتا ہے، گرفتاری ہوتی نہیں ہے اور اس کو 'ہوجی' وغیرہ سے جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب خبر آتی ہے کہ وہ غلط تھا تو اس کا

کوئی پرچار نہیں ہوتا، اس کی سچائی سامنے نہیں آتی۔ ابھی دیوبند میں اتنا بڑا اجتماع ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اقدام ہوا ہے، جو دیوبند میں تمام مدرسوں کے تمام علماؤں نے جمع ہو کر جس طرح سے آتنک واد کے خلاف آواز اٹھائی ہے، وہ ہندوستان کے ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے اور ان مسلمانوں کے دلوں کو چھو کر ہی آپ آتنک واد سے لڑ سکتے ہیں۔ آپ کی اعلیٰ جینس، آپ کی فوج، امریکہ کی مدد، اسرائیل کی مدد آپ کو آتنک واد سے لڑنے میں نہیں مدد کرے گی، آتنک واد سے لڑے گا تو ہندوستان کا مسلمان لڑے گا اور صرف ہندوستان میں ہی نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں سر، کہ پوری دنیا میں ہندوستان کا مسلمان آتنک واد سے لڑنے والا ہے، کیوں کہ ہندوستان کا جو اسلام ہے، ہندوستان میں اسلام کی جو روح ہے، جس طرح سے وہ ابھری ہے، یہ روح محبت کی، بھائی چارے کی، سب کو ساتھ لے کر چلنے والی آتما ہے اور اس بات کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے، اس بات کا اعتراف دنیا کو کرنا پڑتا ہے، پردھان منتری نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، لیکن دیوبند کا جو ایک فیصلہ ہوا ہے، اس کو جس طرح سے پبلیسٹی ملنی چاہئے تھی، وہ نہیں کی گئی۔ کوئی تھرڈ کلاس، کوئی مفتی،

کوئی چھوٹا موٹا، جس کی کوئی پہچان نہیں ہے، وہ کہیں کچھ کہہ دے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ فتوی دے دیا، سارے مسلمان اس فتوے کے پیچھے ہیں۔ اس کے بعد سارے مسلمانوں کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، لیکن جب سارے علماء ملکر ایک فیصلہ لے رہے ہیں، تو اس کا جس طرح سے پرچار ہونا چاہئے... مداخلت...

وزیر برائے پارلیمانی امور "شری پریہ رنجن داس منشی" : آپ نے صحیح فرمایا کہ اتنے بڑھیا ڈھنگ سے، بہترین ڈھنگ سے، سبھی پرائیویٹ چینلو کو بلا کر اس کا پروجیکشن کرایا، ان کے [illegible] خود ہم سے آکر ملے۔

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

مدنی صاحب، پتا نہیں ہاؤس میں موجود ہیں یا نہیں؟ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے خود اس بات کو کہا کہ بہت بڑھیا ڈھنگ سے ہوا۔ اس پر یاس کو میں ابھی بھی جاری کر رہا ہوں کہ چل کیا رہا ہے؟ پاکستان کے اخبار سے لیکر بنگلہ دیش، انڈیا.. اتنی بھی مجھے خبر ملی ہے کہ انڈونیشیا کے کچھ پترکاروں نے بھی اس کا ذکر کیا۔ وہ ساری چیز میں آپ کو پیش کر دونگا۔ آپ نے صحیح فرمایا.....مداخلت....

شری شاہد صدیقی: اپ کا بہت دھنیواد کہ آپ نے اردو چینل پر دکھایا، لیکن اردو چینل کیا کسی نے دیکھا ہے؟ .....مداخلت...

شری پریہ رنجن داس منشی: ڈی ڈی پر دکھایا، دوردرشن پر۔

شری شاہد صدیقی: دوردرشن پر تو آپ نے وہ چھوٹا ہوا دکھایا۔

شری پریہ رنجن داس منشی: سی این این، آئی بی این پر، این ڈی ٹی وی پر، زی پر اور آئی این ایکس پر، سب پر دکھایا، تین دن تک دکھایا۔

شری شاہد صدیقی: اس کے اوپر جس طرح دیش میں چرچہ ہونی چاہئے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالی آپ کا قصور نہیں، ہم سب کا قصور ہے کہ جس طرح چرچا ہونی چاہئے، کیوں کہ مائنارٹیز کی طرف سے جب کوئی پازیٹیو کام ہوتا ہے، تو اس کو دبایا جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کا روز کا experience ہے۔ اگر ہم کوئی اچھا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، دیش بھکتی کا اسٹیٹ منٹ دیتے ہیں، تو اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ آدمی کوئی negative اسٹیٹ منٹ دے دے، جس کو کوئی نہ پہچانتا ہو، اس کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اس کو بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کا جو ایک برا چہرہ ہے، وہ بار بار پیش کیا جا رہا ہے۔ اردو چینل کے بارے میں میں منشی جی سے کہنا چاہونگا، کیوں کہ راشٹرپتی جی نے اپنے ابھیبھاشن میں اردو چینل کی بات بھی کی ہے، اپنی پیٹھ تھپتھپائی ہے، سرکار کی پیٹھ تھپتھپائی ہے۔ میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اردو کا چینل پہلے شاید آٹھ دس گھنٹے کا کیا، پھر اب چوبیس گھنٹے کا کر دیا ہے، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے میرے بہت سارے ساتھی ہیں، جو اردو جانتے ہیں، اردو دیکھتے ہیں، ہمارے تو [illegible] منتری ہی اردو جاننے والے آدمی ہیں، لیکن اردو کا چینل کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، مل نہیں رہا ہے۔ جنتا میں مورنا چار والا معاملہ ہے۔ اس کو آپ ایک گھنٹے کا دکھایئے، دو

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

گھنٹے کا دکھایئے، لیکن دکھایئے تو سہی! لوگوں کو ملے تو سہی! اردو بھی آپ کا ایک ہتھیار ہے جو لڑنے والا ہے کمیونلزم سے۔ وہ ہتھیار ہے، جو پاکستان سے لڑنے والا ہے۔ وہ ہتھیار ہے، جو آتنک واد سے لڑنے والا ہے، تو اس اردو کی طاقت کو سمجھئے یہ ہندستان کو ایک دھاگے میں باندھنے والی زبان ہے۔ انگریزی سے پہلے، پورے ہندستان کو اگر کسی نے باندھا تھا کشمیر سے کنیا کماری تک، تو وہ اردو زبان تھی یہی اردو کی طاقت ہے کہ اردو پورے دیش میں پھیلی ہوئی ہے اور اردو کی یہی بدقسمتی ہے کہ یہ کسی ایک راجیہ کی زبان نہیں ہے اور راجیہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، راجیہ کا بجٹ نہیں ہوتا، راجیہ کی طاقت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے پورے دیش کی طاقت ہے، لیکن یہی اس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ اس لئے اردو کو اس کا حق دیجئے اور اردو چینل کا آپ پہلے سلائز کیجئے اور لوگوں تک پہنچایئے، یہی میری آپ سے درخواست ہے۔

مہودے، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ودیش نیتی کی بات ہوئی ہے، ودیش نیتی آپ کی جس طرح سے چلتی رہی ہے، اس میں جہاں بہت سی باتیں ہیں جن پر ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک خاص بات کی اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل شاید ہمارا دوست ہوسکتا ہے، لیکن ہم اپنے دیش کی سیکورٹی اسرائیل کے حوالے نہیں کرسکتے۔ ابھی کل ہی اسرائیل کے جو جہاز ہیں، انہوں نے سیٹیلائیٹ کی مدد سے کچھ فلسطینی لیڈروں کو ختم کیا، بچوں کے اسکولوں پر بم گرائے۔ آپ ان کو اسپائی سیٹیلائٹ دے رہے ہیں، جن کا استعمال وہ حملہ کرنے کے لئے کرسکیں، دوسرے دیشوں کو نقصان پہنچانے کے لئے کرسکیں، کیا یہ ہمارے دیش کے ہت میں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرو کو اسرائیل سے کچھ پیسہ ملنے والا تھا، لیکن ہمیں جو پیسہ ملتا ہے، ویسٹ ایشیا سے، جو ہمارے لوگ وہاں کام کرتے ہیں اور جب ویسٹ ایشیا میں پیس خطرے میں پڑتا ہے، امن خطرے میں پڑتا ہے.... ..... ''وقت کی گھنٹی'' .....

...تو تیل کے دام بڑھتے ہیں۔ اس تیل کے دام سے ہمیں ہزاروں کروڑ کا نقصان ہوتا ہے۔ کیا یہ ہمارے دیش کے ہت میں ہوگا کہ ایران کے اوپر حملہ ہو؟ اگر ایران پر حملہ ہوگا، تو ہمارا سب سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے.....مداخلت.....

اُپ سبھاادھیکش ''شری پی۔ آر۔ کمار'': کنکلوڈ کیجئے۔

---

†[ ]Transliteration in Urdu Script

شری شاہد صدیقی : اس لیے ہمیں اس بات کا دھیان کرنا چاہئے۔ آپ کو پرواہ نہیں ہے اس دیش کے بیسیوں کروڑ لوگوں کی، اس دیش کے چودہ پندرہ کروڑ مسلمانوں کے جذبات کی آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل غاصب ہے۔ اسرائیل نے ان کے ساتھ انیائے کیا ہے، ان کے تیسرے سب سے مقدس مقام پر، مسجد اقصیٰ پر ۱۹۶۴ سے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کا اپمان ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ہندوستان کے مسلمان کے دل میں بہت بڑا درد ہے۔ یہ بات بش صاحب بھی جانتے ہیں کہ سب سے بڑا کانٹا مسلمانوں کے دل میں ہے، تو وہ فلسطین کا ہے۔ وہ کانٹا ہمارے دل میں بھی ہے۔ اس کے باوجود آپ اسرائیل سے اتنی دوستی دکھاتے ہیں، اتنی محبت دکھاتے ہیں۔ آپ کو ہندوستان کے مسلمان کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو امریکہ کی جوئش لابی کی پرواہ ہے، جوئش لابی ہماری فارن پالیسی کو influence کر سکتی ہے لیکن اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ فارن پالیسی کو کمیونلائز کر رہے ہیں۔ ہم کمیونلائز نہیں کر رہے، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم بالکل مخالفت کرتے ہیں، ہم دیش کے ہت میں بات کہتے ہیں۔ اور ہم دیش کے ہت میں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے دوستی دیش کے ہت میں نہیں ہے، امریکہ سے دوستی دیش کے ہت میں نہیں ہے۔

اپ سبھاادھیکش (پروفیسر پی۔جے۔کورین): صدیقی صاحب، اب ختم کریئے۔

شری شاہد صدیقی: میں ختم کر رہا ہوں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ

نہ تڑپنے کی اجازت ہے، نہ فریاد کی — گھٹ کے مر جاؤ، یہ مرضی ہے، مرے صیاد کی

ہمیں تو تڑپنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ سر، میں اپنی بات فیض کے ان اشعار سے ختم کروں گا، جو کسانوں کے لئے کیا ہے اور سچر کمیٹی کی جو گڈگڈی بجائی ہے، اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں

یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر ہے — وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں

یہ وہ سحر تو نہیں، جس کی آرزو لے کر — چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں

فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل — ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی

نجات دہندہ و دل کی گھڑی نہیں آئی — چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

"ختم شد"

اس پرکار ابھی آپ کو اور ہم کو بہت دور جانا ہے۔ بہت بہت دھنیواد۔

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Prasanta Chatterjee, your party is left with one minute only. But you should conclude in ten minutes. ...(*Interruptions*)... What is left is one minute only, but you can conclude in ten minutes. I am giving you ten fold increase.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, I will try and finish my speech within the allotted time itself. Yesterday, our leader Comrade Sitaram Yechury elaborately recorded the views of CPI(M) on the Presidential Address, and also in the context of the Government's claim on economic growth and foreign affairs, particularly, on Israel and the Palestinian peoples' rights. I will confine my views to other arenas.

The views expressed in the speech of the hon. President appear to be one-sided as there is no admission of harsh realities. Many important issues affecting the common people have not found any place in her Address. How can we deny that every year, approximately, rupees one lakh crores are being accumulated as black money? Some reports have indicated this.

Prosperity for the rich and affluent, and deprivations for the majority of people is the essence of today's exclusive growth. India's position in the Human Development Index is 128 out of the total 177 countries while it was 126 last year. And, as per the Global Hunger Index, India's position is 94th.

Sir, the entire country is reeling under unprecedented price rise of every essential commodity. Systematic demolition of the entire Public Distribution System has added fuel to the fire. The Union Government is slashing down the quota of foodgrains for P.D.S. meant for Kerala and West Bengal. Just before the commencement of this Budget Session, the Union Government opted for hiking the prices of petrol and diesel for the eighth time, without taking the course of lowering down the taxes on fuel. It is obvious that this price hike will lead to further rise of prices of all essential commodities.

In spite of the growth of GDP to the extent of 8.5 per cent, the growth rate in the agricultural sector is only 2 per cent. This is a serious issue. Farmers should get agricultural inputs at cheaper prices and they should get remunerative prices for their products. Land reforms are extremely necessary. For implementation of these necessary steps, political will of the Union Government is the pre-condition. Unfortunately, these serious facts have not found any place in the Presidential Address.

Sir, time and again, we expressed our anxiety over the unemployment situation in the country. Employment in the public sector has declined from 194 lakhs in 1994 to 182 lakhs in 2004. Casualisation of labour, outsourcing and widespread use of contract workers have subjected workers to greater exploitation and deprived them of their rights. Unfortunately, these serious facts too have not found any place in the Presidential Address.

Sir, the hon. President, in her speech, expressed her pleasure for introduction of Unorganised Sector Social Security Bill, 2007. Unfortunately, the Bill is not in consistent with the Statement of Objects and Reasons appended with the Bill itself. The Bill contains neither a compelling provision regarding the floor level social security nor for the universal coverage of all unorganised sector workers. It also does not have a clearly defined funding obligation and a time frame.

The National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, appointed by the Union Government, has already presented its report on August 6, 2007, to the Prime Minister, with its detailed recommendations evolved after elaborate consultations with the Central

Trade Unions. The report includes two draft Bills titled "Agricultural Workers' Conditions of Work and Security Bill, 2007 and Unorganised Non-Agricultural Workers Social Security Bill, 2007." The Government is yet to take a decision on the recommendations made by the Commission set up by the UPA Government itself.

As such, the hon. President should have expressed her displeasure on the attitude of her Government towards the unorganised sector workers.

Sir, I have already mentioned India's position on Human Development Index and also on Global Hunger Index. The high incidence of malnutrition, high infant and maternal mortality rate, illiteracy etc. are the main reasons behind these shabby conditions. These problems should be addressed through ICDS.

Out of the total Rs.16.4 crores eligible children, only 6.29 crores are covered by ICDS, as on 31st December, 2007. The UPA Government is committed to universalize the ICDS in its NCMP. The Apex Court directed universalisation of the ICDS by the end of 2008.

Unfortunately, not a single word on this serious issue, involving mothers and children, has found a place in the President's Address.

Sir, the hon. President, in her speech, has expressed high satisfaction on the issue of Special Economic Zone. I do not know whether it is known to hon. President that the workers and employees working inside the Special Economic Zones are deprived of almost all labour rights, including Trade Union rights.

Sir, permit me to take up the performances of Indian Railways. The hon. President left no word of praise for Indian Railways. According to the hon. President, Indian Railways has achieved a major turnaround in the financial performances.

I beg to be excused by the Chair as well as by the Minister of Railways for my comments hereinafter.

Sir, once upon a time, Railways was the biggest employer in the country. Systematically, Indian Railways are privatising its services. In different sectors, railways is surrendering all vacant posts, closing the cadre and creating supernumerary posts and freezing the cadres. The railways have decided to close all ticket printing presses and general presses by August 1, 2009. It has also decided to outsource the jobs of printing.

Sir, I am afraid that hon. Minister for Railways has forgotten his own statement made on 10th September, 2004. On that day, in his address to a two-day conference of the General Managers of the Zonal Railways, the production units and the Kolkata Metro in Delhi, the hon. Minister for Railways said that he would rather quit than allow privatization, as the private sector would not meet the aspirations of the people. Making a total U-turn, the Railways have given an unprecedented emphasis on Special Purpose Vehicle, Public-Private partnership and Build-Operate-Transfer in wide areas of activities, from cleaning of coaches, building of flyovers, wagon ownership and management to gradually increased participation in infrastructure development.

Unfortunately, the President's speech has failed to address the important issues of continuous downsizing in Railways and outsourcing perennial nature of jobs in the name of public-private participation.

Sir, the Communal Violence Bill is still pending. The Standing Committee submitted its Report last year. This Bill has not come up as yet in the Parliament for discussion. The hon. Home Minister is here. I demand that this Bill should come up for discussion in the House

immediately. The issue of compensation for the victims was also deal there. The hon. Members from the Left Parties in the Standing Committee have given their comments.

Sir, my Party, alongwith the Left Parties, is rendering its support to the UPA Government on the basis of the National Common Minimum Programme. Time and again, we have cautioned the Government and demanded strict adherence to the NCMP. The Government should make an introspection of its performances, accept the realities and take corrective steps. With these few words, I conclude. Thank you.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for having given me this opportunity.

I am happy that I have this occasion to speak in favour of the Motion of Thanks on the President's Address. The Speech that the President delivered at the beginning of the Session undoubtedly marks the beginning of a new era of policies. There is no doubt that this Government, which had talked about and promised 'inclusive growth', has formulated a clear set of policies which will guarantee our progress towards inclusive growth. I thank the President, and, through the President, the Council of Ministers because this is something that we should actually rejoice.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) in the Chair.]

Mr. Vice-Chairman, Sir, I also want to point out that, time and again, there have been references made from different quarters to a report that has been submitted by a Commission under my chairmanship. What we did was, we looked into the official statistics just to examine one simple point, i.e., 'does economic growth automatically lead to inclusive growth?' It is a very simple proposition. And that is what we tried to examine with the statistics that we have. It is not my invention; it is the National Sample Survey which analysed the statistics of three quinquennial periods in 1993-04, 1999-2000 and 2004-05, the periods where our economy has grown in an uninterrupted way, at a very rapid pace. And what we find through our exercise that although the ...

SHRI MAHENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): Sir, sorry to disturb you. I would like to inform all of you that India has won the Tri series. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Thank you. Congratulations! Mr. Sengupta, you please continue.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Thank you. It is very good news. ...(*Interruptions*)...So, if I may continue, I would say that in spite of this very rapid economic growth, it so happens that the income and consumption of about 23 to 24 per cent of the population of our country has grown; their income and consumption has grown very rapidly in a steady way, whereas about three quarters of our population — in fact, we calculated 77 per cent ...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, I think, the Parliament can congratulate the Indian team.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): I think I have already said 'congratulations'. Let him continue. We are discussing a very serious thing. We will discuss that later. ...(*Interruptions*)... Please let him continue. Don't disrupt. This should not be disrupted. ...(*Interruptions*)... Shuklaji, its all right. It is very important for all of us. But let him complete and then we will celebrate. ...(*Interruptions*)...No; no; I will not allow. Let him complete. Senguptaji, please continue. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Sir, if I may continue because this is a point which ...*(Interruptions)*...

SHRI DINESH TRIVEDI (West Bengal): Sir, can I share the good news that India has won the Tri-series Final?

THE VICE-CHAIRMAN: No; you don't have to share it. ...*(Interruptions)*... You are too late. ...*(Interruptions)*... You are too late.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: As I mentioned, this is the result of our examination. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): No cross-talks, please. सेन गुप्ता जी, आप बोलिए।

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: This is the simple finding that if we really want to have 'inclusive growth', we cannot depend only on a high rate of economic growth. We did not talk about the period after 2004-05. I must mention this because a reference has been made to this report by different party leaders as if this report was against the current Government. It is nothing of that sort. Sir, the year 2004-05 is the last number which you have used. After that, a number of things have happened which we are discussing now, but our report is basically for the nineties period of high rate of economic growth. Mr. Vice-Chairman, I want to put forward that our report is completely non-partisan. Of those ten years, only the first few years were ruled by the Congress. The reforms process was initiated by Dr. Manmohan Singh and that has fruitioned into a very high rate of growth. But during that period, we had also the United Front Government, of which Shri Chidambaram was the Finance Minister. Two Communist leaders were members of that Government. They supported the policies of economic reforms. After that, it was the NDA, the BJP Government, which ran the show. So, this is not a partisan report. All the parties were involved. Now the time has come to introspect. What has happened? Why was it that the high rate of growth did not translate into a robust inclusive growth? That is the only question that we ask and we try to formulate some answers to that.

We have analysed the earlier periods of Nehruji; I do not want to talk about Indiraji's period. The only point I wanted to mention was that although the rate of growth during this period was only 3.75 to 4 per cent, this was three times the rate of growth of the previous thirty years. And during this period, we built up our capacity, built up our skills and built up our high industrial structure. All these things happened. But that is not the purpose of our report. The purpose of our report was very simple: how to have this inclusive growth?

Sir, the most important finding that we have is that if we want to have inclusive growth, then the growth and the policies related to growth must be targeted to the poorest of the poor. For that, we have to identify the small and marginal farmers, the unorganised workers, the very small enterprises which are employing less than ten units and having a capital of less than Rs. 25 lakhs. These are the people who are at the lowest rung of our total population. If I may say so, it also shows that this is the group to which most of the Muslims, most of the Dalits and most of the OBCs belong. So, it is a congruence of income poverty, social poverty and all kinds of deprivation. And they have to be looked after. If you want that inclusive growth, the policy should orient towards that. And the most important policy has to be to give them jobs. It so happens that almost 80 per cent of our unorganised, informal workers, workers who work only because they want to avoid starvation, work in conditions of total denigration. There is no job security; there is no light or sanitation. These people work in such poor conditions. So, they are employed in the sense that when the statistician

asks them, 'Do you work?', they say, 'yes, we work'. They don't ask them for how much money they work, what wages they get, what their working conditions were, and so on. If they did, then the entire situation would have been different. So, it is an issue of giving jobs to these people.

Sir, we also find that during this period, particularly during the later part of the period, in the organised sector, the factory sector, the growth of employment has practically come to zero. Whatever employment has been there in those factories, in those organized sectors, had been of the informal workers, workers who do not have social security, who do not have any other protection. They could be called unprotected workers. This is the universe, the universe which will actually provide livelihood to our poor, to our dalits, to our Muslims, to our OBCs. Definitely, I would say, that we must have all those reservation policies, social policies. But the first priority should be to give them jobs. How do you do that? I beg to say that unfortunately, up till now, in most of our policies, including our planning policies, this particular focus is missing. What has happened is that if we give particular assistance to agriculture, this goes to the larger sops. The poor, small and marginal farms do not get credit. Howsoever we may try, howsoever the Reserve Bank of India may dictate banks to extend loans, the fact of the matter is, hardly two per cent of the banking credit goes to these people. The small and tiny units, which we call small enterprises, contribute about 40 per cent of the GDP and they get only less than 4 per cent of our credit. So, the system has to be totally newly worked out with the specific emphasis of programmes for these people. Sir, the first important point is that allocation has to be made and I must congratulate Mr. Chidambaram that he has provided allocation. He provided allocation in the last Budget and in this Budget he has provided much more than that, and that is the first major condition that has been fulfilled. But that is not sufficient. You have to design programmes in such a way that they are actually delivered and the only design that will deliver them from the examination of the actual statistics is when people involved participate and when there is an accountability. Sir, we have seen the Rural Employment Guarantee Scheme. We have seen where this scheme has actually worked out. This Scheme has actually worked out where there are proper mechanisms of accountability. In Andhra Pradesh, they have tried the Social Audit System which has been enormously successful and that has to be universalised for the country as a whole so that people who are actually getting the benefit or not getting the benefit can stand up and say that they must get the benefit. The second most important point is that they should be provided as entitlement so that they can claim that, and if they do not secure, then there must be something to be done, there must be some compensation and somebody should be held responsible. Sir, I am putting it this way because the Rural Employment Guarantee Scheme has been talked about and we know what happened and I am glad today it has now become accepted. Although initially there were some problems to that. But there are certain other schemes.

The Finance Minister has just left, but if he were here he would have heard me that in his Speech he has talked about expanding Health Insurance Scheme. A number of schemes he has talked about. Mr. Prasanta Chatterjee talked about the Social Security Bill. The Social Security Bill is talking about the national minimum package of schemes to be given as entitlement to workers so that once that is given nobody can withdraw. It is not a scheme that the Government in every Budget provides and then changes. Governments come and Governments go, but if it is made into a right or if it is made into an Act, it remains. This is what the purpose of this Bill was. In fact, the Standing Committee's recommendations are built on the scheme that has been announced. If the Government accepts that, there will be

hardly any additional outgo because schemes are already there. But it will give a totally different picture. It has mechanism of monitoring; mechanism of evaluation and mechanism of dispute settlement. All these things are there in this particular Act.

Sir, I may mention the other point that has come out which is a very major breakthrough for small and marginal farmers and that is debt waiver. I must say that this is not the ideal way of dealing with small and marginal farmers. But this is the first essential step to recognise that these small and marginal farmers are the distressed people and I am very happy to say that our Government has announced that they recognise this. But this is not enough. We have to have programmes so that small and marginal farmers can actually get benefit. Dr. Swaminathan Report has talked about it; our Report has talked about it. There were many such programmes. During Indira*ji*'s time, we had a Small and Marginal Farmers Development Programme. We have to somehow reinvent them and reintroduce them and that is the way to go about small and marginal farmers programme.

Sir, I would like to point out two more things. The first most important point that we learnt from this is that the debts of small and marginal farmers are withdrawn. That is not sufficient condition that they will get loan again. This is a major point. I want this thing to be noted because if you just give up all the debt, you don't get additional money because most of the farmers are not paying that. But, they must prepare ground so that they can get fresh loans. The banks must get incentives to provide them loans. Up till now, statistics show that the commercial banks do not want to give loans to small and marginal farmers. Time and again, when programmes are announced, the small and marginal farmers are bypassed. If and when you tell the banks to give them money without any collateral, the farmers do not get loans. And, it is natural. Why should a commercial bank, which is asked to make profits, which is asked to minimise its non-performing assets, go and take a risky proposition? So, we have to create a particular system by which the banks are actually given incentives to provide loans. There is similarly the question of small units, micro units; not the small units having capital of Rs.20 lakh or Rs.25 lakh, but units having capital of Rs. 5 lakh or Rs. 10 lakh. Fifty-eight million such units are there in India. They do not get any loans. Naturally, a profit-making institution will not be willing to provide them loan. For this purpose, in the Common Minimum Programme, we talked about a national fund for the unorganised sector. Like NABARD for the agriculture sector, or SIDBI for the small industries, the idea was to create a development finance institution for the unorganised sector. Sir, in this Budget, the Finance Minister has accepted several new development finance agencies. But, he has not yet accepted the funding programme for the small and tiny units, that is, the national fund for the unorganised sector. I do not know what is the final decision. I would expect that the Cabinet should take it into account. For a very simple reason, if you do not create an institution, which is solely responsible for this purpose, if you give money to SIDBI or NABARD, for example, and tell them that they should also give money to micro units, small and large farmers, then, they would not do that. They would divert all the money. You have to create an institution focussed solely to this particular sector and then monitor them as to how they function, provide them money. I am saying this only for the simple reason that the time has now come to rethink our economic strategy. Inclusive growth has not been achieved. Economic growth is essential and I fully agree with Mr. Chidambaram when he says that the economic growth gives revenue and you can use that. Definitely, that money should be used. But, to use that, we have to have a policy of accountability, policy of design, policy of complete change of approach that this is our new philosophy of economic development. If we do that, then, definitely, inclusive growth will take place in our country.

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA (Nominated): Sir, hon. President, in her Address, has outlined her Government's achievements and priorities and the tremendous economic performance that the Government has achieved. Sir, the prime reason to consider India as the next big economy in the world is its demographic advantage. Labour contributes significantly to the GDP. According to the estimates, almost 63 per cent of the population in India is the working population. And, according to Indian Demographics 2025 Report, Sir, this figure is likely to increase to almost 67 per cent by the year 2025. If you look at the comparable figures of the countries like Japan, Europe and the U.S., all of them are seeing a declining demographic ratio. Moreover, the average age of Indian population by the year 2020 will also be 29 years thereby greatly benefiting the Indian economy. Sir, these favourable demographics will mean that an average Indian will earn more and spend more, provided there are enough jobs. This will result in a greater tax collection allowing the Government to invest much more on its ongoing infrastructure projects. However, to capitalise on this demographic advantage, a lot needs to be done in terms of investing in India's social infrastructure, namely, much more in education and healthcare. A significant part of the President's Address was devoted to talking about the social sector and putting it on the Government's priority list. Sir, the hon. President also highlighted the need for inclusive growth that would connect the nation's GDP to the growing needs of its people

It is in this context of a growing economy, which includes all Indians, that three policy projects of the Government deserve special mention and are extremely noteworthy in the areas of employment, education and rural infrastructure, namely, the National Rural Employment Guarantee Scheme, the Sarva Shiksha Abhiyan and the Bharat Nirman programme. While much has already been said and made of these important and forward-looking programmes, I think, the time has come to look at the proverbial report card to see what the intention was and what they have achieved. Though the schemes are very noteworthy, Sir, I am afraid, there have been several lacunae, and, if these need gaps are not addressed immediately, the growth of rest of India will lag behind.

Sir, because of paucity of time, I will concentrate only on education as, I believe, education is not only necessary but it is imperative to improve the productivity and drive the innovation that is required to accelerate the growth story. According to a UNESCO report, 33 per cent of the world's illiterate population reside in India and yet, Sir, we call ourselves the 'knowledge economy'. How long can we carry on with this trend unless we have a complete relook at this very important sector, which will help us grow into 'India of tomorrow'?

Sir, to my mind, the sector needs to be revamped, giving it a more creative look, making it much more job-oriented so that it can contribute productively to the growth story of our nation.

We need to develop both in terms of quality and in terms of quantity and look at all the three sectors, namely, the primary, secondary and the tertiary sectors, and, see what are the issues that actually haunt the Indian education system, whether it is lack of seats, whether it is outdated curriculum or whether it is the calibre of the teaching staff itself.

Sir, the Government has been more than generous in its grant in terms of its outlay for education, which has increased four-folds in the last four years and several schemes like the Sarva Shiksha Abhiyan and the Mid-day Meal Scheme too have made their impact. Yet, Sir, whilst the enrolment is hundred percent, the quality of output of this sector leaves a lot to be desired.

According to UNESCO, the pupil-teacher ratio is 40:1 in India and 21:1 in China. With such few teachers available, how do we expect to have quality talent that we need to produce for this country?

The trend that has been observed also is of very high absenteeism, both of teachers and students. There was an independent survey done for the World Bank over two hundred primary schools and they found only 50 per cent were actually indulging in any teaching activity, and, only 61 per cent of those who actually went to primary schools were able to go up to the Vth standard. Sir, these figures do not augur well and they need urgent attention. Out of the teachers who come, only one or two out of every four actually teach, and, the others are used to do other government jobs. And, almost thirty five per cent of those who have gone though the primary schools cannot even read a simple paragraph or perform a small mathematical solution.

Sir, there is also a lack of basic resources whether it is *pucca* buildings, whether it is sanitation, hygiene or drinking water. According to the Planning Commission, over seventy per cent of the schools do not even have the electricity and there are inadequate toilets for women, so, the girl students drop out at a later stage, upon which the gender ratio gets extremely tilted.

Teachers' subject knowledge is crucial and has proved to be a good predicator of students' achievements. The quality of Indian teachers at the primary level needs to be upgraded. Only forty per cent of them are actually graduates and over thirty five per cent have not done higher secondary. With this sort of inputs, Sir, how do you expect to churn out students that will meet the challenges and take us to the next quantum leap that we need to make? This obviously necessitates developing very strong teacher-training modules that will train the teachers, give them the support so that they can build the confidence of the people and perform a better job. The poor quality has resulted in high level of drop-outs and even those who drop out at the primary level, unfortunately, do not have the basic skills to find any employment or to contribute significantly to our GDP and this need not be the case at all. The drop-outs with a good and sound primary education can contribute and should contribute to the agricultural sector.

Sir, with over 60 per cent of our population aligned with agriculture, most primary school drop-outs form a substantial portion of this population of 60 per cent. They can contribute productively to the GDP if imparted with the right kind of training customised according to their needs. So, in addition to the basic education, if we can consider imparting knowledge about technological advancements in agriculture, about Government incentives for agriculture and the basics of supply chain, that will enable them to get a better price for their produce. They could also be diverted to other agro-allied industries, whether it is sericulture, fisheries, handicrafts, etc. All these come high on the value chain.

Then, Sir, going on the secondary sector, a very low level of enrolment creates a bottleneck because there are very few who actually pass out and go to the tertiary sector. Once again, here, the concern is not so much of quantity alone, but also of quality because this sector is marked completely by rote learning and the need to pass exams without unleashing creativity or the ability for people to be enterprising. The curriculum is quite outdated and an outdated form of grammar is taught, making students not at all proficient in English and their communication skills are greatly hampered. Sir, stidents who drop out of this sector can be gainfully employed also in the manufacturing sector, but, once again, they need to be provided with proper industry-oriented training. They need to be able to develop their

skills for which we need to have many more institutions like ITI or ITIs. Sir, the ITIs too really needs to be looked at again. Have we kept pace with the changes that are happening in our country? Are we looking at the new emerging India? Are we looking at the trends in industries and seeing where the jobs are? Sir, just to give an example that mobile telephony has taken off in a big way, but, our ITIs still don't offer you courses in terms of either servicing the network or repairing mobile phones. There are endless number of opportunities. On the one hand, people find it difficult to get human resource and, on the other hand, we say that there is joblessness, there is unemployment. I think, we need to marry the opportunities that are there. We need to map what new India offers. And we need to dovetail that with the kind of courses that are offered by the ITIs or such other institutes. The corporate sector too will come forward, but, provided that they are given some kind of benefit in the form of tax exemption or if they are given greater autonomy both in terms of setting the curriculum and greater autonomy to run these institutes.

Sir, I want to cite very quickly just a few world examples because many countries have done this. I am not saying that they have sacrificed formal education, but, they have moved away and tried to bring in vocational education which is an important and integral part if one has to create jobs. I will go to South Korea which decided in 1987 that they would impart a new focus in their educational system, making it much more vocational training based. So, they got together with all the stakeholders, whether they were industry leaders, students, pupils and parents and tried to devise courses which met the needs of the industry and set up schools which were specialised in agriculture, fishery, commerce, merchant marine, arts and there was a strong linkage between the schools and the industry. South Korea doubled its GDP decade after decade. Then, Sir, about Germany where universities are quite empty because what happens there is that after tenth grade, people go in and opt for part-time jobs. They get the minimum wages and they work as apprentices. Simultaneously, they go to a vocational training institute for learning the theory and acquiring the relevant knowledge. So, the German model of training the trainer after working in any industry for three to four years, workers go back to the institute for a certification course on training new people. This way, they link the industry's needs with skill developments of students. Sir, in Germany, South Korea, Canada and many other countries, 85 to 90 per cent of post-tenth standard students go through vocational training. The number in India is only two per cent. India has 8,000 public and private vocational training institutes. China has 800,000. That is the yawning gap. Sir, in the tertiary sector again, while statistics may make us feel happy because between India and China, we are adding close to 0.7 million in India, and 0.53 engineering students serve China, but the truth is that, again, there is a mismatch in the quality of graduates, and the need of the industry. Only one out of every four graduates that comes out, is able to get absorbed. Some of them are able to undergo training, and I know some IT concerns that spend almost 5,000 to 10,000 dollars per graduate, imparting them the necessary skills to make them employable. But half of them are jobless, half of them are looking for some opportunity, and therefore, a lot of frustration sets in.

Sir, there are several causes. One big cause is also the quality of teachers and the huge crunch of teachers in the higher education sector. The private pay scales have moved up rapidly, and on an average, a teacher would get one-sixth of what somebody, who is as qualified, with the same experience, would get in the private sector. So, very few people now want to turn to the teaching profession. This is actually having its toll in the tertiary education sector where you do not see quality teachers. The Government has gone in for some partnerships with the industry. I know that they have entered into some with CII and

other bodies, where they do give a one-time grant of interest-free loan, and the industry sets up training institutes. This benefits the industry as well because there is a dearth of manpower. So, it is a win-win situation. But much more needs to be done because there are just a few initiatives that have started. But they are just a drop in the ocean. The timings of such institutes, again, needs to be a lot more flexible. Most of them at the moment are following a timing of 10 to 5 which is a typical working hour. If we want to follow the Western example where we encourage people to take up part time jobs, and simultaneously, go in for training, we need to have flexible timings, we need to ensure that these institutes are opened even post 5 in the evening. We have an eligibility criteria which is there only in India that you need to be 10 plus before you can enrol in any such institute. Nowhere in the world do you have such criteria. People are encouraged at every stage. If they are drop out at any stage of their education, they can still go in for vocational training, they can still hone their skills and find some gainful employment. We have a regulation where you need to have passed class 10 before you can enrol. I think, this needs to be re-looked at.

Finally, Sir, I believe that those who drop out at the primary stage, should be encouraged into the agricultural sector; those who drop out at the secondary stage, should be imparted with training so that they can be absorbed by the manufacturing sector; and eventually, the education system has to be revamped to support a GDP growth, and to do that, I would like to quote Sam Pitroda, who said, "A knowledge economy needs minds, and we have to create those minds." To do that, we need to be creative and do something that will be a game changer. Thank you.

SHRI RAM JETHMALANI (Nominated): Thank you, Mr. Chairperson. After a wait of nearly 2 days, it is not very exciting to speak to the House with such truncated numbers. But, Sir, I must confess that I have decided that I must participate in this debate only because something which I had been expecting for years, did happen during the last few days. It was a heart-warming thing that happened. I was so happy that though I have been sick for nearly 6 weeks, I immediately got out of the bed and almost danced with joy. I said, this I must share with the House. But when I came here, waiting here, I saw my young friend Shahid speaking about the same thing, and he has almost stolen my thunder. But he certainly doubled my joy because I found that there was one more person who had noticed this grave omission in the President's Address. Sir, I have been, for almost four terms, a Member of this House, but I must confess that I have never introduced myself to my colleagues in this House. I am a respectful student of all religions, but I claim that I am not a blind follower of anyone. Having been a student of Islam, in particular, because I have lived and grown with Muslims in my place of birth, i.e. Sind, I have always argued that pure Islam, the real Islam, of the Prophet is the religion of peace and it condones the use of force and allows only in desperate self-defence, and that too in support of righteousness. It is unfortunate that after the death of the Prophet, there were three or four successive, very unfortunate, assassinations of important leaders of Islam, which have coloured the subsequent history of Islam. But, Sir, the message of the Prophet to his followers was the message which he got from the Archangel Gabriel who saw in his dream: "Read, read, read." Even when the Prophet said, "I can't read", the Angel still said, "Read." The Prophet left only one great message for which I think no other Prophet of any religion can take credit, and in that sense, he was one of the greatest men that humanity has produced, that the ink of a scholar is more valuable than the blood of a martyr. Sir, whenever I discussed with my Muslim friends, in private, everybody has agreed with me about my perception of Islam, but I was always asking them: When will Muslims raise their collective voice and proclaim

this truth to the rest of the world? And, Sir, when I say that I danced with joy, that day was when I read that announcement by Darul Uloom. Sir, it is so heartwarming that 4,000 ulemmas from all over the country and, perhaps, some from outside, met in a conference, which they called 'Anti-terrorist Conference, and issued that fatwa against the scourge of terrorism: "We reject terrorism in all its forms and manifestations. Terrorism negates all the teachings of Islam." Sir, I am more than corroborated in my views that terrorism was not resorted to by practitioners of Islam, but by renegades of Islam. It was a black spot on the pure, white attire of Islam. But, Sir, now I plead that two steps are ought to be taken, almost by a retrospective amendment which I do not formally move, of the President's Address. This great fatwa should be acknowledged as a part of the President's Address. One is that an apology must follow from all those who have tried to paint Muslims as 'terrorists'. And the second which is still more important is the noble message of this seminary. And, Sir, it is not a simple ordinary seminary, but it is the most prestigious seminary of the Muslims in the whole of Asia. This message must now circulate to all schools, colleges, centres of knowledge, holy places of religions, temples, mosques, gurudwaras and churches. Sir, I hope the Minister of Human Resource Development will make it a part of the curriculum which should be taught in every school so that the young should know what the true Islam stands for and that nobody should be misguided by the teachers who are determined to spoil our youth.

Sir, I must compliment the Government on its economic successes; I must compliment the Government for the various schemes which President's Address talked about. Here again I am saying something, not to run down or dilute your successes but to point out where you are going wrong. Despite the economic successes which this country has doubtless registered, the poor in this country have grown in numbers. The domain of poverty has become wider in area. The rich has become richer and the upper middle class has, perhaps, graduated into the rich class, but poverty remains the ugly face of the major part of this country.

Sir, I have been in politics since the emergency and I had tremendous differences with that young man who became very prominent during those times. But that young man had one instinctive realisation that this country can never become economically prosperous unless you resort to a vigorous control of population. Why is it that no Congress politician or not even any Opposition politician today talks of the control of numbers in this country? It is a phenomenon which I really don't understand. This so-called economic growth will never be a real inclusive growth unless you have managed to control numbers and reminded our law-makers, our budget-makers and the framers of our economic policy that the Malthusian nightmare can never be ignored. If you ignore it, you will have this lopsided development in this country; never will you be able to remove the scourge of poverty. Sir, I hope somebody will listen to what has been said about control of numbers. Today, there are my friends here on my right, who are supposed to be in the left of India. They all the time talk about the achievements of China. One of the achievements of China which I want you to emulate is their vigorous control of population growth. We don't copy the good things. We copy only bad things because even those who are admirers of China do not wish to tell us the whole truth about China: Why is it that China progressing and we are not that well off?

Sir, there is a reference in the President's Address to our achievements in the filed of foreign policy. I am very happy that you have talked about friendship with our neighbours. I am very happy that you have talked of friendship and desire to assist Afghanistan, the

desire to assist the West-Asian countries, the desire to help everybody. This is the Gandhian principle. The real creator and formulator of our foreign policy was Gandhiji and not the Congress Party or even the great Pandit Nehru. It is Gandhiji who had proclaimed to the world that after we become independent, we shall be the conscience of the world. In other words, we shall wish the well-being and the progress of everybody. We shall not be enemies of anyone. But we shall tell the stark truth to friend, foe and neutral alike. It is this great Gandhian truth that we have departed from in the pursuit of our foreign policy and that has cost us dear. I do not have much time. That is why, let me only point to a feature of our Constitution which does not exist in any other constitution of the world, that is, article 51 of our Constitution which the Constitution makers actually bequeath to us as a lesson in the conduct of foreign policy. All the four clauses of article 51 of our Directive Principles were Gandhian principles; respect for international law and human rights, respect for treaty obligations, honourable relations, peace and tranquillity throughout the world. Sir, when these three clauses were put in a draft form, there were two Gandhians from Maharashtra who were still sitting in the Constituent Assembly. They got up and said, "Sir, these three clauses of article 51 are all right, but international disputes are bound to arise. How do you propose to solve them?" Then under the influence of these two Gandhians — I am proud to say that both of them were from Maharashtra — Dr. Ambedkar accepted the fourth clause in article 51 that India shall strive to settle all international disputes by arbitration. We have forgotten Gandhiji in our international disputes. We never offered it to China when the Chinese dispute was simmering away. We have never offered it to Pakistan, though Gandhiji had offered it to Pakistan when he was alive. But, Sir, I have no quarrel with our foreign policy in making friends with China. China represents one of the greatest civilisations of the world, like the Indian civilisation. In some ways, it is perhaps superior to ours. But it is certainly indebted to our Indian civilisation and we are natural friends, natural brothers, if you like. But let us not forget, however much some people will want us to forget, that you have on the records of this Parliament a Resolution passed in 1962. I remember every word of it by heart, but I do not wish to repeat it. It says that India has been the victim of a wanton aggression which has been the ungrateful return of friendship and our solicitude for the good of that country. Even more, it contains a Declaration that they are in possession of 93,000 square kilometres of our territory and no Indian citizen shall rest until the last square inch is taken back. Sir, I am one of those in fairness to the Chinese that in our case against the Chinese on the border issue, there are some weaknesses and some holes. But, then, let us freely acknowledge them. Let us tell the Chinese that we agree that this is wrong, but you also agree that you indulge in aggression. Sir, a border dispute is a justiciable dispute. We divided Punjab; we divided Bengal and we divided Assam. Who settled our boundaries? One judge from India, one judge from Pakistan and Sir Redcliff presiding as the third umpire judge. Boundaries of these two great provinces and the third smaller one were settled. Nobody has ever quarrelled. This is primarily a justiciable issue. Why have we not, during the last confabulations, starting from 1963 onwards, told the Chinese that let us sit across the table; let us appoint a bunch of arbitrators and let us go to the existing International Court of Justice or the International Court of Arbitration and let they come and decide the boundary? You will not do the obvious because you don't read article 51. You have forgotten Gandhiji. As a citizen of India, as a proud citizen of India, I feel dishonoured, feel humiliated, that Prime Minister after Prime Minister visits China, but achieves nothing. My great friend, Shri Narasimha Rao, — may his soul rest in peace — went there, and brought back to us what! He came and told the Indian people, "I have brought to you now a Treaty of peace and tranquillity. This is my great achievement." But I wrote even in those days

that even a ferocious tiger, when he swallows up an innocent tourist going by his side, retires back to the jungle for some time, to digest the beautiful meal that he has imbibed. Those who are in occupation of 93,000 square miles of our territory will want that the *status quo* should continue. They don't want any disturbance from the victims of aggression. So, this Treaty, that you have brought, is an abject surrender and humiliation for India. Every step that you have taken from 1962 onwards is negation of the Resolutions of Parliament, and it is a surrender of our sovereignty, about which my Leftist friends, all the time, say that you are surrendering your sovereignty by not making bombs. Now, you should exercise your sovereignty not by making bombs. Gandhiji's India will not plan the extinction of the human race by making bombs. But surely, Gandhiji's India and its citizens are entitled to self-respect that every time you go there and say, "Oh! We have appointed now a committee", what are they doing! They are still examining the principles on which these power disputes can be settled. For 40 or 50 years, you have not been able to settle even the principles. But this is all a deception of India and the Indian citizen, and this must stop. Tell the Chinese, "You have weakness in your case and we have weakness in our case. Let us sit as friends and become friends. Let some arbitrator decide that issue if we can't decide it." Sir, I want India to beat the Chinese in the peaceful pursuit of economic development. This cannot be done unless India is self-sufficient in electricity and energy. Yesterday, Question No.62, put by a hon. Member, was answered by the hon. Minister of Power. Sir, it reveals some startling facts. You will recall that in 1962, we passed the Atomic Energy Act. Nothing happened. We were trying to preserve our fissile material. Whoever discovered thorium or uranium somewhere was to report it to Parliament. It was in 1987 that we amended the Act for the first time. And, you will be surprised that in 1987, India set itself a target of 2,000 MW of energy by the year 2000. In other words, 13 years after the original Act, the target was 2,000 MW. And, yesterday's answer by the Minister of Power is that India is so short of energy, so woefully short of energy that we need to anyhow produce 78,000 MW by the year 2011-12 within the next three years. Within the next years, if you have to produce 78,000 MW, please understand the colossal task on hand. This answer further tells us the depressing fact that, to make up for these arrears of energy, the shortages of energy, which is holding up our economic development and progress, you have taken nine steps, and I want to tell the House that amongst the nine are two steps which the Minister has conceded. First, we are buying power from Bhutan. Aren't we ashamed? You do not want to do the right thing in this country, but you must go to a small country like Bhutan and buy power from them!

Second, we are now importing coal. We have started importing coal but we would not import nuclear know-how and nuclear stuff and nuclear material for the purpose of producing those 78,000 MW. Sir, I am on record in this House, and I wish to repeat it, that this achievement of the Prime Minister of India, my dear, dear, respected friend, Dr. Manmohan Singh, is the greatest achievement of the Congress Party during the last sixty years. He may have now changed his mind after succumbing to his so-called allies. But I remain of the same opinion; I said that a grateful posterity will build a monument in the memory of my Prime Minister if he succeeds in building this deal. (*Interruptions*) But, Sir, it is your allies who have prevented you from bringing you that honour. Please decide who your allies are and what you propose to do. I must also tell the House, Sir — my very dear friend, Brinda is not here — that comrade Karat is the chief election agent of the BJP. Nobody has done more to weaken your Government than he has. Sir, he has convinced this whole country that this Government, to remain in power for a year more, needs his party's support. You

must meet the people of this country in a democratic fight. Go to the people's court and fight out this battle. You have made an achievement; tell the people what achievement you have made. Let the people of India decide whether it was an achievement, or, as those who claim that it is not an achievement, a surrender of sovereignty. Let them decide. If the people decide against you, you would have, at least, done what Gandhiji wanted; you will remain the conscience of India, you will remain the conscience of dear friends of yours who appreciate your character and integrity.

Sir, a few years ago when I was still the Minister and sister Mayawati was one of the leaders present in the Lok Sabha, I was saying something on behalf of the Government and she immediately accused me of being a *manuwadi*. I turned to her and said, 'Sister, I am not a *manuwadi*; I am an *Ambedkarwadi*'. Later on, she saw me in action and the whole country knows that there is no *dalit* fight, which I have not taken as my own fight, not as a paid lawyer, but as a social worker with convictions, with convictions in the rightness of their cause. My friend is not here now; he has left. He is talking about the rights of those *dalits* who, out of a feeling of desperation in the society in which they were condemned to humiliation and backwardness, went and followed other religions. They have been deprived under some judgement of the Supreme Court, a misguided judgement, of the benefits of being *dalits*. Those issues are now before the Supreme Court of India. And, only this morning, a point of order was raised by one of my friends in the Congress Party that matters which are under consideration of the courts shall not be commented upon here. Therefore, I am not commenting upon them. But, I wish to say this and declare it that those who in desperation have become Muslims, who have become Christians, will and must get the rights of Dalits because even in the new society which they have entered, Dalit humiliation has not gone; that continues; that clings to them, and it is the duty of the society to put an end to this state of humiliation. I pray that my last breath of life will be left to the fighting of that cause, and I shall see to it before I die that this comes through. What did Dr. Ambedkar do? Dr. Ambedkar, at the end of his life, advised people to take to Buddhism. Then, you amended the 1954 Scheduled Castes Order exempting those who have been converted to Buddhism. Then, you have included Sikhism. How can you go on making these religious distinctions and leaving out Christians and Muslims? The Christians and Muslims must get into the beneficiary circle of these Dalit rights.

Sir, in the morning, I heard a very interesting speech from my friend, Arun Jaitley. He talked of meritocracy in democracy. Sir, speaking for myself, I have never been impressed by this merit argument. What is this merit argument that you are talking about between the high castes and the Scheduled Castes? The merit argument is that you received a few marks more in an examination, and the examination which does not test you for character, does not test you for integrity, does not test you for commitment to the common will, does not even test you for your attachment to the advancement of the country's national integration. A few marks more and you say, "I am now more meritorious, and why are you getting the less meritorious ones?" But, Sir, humility requires, understanding requires that even your ability to get a few more marks in an examination is a pure genetic accident. It is because of your parents whom you did not select, but somebody else selected them for you. It is a pure, pure genetic accident that has taken place. You have a little more intelligence. You may be very intelligent, but you may still be a crook and you may do no service to your fellow beings. So, Sir, this merit argument, which Mr. Arun Jaitley pronounced this morning with great, great aplomb, I don't accept. The Dalits, some of them may get a few marks less, but they are entitled to the concessions and to the...(*Interruptions*)... Not necessarily, Sir, after all, who

was Dr. Ambedkar? He was one of the greatest constitutional lawyers of the country. He was the best that our country produced. Of course, Sir, what the Congressmen did to Dr. Ambedkar after he had served their purpose is another historic and a somewhat very horrid fact of history. They got him defeated in an election by almost a non-entity, and poor Dr. Ambedkar, ultimately, I believe, died almost a broken hearted man.

But, Sir, as I said, I look at problems not from the point of view of any religion. Therefore, I don't look at international problems of India. Sir, I will take only one minute more and I finish. There are so many things which I have to say, but I have said the most important things. Sir, my friend, Mr. Shahid, who, Sir, if you meet him in private, he is a model of secularism, I must tell you, but even he talks that you are now under the influence of the Jews and you are forgetting the interests of the Palestinians. Sir, I know that the Palestinians must have a State of their own. They must. Even the Israelis don't deny. But what they want is secure borders. And, Sir, the enemy of the Palestinians are not the Jews of Israel but the surrounding Arab States who keep them in refugee camps to be able to make a point. For the last 40 years, they are flushed with oil wealth. They cannot take care of a few couples of millions of Palestinians living in the refugee camps and putting them in decent houses and places to live in. Their enemies are their own Arabs who first incited them to fight a war.

Sir, I have been involved in the Arab-Palestinian conflict. I know, Palestinians are my friends, so are my Israeli friends. The problem is near a solution. There is one small little thing which is bothering them. The Palestinians say that those who in response to the call of jehad, living in the territory which became Israel, fought a jehad and joined the forces which attacked Israel from outside should now be allowed to go back to their original places. Sir, I have spoken to the Israelis. I told them, "I can understand that you will not take those people who fought a war against you, tried to destroy you. Will you at least take those who today take up the Holy Quran and say that they would live there as honest citizens of Israel"?

Sir, this gives you a key to the solution. Those who honestly declare, "We want to go back to the land in Israel which was once ours, but we shall live there as honest, faithful citizens of Israel" will be accommodated in Israel. I can assure you about this, but that requires goodwill and said the great Emanuel Corn, "Nothing in this world is unconditionally good except goodwill. Create goodwill for God's sake."

Sir, that is what I told President Musharraf when I met him in Pakistan. I told him, "Mr. President, do not make the solution of the Kashmir problem dependent as a condition precedent to the growth of friendship and goodwill between the two countries. First create goodwill between the two countries; that will solve the problem." I hope, Sir, I am not letting out anybody's secret. I am in touch with the people across the border. I have a tremendous number of friends there. Through our common friends, no less a person than President Musharraf himself, conveyed proposals in writing which I saw were so eminently reasonable that I asked for permission if I can modify these and adopt them as my own proposals to put to my own countrymen. Sir, those conditions of settlement were publicised in an article which I wrote. Nobody from Pakistan opposed it. That was the time when the Kashmir problem could have been solved so easily. We missed the opportunity. That is my tremendous regret.

You talk in the President's Speech about some conferences which you have held. You say, 'series of conferences'. First of all, there was no series of conferences. There had been two useless conferences. They were never designed to achieve any results. We have

missed the bus. But I hope and pray that my Prime Minister, with his far sight, with his compassion and with his desire to settle things, will resume the dialogue as early as possible, enlist the help of those who want permanent peace between India and Pakistan and resolve this problem before, Sir, you quit office or quit this world. Thank you.

FALICITATIONS TO THE INDIAN CRICKET WORLD TEAM

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : महोदय, देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमने न केवल ट्राई-सीरिज फाइनल आज आस्ट्रेलिया की धरती पर जीती है, बल्कि भारत अंडर-नाइंटीन मैच में भी विश्व कप जीता है। तो इन दोनों के लिए मैं सदन में प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि हम भारतीय टीम चाहे अंडर नाइंटीन जूनियर टीम हो, चाहे सीनियर टीम हो, क्योंकि उसने विश्व चैम्पियन आस्ट्रेलिया को हराया है, तो दोनों को यह सदन बधाई दे। आदरणीय प्रधान मंत्री जी, यहां मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि वे एक मिनट में कोई संदेश इस मामले में दे सकें और टीम को बधाई दे सकें तो सदन के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत है।

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am sure, all Members of this august House will join me in sending our warmest congratulations to all those cricket players who have done our country immensely proud. What they have achieved is an indication of the great potential in the world of sports that exists in our country. Given good leadership, good management, this country can excel in other sports as well.

SHRI RAM JETHMALANI (Nominated): Sir, the President's Address should contain a reference to our sportsmen.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—(Contd.)

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा) : बहुत-बहुत शुक्रिया उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का टाइम दिया है। अभी प्रधान मंत्री जी ने हमारी क्रिकेट टीम के सदस्यों को आज की जीत पर बधाई दी है, हम सब उसमे शामिल हैं। लेकिन आज जिस विषय पर बहस हो रही है, वह है प्रेजिडेंट एड्रेस और मुझे यह कहना है कि प्रेजिडेंट एड्रेस में कामनवैल्थ गेम्स का जिक्र किया गया है। भारत सरकार कामनवैल्थ गेम्स को कामयाब करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। मैं भी खेलों के संघ से वाबस्ता हूं। यह सबको पता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृपा से कामनवैल्थ गेम्स इंडिया को अलाट हुआ।

(श्री उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

जब वह प्रधान मंत्री जी थे, तो उन्होंने एक ब्लैंक चैक की तरह इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन को सपोर्ट दी कि ये गेम्स इंडिया में आयें। आज स्थिति यह है कि इंडियन ओलम्पिक संघ एक तरफ है और भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक तरफ है। इनमें एक तरह से लड़ाई हो रही है और प्रधान मंत्री जी इसको चुपचाप देख रहे हैं और हालत यहां तक पहुंची है कि बैडमिंटन चैम्पियनशिप इंडिया में होनी थी, वह कैंसिल हुई, इसलिए कि उनको शटल कॉक नहीं मिले। शूटिंग चैम्पियनशिप में हमें वर्ल्ड मैडल आने की उम्मीद है, उनके पास एम्युनिशन नहीं हैं। मेरी ये सारी बातें रिकार्ड पर आ चुकी हैं। मैं हाउस में डिप्टी चेयरमैन साहब के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कामनवैल्थ गेम्स इंडिया की प्रेस्टीज़ है, किसी इगो प्राब्लम से, किसी इंडिव्युजल प्राब्लम से पूरी सपोर्ट गेम्स को नहीं देंगे और जितनी ओलम्पिक कमेटीज़ और फेडरेशन्स हैं, उन सब को हिदायत दी जाये, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकें।

दूसरी बात यह है, अभी श्री राम जेठमलानी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रेजिडेंट एड्रेस में यह बात कही गयी कि हम पड़ोसी देशों से भी बहुत अच्छी बात करें। सर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। प्रधान मंत्री